R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-25

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 13
01 से 15 अप्रैल 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

भारत में बदले की राजनीति...!

नेहरु, इंदिरा, राजीव, वाजपेयी और अब मोदी की सख्ती सवालों में

क्या अपने को मजबूत करने सरकारों ने विपक्ष पर डाला घेरा...?

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजतंत्र

9 | कांग्रेस का खेल खराब करेगी...

चुनावों से महीनों पूर्व प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली बसपा में इस समय सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस के प्रयासों के चलते इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बची-खुची संभावनाओं के बीच मायावती की ओर से उप्र...

राजपथ

10-11 | मुद्दों की अग्निपरीक्षा

मप्र में लोकसभा चुनाव चार चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को होंगे। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, अयोध्या में राम मंदिर और कांग्रेस की जाति जनगणना की...

विवाद

14 | मप्र में सबसे ज्यादा मंडी....

चुनावी मौसम आते ही जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं को व्यापारियों-किसानों का हित याद आने लगता है। इन दोनों वर्गों का बड़ा मुद्दा मंडी टैक्स में कमी करना है। हर चुनाव में चर्चा में रहने वाला ये मुद्दा अब तक हल नहीं हो सका है। मंडियों में...

खेती-किसानी

18 | हर साल बर्बाद हो रहा...

फास्फोरस के अधिक कुशल उपयोग से इस महत्वपूर्ण उर्वरक का सीमित भंडार 500 से अधिक वर्षों तक चल सकता है। बढ़ती आबादी की भोजन की मांग को पूरा करने के लिए दुनियाभर में फास्फोरस समेत कई उर्वरकों की मदद से फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वह पार्टी अपने आप में विश्व की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है। लेकिन सत्तारूढ़ दल को हमेशा विपक्ष का डर सताता रहता है। इसलिए सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्ष को दबाए रखने का हर प्रयास किया जाता रहा है। चाहे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर भारतीय इतिहास को देखें तो इंदिरा गांधी ने सबसे अधिक 51 बार राष्ट्रपति शासन लगवाया है।

राजनीति

30-31 | विपक्ष कर रहा आत्मघाती गोल

लोकसभा चुनाव में पहले दिन से भाजपा और मोदी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर प्रवेश के बाद से लोकसभा के चुनाव राष्ट्रपति प्रणाली की तरह हो गए हैं। मोदी एक लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। जब तक उनके सामने एक वैकल्पिक चेहरा नहीं...

महाराष्ट्र

35 | एनसीपी में बगावत से...

लोकतंत्र की पिच पर आम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अबकी बार 400 पार का नारा आम जनमानस के दिमाग में फिट करके मनोवैज्ञानिक बढ़त बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस में चुनाव लड़ने योग्य उम्मीदवारों का टोटा पड़ रहा है। इन सबके बीच 48...

बिहार

38 | बड़े भाई की भूमिका में...

बिहार में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ सोमवार को सीटों का बंटवारा कर लिया। सीटों के बंटवारे में नीतीश की पार्टी जदयू को एक सीट कम देकर भाजपा ने यह बता दिया कि बिहार में अब बड़े भाई की भूमिका भाजपा निभाएगी। ठीक पांच...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

यह कैसी गुंडागर्दी, सबकी अपनी मनमर्जी...

शा यर विनोद बक्सरी का एक शेर है...

पुलिस मिली अपराधी से, नेता की चलती मनमर्जी है,
आम जनता पिस रही चक्की में, झूठी सबकी हमदर्दी है।

उपरोक्त पंक्तियां माननीयों यानी नेताओं और उनके अपने लोगों की तानाशाही और गुंडागर्दी की तथाकथा कह रही हैं। वर्तमान समय में मप्र में दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसने पार्टी विथ डिफरेंस की बात करने वाली भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे पर दाग लगा दिया है। गौरतलब है कि मप्र में एक तरफ सरकार और सरकार के मुखिया सुशासन का दम भर रहे हैं, जनता को पीड़ा पहुंचाने वाले अफसरों को सबक सिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मप्र में कुछ माननीयों और उनके अपनों की गुंडागर्दी आमजनता पर कोप बनकर टूट रही है। हद तो यह है कि यह दोनों मामले प्रदेश के दो बड़े शहरों यानी राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में घटित हुए हैं। राजधानी भोपाल में प्रदेश के स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है। पुत्र के समर्थन में मंत्री ने भी जो कुछ किया है, वह निंदनीय है। मंत्री पटेल ने शाहपुरा थाना पहुंचकर पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर वर्दी तक उतरवाने की धमकी दी थी। मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण दबाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन एक अखबार ने बिना दबाव और भेदभाव के जिस तरह इस मामले को उजागर किया है, उससे पीड़ितों को बल मिला है। यही नहीं भाजपा हाईकमान ने मंत्री के व्यवहार सहित पूरे मामले की जानकारी तलब की थी। वहीं सत्ता और संगठन ने मंत्री को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर में मंत्री पिता का नाम जानबूझकर नहीं लिखा। उसे आरोपी के घर का पता तक नहीं मालूम है। आचार संहिता में अपराध धारा 353 और 188 का भी बनता है, जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं पुलिस ने स्वास्थ्य राज्यमंत्री को बचाने के चक्कर में अभिज्ञान पटेल के पिता का नाम ही एफआईआर से हटा दिया है। जबकि मुख्य आरोपी खुद थाने में मौजूद था। आरोपी की पहचान भी हो गई थी। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में वैध अनुमति के बिना पार्षद और अन्य समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करने और थाने में जाकर पुलिस के कार्य में बाधा डालने के आरोप में राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर आईपीसी की धारा 188 के तहत भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक राजधानी इंदौर में विधायक मधु वर्मा के समर्थक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। विधायक समर्थक पर आरोप है कि वह भोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित चाय की चौकी कैफे एंड रेस्त्रां में एक युवक किसी बात को लेकर मारपीट करने लगा। कैफे की एक महिला कर्मचारी से भी अभद्रता की। महिला ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बेखौफ आरोपी कपिल पुलिस वालों के सामने भी बैट से कर्मचारी पर हमला करने लगा। जब फरियादी थाने पर पहुंचे तो अफसर कहने लगे कि समझौता कर लो, विधायक के परिचितों से पंगा क्यों ले रहे हो। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव के समय एक-एक वोट के लिए जनता के दर पर पहुंचकर गिड़गिड़ाने वाले नेता जीत मिलते ही इतनी अकड़ कहां से लाते हैं। शायद ये नेता भूल जाते हैं कि 5 साल बाद एक बार फिर वे आम जनता के दरवाजे पर याचक बनकर खड़े होंगे, अगर उस समय जनता अपनी पर आ जाए तो इनका क्या होगा?

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 13, पृष्ठ-48, 1 से 15 अप्रैल, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

चुनाव बाद टैरिफ में बढ़ोत्तरी

मप्र विद्युत विनियामक आयोग ने 2024–25 के लिए बिजली का नया टैरिफ जारी कर दिया है। आम चुनाव को देखते हुए नए टैरिफ में इस बार घरेलू, गैर घरेलू, कृषि सहित किसी भी तरह के टैरिफ को नहीं बढ़ाया है। लेकिन चुनाव बाद बिजली के टैरिफ में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

● **अर्चना दुबे,** इंदौर (म.प्र.)

ध्यान दे सरकार

मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक कोर सेक्टर की ग्रोथ 7.7 प्रतिशत रही है। इसी तरह जीडीपी के चमकदार आंकड़ों के बीच खेती और खपत का हाल अब भी बेहाल है। ग्रामीण मांग बहुत कमजोर है, शहरों में भी कोई तेजी नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

● **जगदीश वर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

खतरनाक है यह राख

भारत में मिलने वाले कोयले में राख की मात्रा 30 से 40 प्रतिशत तक होती है। ताप बिजली घरों में कोयले के जलने से निकलने वाली राख में ब्लैक कार्बन, आर्सेनिक, पीएम 2.5, बोरान, क्रोमियम और सीसा होता है। यदि यह राख उड़ती है तो इसके कण पानी और दूसरी सतहों पर जम जाते हैं।

● **प्रिया सिंह,** रतलाम (म.प्र.)

राहुल गांधी की न्याय यात्रा

लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है। इसी तारतम्य में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा भी निकाली। मप्र में राहुल गांधी की यात्रा 5 दिनों में 9 जिले और 7 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी के अलग–अलग रंग नजर आए। वे सेना में भर्ती की चाहत रखने वाले युवाओं से मिले, तो किसानों के साथ खाट पंचायत की। भगवान महाकाल की शरण में गए तो यात्रा के रूट में हो रही एक शादी में शामिल हो गए। एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को अमरूद भेंट किए तो वे अमरूद के बगीचे में पहुंच गए। राहुल ने नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी को भी दोहराया। कांग्रेस की इस यात्रा का चुनाव में कितना असर होता है यह वक्त बताएगा।

● **सिद्धार्थ तिवारी,** ग्वालियर (म.प्र.)

मैदान में चुनावी पार्टियां

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी तक जितने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उससे साफ है कि पार्टी ने जहां पुराने पर भरोसा जताया है, वहीं नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने कई सीटों पर नए प्रत्याशियों को खड़ा किया है। कांग्रेस 2014 और 2019 का चुनाव बुरी तरह हार चुकी है और अब 2024 का चुनाव उसके लिए करो या मरो से कम नहीं है। ऐसे में भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया, जिसका पहिया चुनाव से पहले ही पंचर हो गया।

● **पूनम सिंह,** नई दिल्ली

महिलाओं पर भी ध्यान

पिछले कुछ साल से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला स्वसहायता समूहों को गेहूं उपार्जन का काम दिया जा रहा है। इस बार भी उन्हें यह काम दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने चार साल पहले निर्णय लिया था कि ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला समूहों को गेहूं और धान उपार्जन का काम दिया जाएगा। अब सरकार से उम्मीद बढ़ गई है।

● **राजेश पाठक,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

समरथ को नहीं दोष गुसाईं

तुलसीदास के कथन का भावार्थ है कि सारे सामाजिक नियम, परंपरा मानने की उम्मीद केवल कमजोर आदमी से ही की जाती है। ताकतवर किसी भी परंपरा को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र होता है, और उस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता है। समाज शक्तिशाली की हर बात में हां मिलाता है। पिछले दिनों जिस तरह राम राज्य, संस्कार और आदर्श की बातें हो रही थीं, उससे हम उम्मीदजदा थे कि राजनीति में सब राजा राम के राज्य जैसा आदर्शवादी होगा। लेकिन, अब लग रहा है कि रामचरितमानस की पूरी राम-कहानी से एक सूत्र वाक्य को उठाकर बाकी आदर्शों को वनवास भेज दिया गया है। रामचरितमानस से निकला वह सूत्र वाक्य है- समरथ को नहीं दोष गुसाईं। 2014 से लेकर 2019 तक राजनीति में परिवार को खलनायक की तरह पेश किया गया। परिवार को भ्रष्टाचार की जड़ बताया गया। सत्ता की कुर्सी पर बैठ रहे साधु-संतों को लेकर तर्क दिया गया कि जब परिवार ही नहीं तो भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे? 2014 के पहले विपक्ष के व्याकरण में परिवार के समानार्थी शब्द के रूप में भ्रष्टाचार स्थापित हो चुका था। उस वक्त पूरे देश के सामने एक ही अपराधी दिख रही थीं-सोनिया गांधी।

सही समय के इंतजार में वसुंधरा

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों खामोश हैं। उनकी चुप्पी से तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रहीं हैं। कुछ का कहना है कि वसुंधरा राजे सही मौके के इंतजार में हैं। इसलिए मौन धारण किए है। ऐसा कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जबकि मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान विधानसभा सदस्य होते हुए भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। राजे की परंपरागत सीट झालावाड़ से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा के नहीं बोलने को लेकर हमेशा की तरह इस बार भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राजनीति में कुछ भी स्थाई नहीं होता है। किसी ने नहीं सोचा कि पहली बार ही विधायक बनने वाले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब चुरू से भाजपा सांसद राहुल कस्वां ने पार्टी छोड़ दी है। राहुल कस्वां राजे कैंप के माने जाते थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने चुप्पी साधे रखी है। चर्चा गर्म है कि वसुंधरा सही मौके के इंतजार में हैं। जिस दिन राजे की चुप्पी टूटी राजस्थान की राजनीति में खेला हो सकता है। हालांकि राजे ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि राजस्थान में बगावत हो सकती है।

बदला फारूक अब्दुल्ला का सुर

बीते दिनों जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से ही घाटी में विपक्षी दलों के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। जहां सुबह से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं अब पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग भी प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम की सरहाना करते दिखाई दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फारूक अब्दुल्ला को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि क्या भाजपा के प्रति अब्दुल्ला परिवार के सुर बदलने लगे हैं? असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय को मुबारकबाद पेश करता हूं। वहीं उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि वे नरेंद्र मोदी पर निजी हमला न करें। गौरतलब है कि फारूक और उमर अब्दुल्ला ने ही गुपकर एलायंस की पहल की थी और भाजपा विरोधी पार्टियों को एक मंच पर इकट्ठा किया था। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे दूर हो गई है। उसने विपक्षी गठबंधन को एक तरह से तोड़ दिया है।

बागियों में बहार है, न न न

देश में अभी पहली और सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की लड़ाई ऐसी सत्ता से है जो अपनी राजनीतिक सतर्कता से एक क्षण भी इधर-उधर नहीं होती है। चुनावी सीटों के अखिल भारतीय नक्शे पर भाजपा की रणनीति हर उस सीट के वोट जिताऊ कांग्रेसी या विपक्षी नेता को अपने पाले में कर लेना है जो किसी सीट को विपक्ष की सीट में तब्दील करने की काबिलियत रखते हैं। महाराष्ट्र, मप्र और बिहार के बाद राज्यसभा चुनाव के जरिए जिस तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता पर संकट आया उसका सकारात्मक पहलू है, पार्टी का उसका सामना करना। राजस्थान के बाद हिमाचल में भी कांग्रेस ने मान-मनौव्वल की जगह अनुशासन और कार्रवाई की भाषा का प्रयोग किया। पार्टी में संकट का सामना करने की ताकत दिखी। आजादी के बाद से सत्तर सालों तक शासन के कारण कांग्रेस में शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक परिवारवादियों का जमघट लग गया।

मर्यादा पड़ गई भारी

भाजपा द्वारा जारी की गई 407 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची में कई फायरब्रांड नेताओं के नाम नहीं हैं। दरअसल, इन पर मर्यादा भारी पड़ गई है। अक्सर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपने उग्र भाषणों के लिए जाने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री व छह बार से सांसद अनंतकुमार हेगड़े कर्नाटक में हिंदुत्व के शुरुआती पोस्टर बॉय में से एक थे। लेकिन राजनीति करने का उनका तरीका, जिससे उनकी बदनामी भी हुई और पहचान भी मिली और यहां तक कि जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जगह भी दिलाई, वही उनके पतन का कारण भी बनी। इस बार उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट के लिए विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। इस सूची में या इससे पहले जारी की गई अन्य सूची में मप्र देश से प्रज्ञा ठाकुर, दिल्ली से परवेश साहिब सिंह और रमेश बिधूड़ी, कर्नाटक से प्रताप सिम्हा और नलिन कुमार कतील शामिल हैं, जिन्होंने ध्रुवीकरण से संबंधित नैरेटिव को जोर-शोर से हवा दी या विवादों को जन्म दिया।

सहयोगी चला रहा जिला

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों 2014 बैच के एक आईएएस अधिकारी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल, साहब लक्ष्मी जी के बड़े पुजारी हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि जो साहब पर लक्ष्मीजी की कृपा बरसाता है वह साहब का चहेता बन जाता है। लेकिन साहब की चर्चा इसलिए हो रही है कि साहब अपने आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उनके दामन पर दाग लग सके। साहब ने काजल को कोठरी में रहते हुए कालिख से बचने के लिए एक सहयोगी रख रखा है। सूत्रों का कहना है कि जब साहब का तबादला ग्वालियर-चंबल अंचल के जिले में हुआ तो वहां की स्थिति-परिस्थिति को देखते हुए साहब अपने साथ राजधानी भोपाल से एक व्यक्ति को साथ ले गए। वह व्यक्ति चतुर-चालाक है और साथ ही जुगाड़ बैठाने में माहिर है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि साहब तो केवल नाम के कलेक्टर हैं। यानी साहब केवल बैठकें, समीक्षा आदि में व्यस्त रहते हैं, बाकी पूरा कलेक्टोरेट साहब का सहयोगी ही चला रहा है। जिले में कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं यह वही व्यक्ति तय करता है। सूत्रों का दावा है कि साहब ने उसे फ्रीहैंड कर रखा है, इस बात को जिले के सभी अफसर भलिभांति जानते हैं। इसलिए जिले के अफसर भी साहब के सहयोगी से ही काम के लिए मिलते हैं। इससे साहब को जहां मत्थापच्ची से राहत मिली हुई है, वहीं साहब पर लक्ष्मीजी की कृपा भी बरस रही है।

कमाऊ विभाग गुप्ता जी के भरोसे

प्रदेश के सबसे कमाऊ विभाग में इन दिनों एक गुप्ता जी की तूती बोल रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि यह कमाऊ विभाग पूरी तरह गुप्ता जी के भरोसे है। यहां हम यह बता दें कि यह गुप्ता जी परिवहन आयुक्त वाले गुप्ता जी नहीं हैं। बल्कि यह गुप्ता जी एक ठेकेदारनुमा व्यक्ति हैं। इनके बारे के कहा जाता है कि इनके पास अफसरों और नेताओं की सुख-सुविधा और मनोरंजन का पूरा इंतजाम रहता है। इसलिए ये कईयों के मुंहलग्गू बन गए हैं। अगर यह कहा जाए कि अपने इसी गुण के कारण इन दिनों इन्होंने परिवहन विभाग का पूरा धंधा-पानी संभाल लिया है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि विभाग में कुछ हद तक स्थिति ऐसी हो गई है कि इन गुप्ता जी के बिना कोई काम ही नहीं होता है। आलम यह है कि विभाग में बड़े से बड़ा काम इन गुप्ता जी के एक इशारे पर हो जाता है। सूत्र बताते है कि गुप्ता जी भले ही किसी से मोटी फीस लेकर काम कराते हैं, लेकिन काम की 100 फीसदी गारंटी रहती है। इसलिए गुप्ता जी अन्य दलालों के चहेते भी बन गए हैं। वैसे गुप्ता जी की करतूतों की जानकारी ऊपर तक पहुंच गई है। अब देखना यह है कि उनका रसूख इसी तरह कायम रहता है या फिर उन पर गाज गिरती है।

सब नारायण की कृपा है...

सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि जिस पर नारायण की कृपा रहती है उसका भाग्य कभी भी बदल सकता है। प्रदेश के एक बड़े विभाग में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। विवादों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले एक बड़े इंजीनियर साहब पर भी एक नारायण की कृपा ऐसी बरसी है कि उनके रिटारयमेंट के बाद उन्हें घर से बुलाकर विभाग का ईएनसी बनाया गया है। यह नारायण कौन है यह पूरा सरकारी महकमा भलिभांति जानता है। हालांकि बड़े इंजीनियर साहब पहले भी विभाग के ईएनसी रह चुके हैं, लेकिन एक समीक्षा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के सामने उनकी लापरवाही आई थी तो उन्होंने तत्काल उन्हें ईएनसी के पद से चलता कर दिया था। उसके बाद साहब से जूनियर को ईएनसी बना दिया गया था। दरअसल, बड़े इंजीनियर साहब का पूरा कार्यकाल विवादों में रहा है। वे अपनी नौकरी के दौरान जहां भी पदस्थ रहे वहां किसी न किसी विवाद में फंसते रहे। विवादों के कारण ही बड़े इंजीनियर साहब हमेशा सभी के निशाने पर रहे। लेकिन जब वे रिटायर हुए तो उनकी किस्मत ने पलटी खाई और उन पर नारायण की कृपा दृष्टि पड़ी। दरअसल, विभाग में इंजीनियरों की कमी है। इस कमी का फायदा साहब को यह हुआ कि नारायण की कृपा उन पर पड़ी और उन्हें एक साल का एक्सटेंशन देते हुए ईएनसी की बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया गया है। विभाग ही नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक वीथिका में यह चर्चा जोरों पर है कि काश! हमें भी नारायण का साथ मिल जाए।

धुआं उठा है तो...

शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा, जिस दिन ईडी की छापेमारी की खबर न आती हो। विगत दिनों ऐसी ही एक खबर प्रदेश में उठी और थम गई। दरअसल, मामला ही कुछ ऐसा हाईप्रोफाइल था। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में सबसे दमदार अफसरों में गिने जाने वाले एक साहब जो इस समय रिटायर हुए हैं, उनके यहां ईडी छापा मारने पहुंची थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही खुद साहब ने आगे आकर कहा कि यह अफवाह है। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो यह बताया गया कि ईडी आई थी, लेकिन फिर वापस चली गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसके कहने पर ईडी ने साहब के गिरेबां में हाथ डालने की कोशिश की और किसके कहने पर बिना कुछ किए चली गई। वहीं सूत्र बताते हैं कि ईडी की यह कवायद इस बात का संकेत है कि साहब ही नहीं बल्कि साहब के तथाकथित संरक्षक भी सचेत रहें, क्योंकि ईडी के हाथ किसी के भी गिरेबां तक पहुंच सकते हैं। बताया जाता है कि जिस दिन से ईडी आकर चली गई, उसी दिन से प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक वीथिका में घबराहट है।

लेने के देने पड़ गए...

हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, अति सर्वत्र वर्जते। लेकिन धर्मशास्त्र की बात करने वाले एक कद्दावर मंत्री ही इस बात को भूल गए और अब उन्हें लेने के देने पड़ रहे हैं। दरअसल, गत दिनों वाल्मी में एक सामाजिक आयोजन किया गया। जिसकी 30-35 हजार रिकवरी निकली। जब इस रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हुई तो पता चला कि यह प्रदेश सरकार के एक कद्दावर मंत्री के समाज से संबंधित है। इस पर संस्थान में पदस्थ तेजतर्रार महिला आईएएस अधिकारी ने आव देखा न ताव और कह दिया कि जिस पर भी यह रिकवरी हैं, मैं उसकी रिकवरी कर दूंगा। यह बात जैसे ही मंत्रीजी को पता लगी, उन्होंने मैडम को ऐसे-ऐसे अपशब्द कहे, जिसे यहां लिखा नहीं जा सकता। फिर क्या था, मैडम ने भी इसे गंभीरता से लिया और सीएम, सीएस और विभाग प्रमुख तक अपनी शिकायत पहुंचा दी। इसका प्रभाव भी जल्द ही देखने को मिला। मंत्रीजी ने अपने विभाग के दर्जनों सीईओ के ट्रांसफर की सूची बनाकर सरकार के पास अनुमति के लिए भेजी, लेकिन वहां से अनुमति नहीं मिली। बताया जाता है कि इन तबादलों के लिए लेनदेन भी हो चुकी थी। अब मंत्रीजी पसोपेश में फंसे हुए हैं।

अमेरिका का हित मेरी पहली प्राथमिकता है। डोनाल्ड ट्रम्प जब राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका की विश्व में साख तेजी से गिरी थी। इसलिए मेरी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रम्प को दोबारा राष्ट्रपति न बनने दिया जाए। इसी में ही अमेरिका और पूरे विश्व का हित है।

● **जो बाइडेन**

आईपीएल का सेटअप इस तरह का है कि पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कौनसी टीम टूर्नामेंट जीतेगी। मुंबई इंडियन लगातार अपने मैच हार रही है, इससे उसके समर्थकों में निराशा का भाव है। लेकिन अगर पुराने रिकार्ड देखें तो मुंबई इंडियन शुरुआती मैच हारने के बाद तेजी से संभलती है और कई बार उसने ऐसी ही स्थिति में कप भी उठाया है।

● **इरफान पठान**

हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बने रहें। वर्तमान में भारत के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं। लेकिन उम्मीद है कि रिश्ते जल्द सुधरेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध भारत के साथ बहाल हों। अगर इस दिशा में भारत चाहे तो बात आगे बढ़ सकती है। इससे दक्षिण एशिया में शांति बहाल होगी।

● **ख्वाजा आसिफ**

चीन कितनी भी कोशिश कर ले, अब भारत पहले वाला नहीं रह गया, जो उसकी गीदड़ भभकियों से घबराएगा। आज चीन कई तरह के पैंतरेबाजी कर रहा है, ताकि भारत को अस्थिर किया जाए, लेकिन ऐसा करने की कोशिश में वह खुद परेशान हो रहा है।

● **एस जयशंकर**

मेरी सफलता का राज यह है कि मेरे परिवार का पूरा समर्थन मुझे मिलता है। चाहे निजी जिंदगी हो या फिल्मी मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। यही बात है कि मैं कोई भी कदम सोच समझकर उठाती हूं। मैं जल्द ही फिल्म उलझन में नजर आऊंगी। इस फिल्म में मेरा आईएफएस अफसर का किरदार है। वहीं जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म देवरा से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हूं। इसके अलावा राजकुमार राव के साथ फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही में भी दिखूंगी। इन फिल्मों में मैंने भले ही अलग-अलग किरदार निभाए हैं, लेकिन इनके पीछे मेरे परिवार का पूरा समर्थन रहा है।

● **जाह्नवी कपूर**

वाक्युद्ध

दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार वर्षों से हाथ-पांव मार रही है। कई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी जब उन्हें लगा कि दिल्ली सरकार को वे अस्थिर नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन उनका कोई भी दांव सफल नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ ईमानदारी है।

● **आतिशी मार्लेना**

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने शराब घोटाले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब ईडी कार्यवाही कर रही है तो ये भाजपा को दोष दे रहे हैं। जबकि सभी जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी शामिल है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे कई और नेता जेल जाएंगे।

● **सुधांशु त्रिवेदी**

कांग्रेस का खेल खराब करेगी बसपा?

बसपा फैक्टर से कैसे निपटेगी कांग्रेस

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा में देरी का कारण भी कहीं न कहीं बसपा फैक्टर है, क्योंकि दोनों ही दल जाति-वर्ग आधारित राजनीति करते हैं और दोनों का कोर वोटर भी लगभग एक सा है। हां, नरेंद्र मोदी ने बसपा के बड़े वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ा है किंतु अभी भी उसका कोर उससे छिटका नहीं है। यानी कांग्रेस को विंध्य, चंबल और बुंदेलखंड की लोकसभा सीटों पर बसपा से बड़ा खतरा है क्योंकि यदि वोट बंटता है तो उसका लाभ भाजपा को होना निश्चित है।

चुनावों से महीनों पूर्व प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली बसपा में इस समय सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस के प्रयासों के चलते इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बची-खुची संभावनाओं के बीच मायावती की ओर से उप्र में प्रत्याशी चयन को लेकर खामोशी यह इंगित करती है कि बसपा में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। जिस राज्य में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हों और लोकसभा चुनाव में पार्टी के सांसद भी जीतते रहे हों, वहां 80 लोकसभा सीटों में से अब तक मात्र 13 प्रत्याशियों की घोषणा करना कहीं न कहीं राज्य में बसपा के राजनीतिक पतन की कहानी कह रहा है। हालांकि मप्र के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि भाजपा और कांग्रेस अपने जिन नेताओं को पार्टी अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाती है, वे सपा-बसपा के टिकट पर अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाते हैं। कई बार इस कवायद में उन्हें सफलता मिलती है तो अधिकांश चुनावों में ये प्रत्याशी किसी न किसी की जीत का गणित बिगाड़ देते हैं।

मप्र में बसपा ने ऐसा कई बार किया है और इस बार भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि कई लोकसभा सीटों पर आयातित नेताओं ने हाथी के सहारे अपनी चाल चलने की तैयारी कर ली है। सपा, कांग्रेस और भाजपा में रह चुके तथा अलग विंध्य प्रदेश की मांग का नेतृत्व करने वाले पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने बसपा का दामन थाम लिया और पार्टी ने भी बिना देर किए उन्हें सतना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके अलावा खजुराहो से कमलेश पटेल, सीधी से पूजनराम साकेत, मंडला से इंदर सिंह उईके, छिंदवाड़ा से उमाकांत बंदेवार, मंदसौर से कन्हैयालाल मालवीय और बैतूल से अशोक भलावी को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि पहली सूची के अनुसार, इन सभी में नारायण त्रिपाठी ही किला लड़ाने की क्षमता रखते हैं क्योंकि भाजपा-कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी उतारकर सतना में ब्राह्मण और क्षत्रियों को एकजुट होने का अवसर दे दिया है। दलबदलू छवि के बाद भी नारायण त्रिपाठी लड़ाकू नेता माने जाते हैं और अलग विंध्य प्रदेश की मांग के आंदोलन ने उन्हें बड़ी प्रसिद्धि दी है। यदि वे सतना में चमत्कार कर दें तो बसपा के लिए वर्तमान परिदृश्य में बड़ी बात होगी।

एक समय समाजवादियों का गढ़ रहा विंध्य क्षेत्र बसपा की दलित राजनीति की पहली प्रयोगशाला बना था। रीवा संसदीय सीट पहली ऐसी सीट थी जिसने देश में बसपा का पहला सांसद दिया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में रीवा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी भीम सिंह पटेल ने विंध्य के सफेद शेर कहे जाने वाले दिग्गज कांग्रेसी नेता श्रीनिवास तिवारी को हराया था। 1996 में बुद्धसेन पटेल और 2009 में देवराज पटेल भी रीवा से बसपा सांसद बनने में सफल रहे थे। इसके बाद बसपा का ग्राफ इस क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से गिरा जिसका सीधा लाभ भाजपा को हुआ। वर्तमान में बसपा यहां दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी है और इसके प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल का गणित बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं।

रीवा से ही लगी सतना लोकसभा सीट पर भी बसपा अपना परचम लहराने में सफल रही है। 1996 के लोकसभा चुनाव में बसपा के सुखलाल कुशवाहा ने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा और कांग्रेस से टूटकर बनी तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को हराकर देशवासियों को अचंभित कर दिया था। हालांकि बसपा इस जीत को कायम नहीं रख सकी और उसका जनाधार सतना लोकसभा में सिकुड़ता चला गया। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि जिन सुखलाल कुशवाहा ने सतना में बसपा का खाता खोला था, इस बार उनके पुत्र सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर भाजपा के गणेश सिंह से मुकाबला करते दिखेंगे।

विंध्य क्षेत्र की ही सीधी और शहडोल लोकसभा सीट पर भी बसपा प्रत्याशी कई बार कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बने हैं जिसका लाभ सीधे तौर पर भाजपा को मिलता है। हालांकि इन दोनों लोकसभा सीटों पर बसपा का खाता अभी तक नहीं खुला है। इसी प्रकार उप्र की सीमा से लगे चंबल क्षेत्र में भी बसपा ने कई बार भाजपा-कांग्रेस का सियासी गणित बिगाड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुरैना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉ. गोविंद सिंह लड़ रहे थे। इस लोकसभा सीट पर जातिवाद हावी है, अत: ब्राह्मण और क्षत्रिय दो खेमों में बंट गए थे। ऐसे में बसपा ने क्षत्रिय समाज के ही वृंदावन सिकरवार को उतारकर डॉ. गोविंद सिंह की हार सुनिश्चित कर दी। कांग्रेस के डॉ. गोविंद सिंह तीसरे स्थान पर रहे।

इस बार अभी तक बसपा ने इस सीट के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है किंतु कांग्रेस की सांसें इस सीट पर अटकी हुई हैं। यही कारण है कि कांग्रेस बसपा के प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही अपना प्रत्याशी उतारेगी। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित भिंड सीट पर मामला और रोमांचक है। मप्र में बसपा के हाथी को पहचान दिलाने वाले पूर्व बसपा प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह बरैया अब कांग्रेस के साथ हैं और भिंड से भाजपा की संध्या राय के सामने मजबूती से खड़े हो गए हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

मप्र में लोकसभा की 29 सीटों के घमासान में भाजपा मैदानी तैयारी और चुनावी रणनीति में कांग्रेस से काफी आगे है। भाजपा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन, राम मंदिर, मोदी की गारंटी, हिंदुत्व जैसे मुद्दों को जनता के बीच गिनाकर सभी सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों के सहारे साख बचाने की कोशिश कर रही है।

मुद्दों की अग्निपरीक्षा

मप्र में लोकसभा चुनाव चार चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को होंगे। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, अयोध्या में राम मंदिर और कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग लोकसभा चुनाव के दौरान मप्र में प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेशभर में चुनावी सभाएं करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकसभा क्षेत्रों में बैठकें और सभाएं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ही मोर्चे पर नजर आ रहे हैं।

इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद सूबे में सियासी पारा हाई हो गया है। प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा विकास, रोजगार समेत तमाम स्थानीय मुद्दों पर सियासी समीकरण साधने में जुट गई हैं। सूबे में दोनों पार्टियों का फोकस विकास और रोजगार के मुद्दे पर है। एक तरफ भाजपा सरकारी योजनाओं और स्कीमों के जरिए विकास के दावे ठोंक रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर भाजपा को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा का दबदबा रहा था और कुल 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि कांग्रेस केवल अपना गढ़ छिंदवाड़ा बचा पाने में ही कामयाब हुई थी।

राज्य में पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव को अगर संकेतक माना जाए, तो मोदी की गारंटी सत्तारूढ़ दल का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। पार्टी गरीबों के लिए मुफ्त अनाज जैसी मोदी की गारंटी और पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने में जुटी हुई है। भाजपा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने में जुट गई है और उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ठुकराने के लिए कांग्रेस पर हमला बोल रही है। वहीं कांग्रेस यह कहकर आलोचना को कुंद करने की कोशिश कर रही है कि विवादित स्थान पर पहले अस्थायी रामलला मंदिर का ताला तब खोला गया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे।

भाजपा बहुसंख्यक समुदाय को साधने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को गर्माए हुए है। वहीं कांग्रेस की रणनीति नरम हिंदुत्व को बढ़ावा देने की है जैसा कि उसने विधानसभा चुनावों के दौरान किया था। नौकरियों की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साध रही है। मप्र में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर है। वहीं कांग्रेस महंगाई, खासकर दूध और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाएगी। विपक्षी दल ने दावा किया कि वस्तु एवं सेवा कर ने छोटे व्यवसायों को बर्बाद कर दिया है और अंतिम उपभोक्ता के लिए कीमतें बढ़ाकर गरीबों को कड़ी चोट पहुंचाई है। मप्र की लगभग आधी आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक

90 के दशक से भाजपा का बोलबाला

1990 में मप्र और छत्तीसगढ़ एक था, तब लोकसभा की 40 सीटें थीं। संयुक्त मप्र में 90 के दशक में कांग्रेस का दबदबा रहा था। इस दौर में ही भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी वर्चस्व को बढ़ाया है। 90 के दशक के बाद से मप्र और छत्तीसगढ़ में भाजपा का ग्राफ बढ़ता गया है। कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान भी लोकसभा चुनावों में भाजपा का दबदबा मप्र में रहा है। यह तब भी हुआ, जब 1993 से 2003 तक मप्र में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान तीन लोकसभा चुनाव हुए। इन तीनों चुनाव में भाजपा का ही दबदबा दिखा है। यह चुनाव 1994, 1996 और 1998 में हुए थे। इसके साथ ही केंद्र में 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही है। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में भी मप्र में भाजपा को 29 में से 25 सीटें आईं। हालांकि 2009 में कांग्रेस की प्रदर्शन में सुधार हुआ था। कांग्रेस को 12 सीटें आई थी और भाजपा को 16 सीटें मिली थी। इस दौरान अन्य को एक सीट पर जीत मिली थी। बीते तीन दशक में यह भाजपा का सबसे कमजोर प्रदर्शन था। वहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन सबसे दमदार रहा है। भाजपा ने मप्र की 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की।

रखती है। मोहन यादव 2003 के बाद से भाजपा के चौथे ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी दावा करते रहे हैं कि जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कैसे अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में ओबीसी, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की उपस्थिति बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के लिए लाड़ली बहना वित्तीय सहायता योजना को विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए गेम-चेंजर के रूप में देखा गया। राज्य भाजपा के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि पार्टी महिलाओं को दिए गए 33 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण और सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर पर भी प्रकाश डालेगी। कांग्रेस मतदाताओं को याद दिला रही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) उसके दिमाग की उपज थी जबकि दावा किया जा रहा है कि मोदी शासन के तहत नौकरी के अवसर कम हो गए हैं। कांग्रेस ने फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया है। पार्टी, एक लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफी की भी मांग कर रही है। ऋण माफी के वादे ने उसे मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की थी।

भाजपा ने सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अब तक 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। मप्र की कुल 29 लोकसभा सीटों में से पांच अनुसूचित जनजाति के लिए और चार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा जहां क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है, वहीं कांग्रेस अपने वादों के दम पर सीटों का ग्राफ बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों के अलावा सूबे के सभी 6 संभागों में अलग-अलग मुद्दे सियासी तूल पकड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि मप्र के हर संभाग में इस बार फैक्टर कौन-कौन से हैं जिनका सियासी असर पड़ने वाला है। क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर,

मप्र को 6 संभागों में बांटा जाता है- ग्वालियर-चंबल, सेंट्रल मप्र (भोपाल), मालवा-निमाड़, महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड। मालवा-निमाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा आठ लोकसभा सीटें हैं। विकास और आर्थिक तरक्की के आधार पर हर संभाग के सियासी मुद्दे भी अलग-अलग हैं। कभी डकैतों से प्रभावित माना जाने वाला यह ग्वालियर-चंबल क्षेत्र अब विकास की ओर छलांग लगा चुका है। भाजपा सरकार ने पिछले साल उप्र के आगरा से जोड़ने वाले एक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी थी। वहीं, कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाया गया है। विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में, रोजगार के रास्ते भी खोल दिए हैं। गुना इस क्षेत्र के प्रमुख लोकसभा क्षेत्रों में से एक है, जहां से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के बेहद करीबी रहे सिंधिया मार्च 2020 में भाजपा में शामिल हो गए थे। इस अंचल की अन्य सीटें मुरैना, भिंड (एससी) और ग्वालियर हैं। बीते दिनों, ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया गया है। सत्तासीन भाजपा दावा कर रही है कि इस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। हालांकि, लोगों की आमदनी और रोजगार के मुद्दे को कांग्रेस जमकर उठा रही है। खासकर इस अंचल में बड़ी संख्या में युवा आर्मी में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। बीते दिनों न्याय यात्रा के दौरान ग्वालियर में राहुल गांधी ने युवाओं और रिटायर्ड सैनिकों से मुलाकात की थी और अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला था। मध्य क्षेत्र (भोपाल) में राज्य की राजधानी भोपाल और नर्मदापुरम सहित इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। झीलों के शहर के नाम से मशहूर भोपाल, विश्व धरोहर स्थलों सांची और भीमबैठिका रॉक शेल्टरों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में पांच लोकसभा सीटें शामिल हैं भोपाल, विदिशा, राजगढ़, बैतूल (एसटी) और नर्मदापुरम।

भाजपा ने इस बार भोपाल से अपनी मौजूदा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर पूर्व महापौर आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं, विदिशा में भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, जो पहले भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विकास और रोजगार उन प्रमुख मुद्दों में से हैं जो इस क्षेत्र में चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस क्षेत्र में विकास की राजनीति पर केंद्रित नजर आई हैं। इसके अलावा राजधानी के आसपास का क्षेत्र शामिल होने के चलते मुद्दे कमोबेश सूबे की सियासत से जुड़े हुए ही हैं।

● **सुनील सिंह**

छिंदवाड़ा में नहीं खुला भाजपा का खाता

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा खास रणनीति पर काम कर ही है। पार्टी की नजर एक-एक वोट पर है। हर बूथ और गांव तक भाजपा अपनी पहुंच बना रही है। इस बार प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य भाजपा ने साध रखा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के पास एक मात्र सीट छिंदवाड़ा है। यहां से नकुलनाथ सांसद हैं। पार्टी ने हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय कर दी है। एक मतदाता केंद्र में 370 मतों को अपने पक्ष में करने का लक्ष्य दिया गया है। विधानसभा और बूथवार भाजपा अपनी रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की नजर उन ग्रामीण इलाकों पर भी है, जहां प्रदर्शन कमजोर था। इन ग्रामीण इलाकों में टोलियों को तैनात किया गया है। पार्टी का खास फोकस छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट लोकसभा सीट पर है। ग्रामीण टोलियों को बूथों पर मतदान बढ़ाने और मतदातों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन सही नहीं था। यही वजह है कि भाजपा इस गलती को दोहराना नहीं चाहती है।

मप्र में किराए पर पीएम आवास

आवासहीनों को पक्की छत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन इसमें अधिकारियों ने वैध दस्तावेजों की जांच नहीं की, बल्कि आवंटियों से पैसे जमा करवाकर उन्हें आवंटन दे दिया। जिससे पात्र हितग्राहियों को सरकार द्वारा बनाए गए किफायती मकान नहीं मिल रहे हैं, वहीं अपात्र एक से अधिक मकानों का आवंटन कराकर, अब इससे मोटा किराया वसूल रहे हैं। इधर जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रह रहे हैं, उन्होंने भी आवंटन के बाद पीएम आवास को किराए पर चढ़ा दिया। यही कारण है कि बीते 10 वर्षों में शासन ने पीएम आवास बनाने के नाम पर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन झुग्गियों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है।

बता दें कि नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक 8500 से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का आवंटन किया जा चुका है, लेकिन इसमें 40 प्रतिशत लोग ही रहे रहे हैं। जबकि 60 फीसदी लोग या तो ऐसे थे, जिनके पास पहले से ही मकान था। या फिर ऐसे लोग जिन्होंने झुग्गी से विस्थापित होकर पीएम आवास का आवंटन तो करा लिया, लेकिन अब फिर किसी अन्य स्थान पर झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। जो मकान उन्हें आवंटित हुआ है, उसे किराए पर देकर हर महीने तीन से पांच हजार रुपए किराया वसूल रहे हैं। इधर शहर में स्मार्ट सिटी समेत अन्य परियोजनाओं के कारण एक दर्जन से अधिक झुग्गी बस्तियों को विस्थापित किया जाना है, लेकिन पर्याप्त मकान नहीं होने से इनको पीएम आवास नहीं मिल रहा है। नगर निगम की मालीखेड़ी, राहुल नगर और कोकता ट्रांसपोर्ट नगर समेत अन्य स्थानों पर बनाए गए मकानों का शत-प्रतिशत आवंटन किया जा चुका है, लेकिन यहां 30 प्रतिशत से अधिक मकान खाली हैं, लोगों ने अब तक पजेशन नहीं लिया है। जिससे इनके द्वारा कॉलोनी का मेंटेनेंस शुल्क भी नहीं जमा किया जाता है। ऐसे में जो रहवासी यहां रह रहे हैं, उन्हें भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जबकि कई मकानों में किराएदार रह रहे हैं, वो भी मेंटेनेंस शुल्क नहीं जमा करते। एक तरफ नगर निगम ने बड़ी संख्या में ऐसे हितग्राहियों को पीएम आवासों का आवंटन कर दिया, जो पात्र ही नहीं थे, वहीं ऐसे पात्र हितग्राही भी हैं, जो मकान के लिए नगर निगम कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मकान खाली नहीं होने से उन्हें आवास का आवंटन नहीं हो पा रहा है।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम की आवासीय परियोजनाओं में मकान बेचने और किराए पर देने की शिकायतें रहवासियों द्वारा की गई है। इसके लिए निगम द्वारा एक टीम बनाकर पीएम आवास में हितग्राहियों का भौतिक परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने गलत दस्तावेज लगाकर मकान लिया है, उनका आवंटन निरस्त किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण का कहना है कि पीएम आवास के मकानों की जांच कराई जाएगी। जो लोग आवंटन के बाद अपने घर में नहीं रह रहे या किराए पर चला रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी करेंगे। यदि इसके बाद भी वापस पीएम आवास में रहने नहीं जाते, तो उनका आवंटन निरस्त किया जाएगा। वहीं यदि पीएम आवास लेने के बाद लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, तो ऐसे में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाएगा।

वहीं राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में स्थिति यह है कि लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में लोन लेकर मकान बुक कराया है लेकिन आज तक उनको मकान नहीं मिल पाया है। मप्र के 40 शहरों में पीएम आवास योजना (शहरी) में मकान बुक कराने वाले हजारों लोगों की है। इन लोगों का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लॉन्च की थी। मकसद ये था कि शहरों में सभी के पास मकान हो, लेकिन मप्र में निगम के ठेकेदारों व निगम अफसरों ने प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को अधर में लटका दिया। भोपाल की रहने वाली विजय लक्ष्मी पटौदिया ने इस योजना में अपनी बेटी के लिए 3 बीएचके फ्लैट बुक कराया था। उनकी बेटी दिल्ली में रहती है और वह भोपाल आना चाहती है। पटौदिया कहती हैं कि नगर निगम ने एक साल में प्रोजेक्ट पूरा होने का दावा किया था। इसके लिए हमने बैंक से लोन लिया है। बैंक अधिकारी मकान की रजिस्ट्री करवाने का दबाव बना रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि रजिस्ट्री जमा नहीं की तो लोन की किस्त बढ़ जाएगी। अब उन्हें कौन बताए कि नगर निगम ने फ्लैट ही नहीं बनाया तो रजिस्ट्री कहां से होगी।

लोकेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि 2017 में नगर निगम ने बड़े-बड़े दावे कर फ्लैट्स की बुकिंग शुरू की थी। 2018 में मैंने 12 नंबर प्रोजेक्ट में आवास बुक कराया था। उस वक्त 18 माह में प्रोजेक्ट पूरा करने का दावा किया था, लेकिन 6 साल बाद भी आवास कब तक बनेंगे, ये खुद निगम अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो निगम ने ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर उसका टेंडर निरस्त कर दिया था, अब नई कंपनी को टेंडर दिया गया है। हर बार की तरह इस बार भी दिसंबर तक काम खत्म करने का वादा किया जा रहा है। मैं पिछले 6 साल से मकान का लोन और घर का किराया दोनों चुका रहा हूं। नगर निगम के 40 शहरों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हर शहर में आवासों की क्वालिटी को लेकर हितग्राही लगातार आपत्ति जताते रहे हैं।

● **अरविंद नारद**

नई कंपनियों को जिम्मा

प्रदेश में प्रोजेक्ट पिछड़े तो इसकी समयसीमा बढ़ाकर दिसंबर-24 कर दी गई। कई निकायों के सामने इस समयसीमा में भी इन प्रोजेक्ट को पूरा करना बड़ी चुनौती है। भोपाल के 3, विदिशा का एक, इटारसी का एक और टीकमगढ़ का एक प्रोजेक्ट कई सालों से अधूरा था, ठेकेदार इन्हें समय पर बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे तो निगमों को इन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर इन्हें हटा दिया। अब नए कंपनी के माध्यम से इन प्रोजेक्ट को पूरा कराया जाएगा। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन के चुनाव भी एक बड़ी वजह रही कि लोगों ने यहां फ्लैट बुक कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। महापौर बनने से पहले भी मैं देख रहा था कि मटेरियल के दाम में बढ़ोत्तरी होने से ठेकेदार काम से हाथ खींच रहे थे। हम लगातार बैठक कर इन प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

महामारी बनेगा बर्ड फ्लू

जानवर फैलाते है वायरस

रोडमैप पर्यावरणीय बदलावों और जानवरों से मनुष्यों में रोगजनकों के फैलाव को जोड़ने वाले तंत्रों को समझाने के लिए इसका और अन्य अध्ययनों का उपयोग किया गया है। इन संबंधों को बाधित करने के लिए पारिस्थितिक हस्तक्षेपों की पहचान करता है और उन्हें लागू करने के लिए नीतिगत ढांचे की पहचान करता है। पारिस्थितिक हस्तक्षेप उन स्थानों की रक्षा से शुरू होता है जहां जानवर खाते हैं। अध्ययन में अध्ययनकर्ता ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि साल के सभी समय में भोजन की प्रचुर आपूर्ति हमेशा उपलब्ध रहे, खासकर जब जानवर प्रजनन और प्रवास जैसे चरणों में हों। इसके बाद यह संरक्षित करना महत्वपूर्ण है कि जानवर कहां बसेरा कर सकते हैं या एकत्र हो सकते हैं, क्योंकि हजारों चमगादड़ गुफाओं में बसेरा कर सकते हैं, इसलिए जब इन क्षेत्रों में गड़बड़ी होती है तो ये आबादी बिखर सकती है, दूसरी जगहों पर जा सकती है और अधिक वायरस फैला सकती है। इसके अलावा, गुफा में रहने वाले चमगादड़ों के पास जाने के लिए अन्य गुफाएं नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में वे वहीं रहते हैं और अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में उनके अधिक वायरस फैलाने के आसार होते हैं।

कोविड-19 के बाद अब इंसानों पर एक और जानलेवा महामारी का हमला होने वाला है। यह महामारी है बर्ड फ्लू एच5एन1। एक नई स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार बर्ड फ्लू एच5एन1 तेजी से जंगली पक्षियों में फैल रहा है। जिस तेजी से यह बीमारी फैल रही है उससे करोड़ों लोगों के प्रभावित होने का खतरा है। वैज्ञानिकों ने 1.20 करोड़ वायरस जीनोम की स्टडी की, उनका डेटा देखा। इसमें पता चला कि फिलहाल सबसे बड़ा खतरा बर्ड फ्लू एच5एन1 को लेकर है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जेनेटिक इंस्टीट्यूट में डॉक्टोरल स्टूडेंट सेड्रिक टैन ने बताया कि जब भी कोई वायरस एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति या एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, तो वह अपने टारगेट के हिसाब से पहले ही खुद को ढाल चुका होता है। जिसे होस्ट के मुताबिक का बदलाव कहते हैं।

सदियों से महामारियों ने करोड़ों इंसानों को मारा है। वजह वायरस, पैथोजेन और बैक्टीरिया रहे हैं। जूनोसिस यानी जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारियों को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। इंसानों में मौजूद वायरसों की वजह कहीं न कहीं जानवर ही हैं। जो कभी न कभी इंसानी शरीर में प्रवेश कर गए। किसी तरह की महामारी या नई बीमारी फैले तो आसान होता है उसकी उत्पत्ति किसी जानवर से जोड़कर खुद को संभालना। चमगादड़ों से कोविड-19 फैला, चिम्पैंजी से एड्स का वायरस। लेकिन अब एक नई स्टडी सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंसानों ने जानवरों को ज्यादा वायरस से संक्रमित किया है। वायरसों के आने का मार्ग एकतरफा नहीं रहा है। यह दोतरफा है। सार्वजनिक तौर पर मौजूद वायरल जीनोम की स्टडी करने के बाद हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं। इंसान जानवरों को दोगुना ज्यादा वायरस देते हैं। जबकि जानवर ऐसा नहीं करते। वैज्ञानिकों ने 1.20 करोड़ वायरस जीनोम की स्टडी की। उनका डेटा देखा। पता चला कि 3000 मामले ऐसे हैं, जब वायरस एक प्रजाति के जीव से दूसरी प्रजाति के जीव पर जाते हैं। इसमें 79 फीसदी वायरस ऐसे हैं, जो एक जानवर की प्रजाति से दूसरी जानवर की प्रजाति में जाते हैं। 21 फीसदी वायरस ऐसे हैं, जो इंसानों से फैलते हैं।

इन तीन हजार वायरसों के मामले में से 64 फीसदी वायरस ऐसे हैं, जो इंसानों से जानवरों में जाते हैं। इसे एंथ्रोपोनोसिस कहते हैं। सिर्फ 36 फीसदी वायरस ऐसे हैं, जो जानवरों से इंसानों में जाते हैं। वायरस के इस ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को जूनोसिस कहते हैं। एंथ्रोपोनोसिस का शिकार होने वाले जीवों में घरेलू बिल्लियां, कुत्ते, घोड़े, सुअर, मवेशी शामिल हैं। इसके अलावा मुर्गियां, बत्तख, प्राइमेट जैसे चिम्पैंजी, गोरिल्ला, हॉउलर मंकीप, रकून, चूहे आदि भी इसके शिकार होते हैं। जंगली जानवरों को इंसानों से होने वाले वायरस संक्रमण का खतरा रहता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जेनेटिक इंस्टीट्यूट में डॉक्टोरल स्टूडेंट सेड्रिक टैन कहते हैं कि इंसान पर्यावरण पर कई तरह का असर डालता है। हर चीज पर डालता है। चाहे वह जानवर हों या पेड़-पौधे। मेरी ये स्टडी हाल ही में नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल में प्रकाशित हुई है। सेड्रिक कहते हैं कि इंसान और जानवर लाखों-करोड़ों माइक्रोब्स लेकर घूमते हैं। जो एक प्रजाति के दूसरी प्रजाति के नजदीक आते ही आदान-प्रदान हो जाते हैं। आमतौर पर सभी कशेरूकीय जीवों में, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी है। जैसे स्तनधारी, पक्षी, सरिसृप, उभयचर और मछलियां। 25 वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय टीम ने प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षित करके और जैव विविधता को बढ़ावा देकर अगली महामारी को कैसे रोका जाए, इसके लिए एक खाका या रोडमैप का सुझाव दिया है। इससे जानवरों को पर्याप्त भोजन, सुरक्षित आश्रय और संपर्क सीमित करने और मनुष्यों में रोगजनकों के फैलने को सीमित करने के लिए दूरी प्रदान की जा सकती है। महामारी तब शुरू होती है जब रोग फैलाने वाले जीव जैसे चमगादड़, लोगों, मवेशियों या अन्य जानवरों के करीब आते हैं और नए रोगजनकों को फैलाते हैं। सार्स-सीओवी-2, सार्स-सीओवी-1, निपाह, हेंड्रा और इबोला जैसे वायरस घातक रूप से चमगादड़ से मनुष्यों तक पहुंचे हैं। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि जब कोई नया रोगजनक मनुष्यों में फैल रहा होता है तो हम उसका कैसे पता लगा सकते हैं और फिर उस पर काबू कैसे पा सकते हैं, न कि हम उस रोगजनक को मानव आबादी में प्रवेश करने से कैसे रोक सकते हैं।

महामारी-रोकथाम की रणनीति 2022 के अध्ययनों पर आधारित है जो संभावित रूप से जूनोटिक बीमारियों वाले सभी जानवरों पर लागू होने वाले केस स्टडी के रूप में काम करती है। अध्ययन बताता है कि चमगादड़ कैसे घोड़ों और लोगों में घातक हेंड्रा वायरस फैला सकते हैं। जब चमगादड़ अपने प्राकृतिक आवास और सर्दियों के भोजन स्रोतों को खो देते हैं, तो उनकी बड़ी आबादी बिखर जाती है और वे छोटे समूहों में कृषि और शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। वे तनावग्रस्त भी हो जाते हैं, आंशिक रूप से अपर्याप्त भोजन स्रोतों के कारण और वे अपने मूत्र के द्वारा अधिक वायरसों को बहाते हैं। वायरस जमीन पर गिरता है जहां चरने वाले घोड़े संक्रमित हो जाते हैं, बदले में घोड़े लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन जब प्राकृतिक आवास पर्याप्त भोजन प्रदान कर सकते हैं, खासकर परती सर्दियों के महीनों में तो चमगादड़ इन आवासों में लौट आते हैं, बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं और वायरस फैलाना बंद कर देते हैं।

● **प्रवीण सक्सेना**

मप्र में सबसे ज्यादा मंडी टैक्स

चुनावी मौसम आते ही जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं को व्यापारियों-किसानों का हित याद आने लगता है। इन दोनों वर्गों का बड़ा मुद्दा मंडी टैक्स में कमी करना है। हर चुनाव में चर्चा में रहने वाला ये मुद्दा अब तक हल नहीं हो सका है। मंडियों में शासन द्वारा सभी प्रकार के अनाज व दलहन जिंसों पर एक प्रतिशत मंडी टैक्स व 20 पैसे निराश्रित शुल्क लिया जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों को सौ रुपए की खरीदी पर 1.20 रुपए टैक्स देना पड़ा रहा है। व्यापारियों का कहना कि गुजरात व अन्य राज्यों में आधा प्रतिशत ही टैक्स लिया जा रहा है। प्रदेश में टैक्स घटाकर आधा प्रतिशत करना चाहिए। पहले डेढ़ प्रतिशत टैक्स व 20 पैसे निराश्रित शुल्क लिया जाता था। बड़े वर्ग की इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों से व्यापारी-किसान कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली।

मप्र में किसान अपनी ज्यादातर फसलें मंडियों में बेचते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि प्रदेश की मंडियों में देश में सबसे अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है। इसका खामियाजा किसान और व्यापारी दोनों को उठाना पड़ता है।

विधानसभा चुनाव से पूर्व मंडी टैक्स घटाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ के आव्हान पर चार सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी। 18 दिन बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंडी टैक्स घटाकर एक प्रतिशत करने पर हड़ताल खत्म की गई थी। द ग्रेन सीड्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र चत्तर का कहना है कि मंडी टैक्स कम करने से सभी को फायदा हुआ है। इसे आधा प्रतिशत करने से किसानों व उपभोक्ताओं को और फायदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को लेकर भी विशेष रूप से नोटिस दिए जाते हैं। फरवरी में केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग द्वारा सभी व्यापारियों को नोटिस दिया गया है कि वर्ष 2017 से लेकर आज तक का मंडी टैक्स और जीएसटी का विवरण प्रस्तुत करें। व्यापारियों में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इसकी वजह यह है कि पांच साल का रिकार्ड केवल तीन दिन में दे पाना संभव नहीं है। वहीं मंडी व्यापारियों का कहना है कि मंडी टैक्स में कमी नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि मंडी टैक्स के साथ सोयाबीन तिलहन वाली फसल होने के कारण इस पर जीएसटी भी लगाया जाता है। मंडी व्यापारियों को परेशानी हो रही है। मामले में सांसद छतर सिंह दरबार ने कहा कि हाल ही में जीएसटी को लेकर जो नोटिस दिया गया है, उसे लेकर मुझे विशेष रूप से कोई जानकारी नहीं है। मंडी से जुड़े किसान और व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उनकी व्यवहारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे। मंदसौर जिले में कुल नौ मंडियों में लगभग 800 व्यापारी किसानों से उपज खरीदी करते हैं। यहां व्यापारियों से एक प्रतिशत मंडी शुल्क वसूला जा रहा है, जो केवल गुजरात से ज्यादा है। इसके अलावा राजस्थान और अन्य राज्यों में यहां से दोगुना मंडी टैक्स वसूला जा रहा है। व्यापारियों का कहना है दूसरे राज्यों से जो उपज खरीद कर लाते हैं, उस पर मंदसौर में भी मंडी टैक्स वसूला जाता है। जबकि मंडी में भी नहीं ले जाते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में मंडी व्यापारियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। समय-समय पर सरकार तक उनकी बात पहुंचाते रहते हैं।

वर्तमान में कपास खरीदी में व्यापारियों से 70 पैसे प्रति सैकड़ा टैक्स लिया जा रहा है। इसमें 50 पैसे मंडी व 20 प्रतिशत निराश्रित शुल्क लिया जा रहा है। अनाज, दलहन, तिलहन में व्यापारियों से 1.20 पैसे टैक्स लिया जा रहा है। इसमें एक रुपया मंडी व 20 पैसे निराश्रित टैक्स है। व्यापारी संघ का कहना है कि सभी तरह की खरीदी पर 1 रुपए 70 पैसे लिए जा रहे थे। विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार ने कपास में 1 रुपया कम किया है तो अनाज में 50 पैसे। यह भी 31 मार्च तक के लिए है। विभिन्न समस्याओं के चलते ही खरगोन जिले में संचालित 100 से ज्यादा जीनिंग महाराष्ट्र में चली गई हैं। बड़वानी में भी यही स्थिति है। टैक्स की मार के चलते सेंधवा व खेतिया के कुछ कपास व्यापारियों ने यहां के बजाय महाराष्ट्र में फैक्ट्री स्थापित कर ली है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

निराश्रित शुल्क का कोई औचित्य नहीं

उज्जैन जिले के व्यापारियों को मंडी टैक्स को लेकर परेशानी है। व्यापारियों का कहना है कि तीन महीने पहले मंडी शुल्क 0.50 फीसद कम कर 1 फीसद कर दिया, किंतु 0.20 फीसद लगने वाले निराश्रित शुल्क को यथावत रख दिया। इसका कोई औचित्य नहीं है। यह शुल्क बरसों पहले बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए लगाया गया था। वर्तमान स्थिति में इस शुल्क का उपयोग नहीं हो रहा है। बता दें देश की किसी भी मंडी में निराश्रित शुल्क लागू नहीं है। प्रदेश के व्यापारी, किसान इस शुल्क से मुक्ति चाहते हैं। ताकि व्यापार में अन्य प्रदेशों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सांसद इसे लेकर प्रयास करते रहे हैं, मगर सफलता नहीं मिली। इधर झाबुआ जिले के व्यापारियों का कहना है कि मंडियों में सुविधाएं नहीं होने से किसानों व व्यापारियों को दिक्कतें आती हैं। खंडवा के कपास व्यापारी भी इस बात से चिंतित हैं कि 31 मार्च के बाद कपास पर भी एक रुपए प्रति सैकड़े के हिसाब से टैक्स वसूला जाने लगेगा। व्यापारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान सरकार ने कपास पर टैक्स कम करते हुए इसे 50 रुपए प्रति सैकड़ा किया था लेकिन अब फिर टैक्स बढ़ने से नुकसान होगा। मंडी में इस सीजन में कपास की भरपूर आवक हुई है। खंडवा ही नहीं बुरहानपुर और खरगोन जिले से भी किसान यहां कपास लाकर बेच रहे हैं। सीजन के शुरुआती दौर में 300 से 400 वाहन तक कपास नीलाम हुआ लेकिन वर्तमान में औसतन 100 वाहन कपास नीलाम हो रहा है। जनप्रतिनिधियों से यहां भी व्यापारी कई बार अपनी समस्या बता चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

मजदूरी की गारंटी फेल

चुनावी मौसम में सियासी गारंटियों का माहौल बना हुआ है। विभिन्न दल अलग-अलग गारंटी देकर जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच मनरेगा योजना में रोजगार की गारंटी मिलने के बाद भी मजदूरों के हाथ करीब छह महीने से खाली हैं। शहरी क्षेत्र में सितम्बर 2023 तथा ग्रामीण क्षेत्र में दिसम्बर 2023 के बाद मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। रोज कुंआ खोदकर, रोज पानी निकालने की तर्ज पर मजदूरों का जीवन चलता है। परंतु सरकार उनकी बेबसी को नहीं समझ पा रही है। तभी तो छह महीने बीतने के बाद भी मनरेगा मजदूरों को मजदूरी दिलाने के प्रति केंद्र व राज्य सरकार गंभीर नहीं हो रही है। स्थानीय अधिकारियों से जब मजदूर अपनी मजदूरी के भुगतान को लेकर संपर्क करते हैं तो अधिकारी भोपाल व दिल्ली से समन्वय बनाकर जल्द भुगतान होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं।

इस तरह झूठी तसल्ली के सहारे मनरेगा मजदूरों के जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है। प्रदेश के मजदूरों को बामुश्किल काम मिला, तो अब उनकी मजदूरी अटक गई है। त्यौहारी और शादी ब्याह के सीजन में भी उन्हें मजबूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से गरीबों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। यह हाल प्रदेश में मनरेगा योजना के हैं। दरअसल इस स्थिति की वजह है केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के हिस्से की राशि का भुगतान नहीं किया जाना। हालत यह है कि प्रदेश को 973 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक महज 177 करोड़ रुपए ही दिया गया है। प्रदेश को अब भी मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार से 796 करोड़ रुपए लेना है। इस स्थिति में मजदूरों व मनरेगा कार्मिकों के लिए जीवन-बसर करना मुश्किल हो रहा है। बढ़ रही महंगाई के बीच जहां श्रमिक मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इस बीच छह महीने से न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनती जा रही है। सरकारी स्तर पर भुगतान को लेकर ठोस प्रयास नहीं करने की वजह से मजदूर लगातार आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं।

प्रदेश को अब भी मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार से 796 करोड़ रुपए लेना है। इस राशि के मिलने की प्रत्याशा में प्रदेश में मजदूरों से काम तो करा लिया गया, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो अफसरों ने बजट न आने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में मजदूर संबंधितों के चक्कर काट-काट कर परेशान हो रहे हैं। यह हाल तब हैं, जबकि मजदूरों से तीन माह तक मजदूरी करा ली गई है। और तो और होली का त्यौहार भी निकल गया है, लेकिन मजदूरी न मिलने से मजदूर परेशान घूम रहे हैं। इसकी वजह से ही समझा जा सकता है कि इस योजना के हाल कितने बेहाल बने हुए हैं। प्रदेश में करीब सवा आठ लाख परिवार ऐसे हैं, जो काम के 99 दिन पूरे कर चुके हैं, लेकिन इस बीच उन्हें एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। इस योजना में केंद्र से राशि नहीं मिलने की वजह से राज्य सरकार की भी परेशानी बढ़ गई है। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने 360 करोड़ रुपए के जल्द भुगतान का भरोसा जताया है। दरअसल यह योजना पूरी तरह से केंद्र प्रवर्तित योजना है और इसमें शत-प्रतिशत मजदूरी का पैसा केंद्र सरकार द्वारा ही दिया जाता है। मजदूरी नहीं मिलने की वजह से इस बार गरीबों को आर्थिक तंगी के बीच ही महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाना पड़ा है। यही नहीं अब तक इस मद में केंद्र से पैसा नहीं मिलने की वजह से होली का त्यौहार भी इसी तरह से मनाना पड़ा।

मजदूरी के मामले में केंद्र सरकार के अधिकारियों की असंवेदनशीलता के कारण राज्य के मजदूर अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। एक तो मजदूरी करा ली और उसके बाद भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। मजदूरी पाने के चक्कर में अब उन्हें पंचायत से लेकर जनपद तक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका समय भी बर्बाद हो रहा है और दूसरा काम नहीं कर पाने की वजह से आर्थिक नुकसान अलग से हो रहा है। यही नहीं सरपंच और सचिव भी मजदूरों की खरी-खोटी सुनने के लिए अलग से मजबूर बने हुए हैं। मनरेगा योजना कोरोनाकाल में लोगों के रोजगार का बड़ा सहारा बनी थी। प्रदेश में कुल 1 करोड़ 7 लाख 46 हजार 359 एक्टिव मजदूर हैं। इन्हें एक दिन की मजदूरी के रूप में 221 रुपए का भुगतान किया जाता है। मनरेगा योजना के तहत कराए जाने वाले कामों के लिए मिलने वाली राशि में 60 प्रतिशत मजदूरी और 40 प्रतिशत सामग्री पर खर्च करने का प्रावधान है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को एक साल में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण मजदूरों को गरीबी से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने वाली मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मप्र में हाल बेहाल हैं। मप्र सहित कई राज्यों के मजदूरों को पिछले कई महीने से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अपने मेहनताने यानी मेहनत की मजदूरी के लिए मजदूर दर-दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। यह योजना केंद्र सरकार के फंड से चलने वाली है, लिहाजा विभाग को केंद्र से पैसा आने का इंतजार है।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

मजदूरी बढ़ोतरी से लेकर भुगतान तक पर उठे सवाल

भारत सरकार की महत्वपूर्ण रोजगार योजना मनरेगा के तहत अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए औसत मजदूरी दर 2018-19 से ही काफी सुस्त गति से बढ़ रही है। 2018-19 में औसत मजदूरी दर 207 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 259 तक हो गई है। यह इस अवधि में केवल 4.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बढ़ती महंगाई के बीच बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ये मजदूरी दर अपर्याप्त रही है। बीते 5 वर्षों में देखा जाए तो ग्रामीण मुद्रास्फीति को कवर करने में वर्तमान मजदूरी दर पूरी तरह से अक्षम रही है। यही कारण है कि बढ़ती महंगाई के बीच मनरेगा मजदूरों के हालात खस्ताहाल हो गए हैं। बढ़ती महंगाई के मुकाबले मजदूरी में मामूली इजाफे से पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। जी हां, मनरेगा की मजदूरी दर में 8.71 प्रतिशत की सबसे तेज वृद्धि 2020-21 में की गई थी, जब महामारी के दौरान मजदूर अपने गृहनगर की ओर पलायन कर रहे थे। 2022-23 में वृद्धि की गई लेकिन वो सिर्फ 1.55 प्रतिशत थी।

अखिल भारतीय सेवा के लिए चयनित होने वाले अधिकांश अधिकारियों की कोशिश रहती है कि या तो उन्हें अपने प्रदेश का कैडर मिल जाए, या फिर मप्र कैडर। लेकिन विडंबना यह है कि जिन आईएएस अधिकारियों को मप्र कैडर अलॉट होता है, वे दूसरे राज्यों में पदस्थ अपने समकक्ष अधिकारियों से कलेक्टर बनने में पिछड़ जाते हैं। यही नहीं यहां यह भी विडंबना देखने को मिलती है कि जो अधिकारी प्रमोट होकर आईएएस बनते हैं, उनमें से कई बिना कलेक्टर बने ही रिटायर हो जाते हैं।

कलेक्टर बनने में पिछड़े मप्र के आईएएस

मप्र में कैडर मिस मैनेजमेंट के कारण युवा आईएएस अधिकारी कलेक्टर बनने में पिछड़ते जा रहे है। मप्र में अभी 2014 बैच तक के आईएएस अधिकारी ही कलेक्टर बन पाए हैं। 2015 से लेकर इसके बाद के बैच के अफसर बेसब्री से कलेक्टर बनने का इंतजार कर रहे हैं। 2015 बैच के अफसरों को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पूर्व उनके बैच की कलेक्टर पद की पोस्टिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी 2014 बैच के चार अधिकारी कलेक्टर बनने की कतार में हैं। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा में 2018 बैच, राजस्थान में 2016 बैच और छत्तीसगढ़ में 2017 बैच के आईएएस अफसरों की जिला कलेक्टर के पद पोस्टिंग हो चुकी है। वर्ष 2012 बैच की महिला अधिकारी को अपनी ईमानदारी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

जिला कलेक्टर के पद पर पोस्टिंग में देरी का असर आईएएस अफसरों के मनोबल पर पड़ रहा है। एक ही पद पर कई वर्षों तक पोस्टिंग से उनका मनोबल टूट रहा है। दूसरे राज्यों में उनके बैच के अधिकारी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं और मप्र में आईएएस अफसर वर्षों से जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम कमिश्नर, एडीएम, मंत्रालय में उपसचिव जैसे पदों पर पदस्थ हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ अफसरों को लगातार जिले दिए जा रहे है, जबकि जिनका कोई माई बाप नहीं है, उन्हें योग्यता या वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापना नहीं मिल रही है।

मप्र में कई आईएएस अफसर ऐसे हैं जो कई बार कलेक्टरी का सुख प्राप्त कर चुके हैं, वहीं कई अफसर ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कलेक्टरी ही नहीं मिली है। साथ ही कुछ ऐसे अफसर भी हैं जो बिना कलेक्टर बने रिटायर हो चुके हैं। ऐसे अफसरों की संख्या एक दर्जन तक पहुंच चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगले दो सालों में यह संख्या दर्जनों में हो जाएगी। इसके उलट कई अफसर ऐसे हैं जो लगातार मैदानी पदस्थापना पा रहे हैं। प्रदेश में यह हाल तब है, जबकि आईएएस बनने वाले अफसरों की तमन्ना कलेक्टर बनने की होती है। जिन अफसरों का कलेक्टर बनने का इंतजार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, उनमें 2007 बैच की बेला देवर्षि शुक्ला, 2008 बैच के चंद्रशेखर वालिंबे, उर्मिला सुरेंद्र शुक्ला, 2009 बैच के आशीष कुमार, 2010 बैच की सपना निगम, अशोक कुमार चौहान, सुरेश कुमार, विनय निगम, मीनाक्षी सिंह, 2011 बैच के गिरीश शर्मा, सरिता बाला प्रजापति, धरणेंद्र कुमार जैन, प्रीति जैन, 2012 बैच के केदार सिंह, विवेक श्रेत्रिय, तरुण भटनागर, अरुण कुमार परमार, राजेश कुमार ओगरे, भारती ओगरे, ऊषा परमार, राजेश बाथम आदि शामिल हैं। मप्र कैडर में आईएएस अफसरों के 469 पद स्वीकृत हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अफसरों सहित वर्तमान में 383 अफसर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि हर अफसर की एक बार कलेक्टर के रूप में काम करने की तमन्ना रहती है, जबकि उनमें कितना भी टेलेंट क्यों न हो। कलेक्टर नहीं बन पाने की वजह से-उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसे ही कई आईएएस अफसर हैं, जो सीनियर होने के बाद भी कलेक्टर नहीं बन सके और ऊपर तक पहुंच रखने वाले उनसे जूनियर कलेक्टरी संभाल रहे हैं। खासकर महिला आईएएस के साथ तो हमेशा से ही भेदभाव होता रहा है। दरअसल इन अफसरों के बारे में कहा जाता है कि इनकी सरकार में पकड़ कमजोर है और प्रशासन में भी उनका कोई प्रभावशाली आका नहीं है, जिसकी वजह से ही उनकी कलेक्टरी के लिए कोई पूछ परख नहीं की जा रही है। इसके अलावा राप्रसे से आईएएस अधिकारी बनने वाले

जूनियरों को बड़ी जिम्मेदारी

लोकसभा चुनाव को लेकर गत दिनों थोकबंद तबादले किए गए। इन तबादलों में सबसे बड़ी बात यह है कि दो जूनियर आईएएस अफसरों के कंधों पर भोपाल और इंदौर नगर निगम की जिम्मेदारी डाल दी गई है। भोपाल निगमायुक्त बनाए गए हरेंद्र नारायण और इंदौर निगमायुक्त बनाए गए शिवम वर्मा की पदस्थापना भी प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। खास बात यह है कि भोपाल और इंदौर निगमायुक्तों के लिए अन्य अधिकारियों के नाम थे, लेकिन नामों पर सहमति नहीं बनने की वजह से दोनों ही नगर निगमों में जूनियर अधिकारियों को पदस्थ कर दिया गया। खास बात यह है कि इंदौर निगमायुक्त के लिए अन्य अधिकारियों के भी नाम चर्चा में थे। लेकिन शीर्ष स्तर पर सहमति नहीं बनने की वजह से अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन संचालनालय शिवम वर्मा को इंदौर का नया निगम आयुक्त पदस्थ किया गया है। भोपाल नगर निगम में 2016 बैच के आईएएस को आयुक्त पदस्थ किया है। 2013 बैच के आयुक्त फ्रेंक नोबल को हटाकर 2016 बैच के अपर कलेक्टर भोपाल हरेंद्र नारायण को नगर निगम भोपाल का नया आयुक्त बनाया गया है। साथ ही उन्हें अपर प्रबंध संचालक मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

अधिकांश अफसरों को एक ही बार कलेक्टर बनने का मौका मिल सका है। इसमें अपवाद स्वरूप एक-दो सीधी भर्ती के आईएएस अफसर भी शामिल हैं। यह बात अलग है कि पूर्व में कुछ पदोन्नत होकर आईएएस अफसर सरकार के बेहद खास रहे, जिसकी वजह से वे न केवल कई जिलों के कलेक्टर बनते रहे हैं, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण और मलाईदार जगहों पर भी पदोन्नत होकर पदस्थ होते रहे हैं।

मप्र आईएएस संवर्ग में प्रमोशन से आईएएस बने 2004 बैच के अमर सिंह बघेल, 2005 बैच के भगत सिंह कुलेश, 2006 बैच के आशकृत तिवारी, रवि डफरिया, अशोक शर्मा, पतिराम कतरोलिया, 2007 बैच के उपेंद्रनाथ शर्मा आदि आईएएस अफसर ऐसे हैं, जो बिना कलेक्टर बने ही रिटायर हो गए। खास बात यह है कि मप्र सरकार प्रमोशन से आईएएस बने अधिकारियों को मैरिट में आने पर भी कंसीडर नहीं करती है। जबकि सरकार को मापदंडों का फॉलो करते हुए प्रमोशन वाले अधिकारियों को भी कलेक्टर बनाना चाहिए। इनमें बेला देवर्षि शुक्ला, भगत सिंह कुलेश, रमेश थेटे, उर्मिल मिश्र के नाम शामिल हैं। रमेश थेटे को सरकार से अनबन के चलते कलेक्टर नहीं बनाया गया। वहीं कलेक्टरी नहीं मिलने के बाद भी आयुक्त, सचिव के रूप में प्रमोशन पाने वालों में पहला नाम उर्मिला सुरेंद्र शुक्ला का है, इन्हें किसी भी जिले की कलेक्टरी नहीं मिली, लेकिन सरकार ने इन्हें सचिव के पद पर प्रमोट करते हुए आयुक्त पुरातत्व जरूर बना दिया।

वहीं 2009 बैच की शैलबाला मार्टिन तो केवल दो महीने के लिए ही कलेक्टर बन सकीं। इसी तरह 2010 बैच के सुरेश कुमार बिना कलेक्टर बने सचिव राजस्व मंडल बना दिए गए हैं। 2008 बैच की उर्मिला सुरेंद्र शुक्ला के अलावा 2010 बैच की सपना निगम, 2011 बैच की नेहा मारव्या, सरिता बाला प्रजापति, प्रीति जैन तथा 2012 बैच की भारती ओगरे को अभी तक कलेक्टर नहीं बनाया गया। अन्य अफसरों में 2010 बैच के चंद्रशेखर बालिम्वे, 2011 बैच के गिरीश शर्मा, रत्नाकरक्षा, हरिसिंह मीना, अमरपाल सिंह कलेक्टरी पाने से वंचित रहे हैं। जबकि सीधी भर्ती के आईएएस में 2010 से लेकर 2011, 2012, 2013 और 2014 बैच तक के अधिकांश अफसर कलेक्टर बन चुके हैं। इनमें से कुछ तो दो से तीन जिलों में कलेक्टरी संभाल चुके हैं। इनमें आलोक कुमार सिंह, ललित दाहिमा, राकेश कुमार श्रीवास्तव, वंदना वैद्य, अनुभा श्रीवास्तव, राकेश सिंह, शशि भूषण सिंह, प्रवल सिपाहा, अशोक कुमार, राम प्रताप सिंह जादौन, छोटे सिंह, गौतम सिंह, अभिषेक सिंह, बसंत कुर्रे, शिवराज सिंह वर्मा, वीरेंद्र कुमार, एमआर खान, चंद्रमोली शुक्ला, रवींद्र कुमार चौधरी तथा दिनेश श्रीवास्तव आदि के नाम शामिल हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव शर्मा का कहना है कि सरकार को चिन्ह-चिन्ह कर अधिकारियों को कलेक्टर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सीनियोरिटी के हिसाब से कलेक्टरी देना चाहिए। जिस तरह सीधी भर्ती के आईएएस के साथ किया जाता है। इन्हें भी मौका मिलना चाहिए, चाहे छोटा जिला ही क्यों न दिया जाए। इससे उनका टेलेंट सामने आएगा।

● **कुमार राजेन्द्र**

इस साल चार अफसर ही बन सकेंगे आईपीएस

प्रदेश की पुलिस सेवा के चार अफसर ही इस साल आईपीएस बन पाएंगे। इसकी वजह है कैडर रिव्यू में होने वाली देरी जिसकी वजह से पदों की होने वाली वृद्धि का अटकना। दरअसल मप्र ऐसा प्रदेश है, जहां पर आईएएस अथवा आईपीएस अफसरों को पदोन्नति समय से पहले ही प्रदान कर दी जाती है, जबकि अन्य संवर्ग के अफसरों को इसके लिए इंतजार करने के साथ ही संघर्ष भी करना पड़ता है। इस मामले में सबसे खराब हालत रापुसे तथा रावसे के अफसरों की है। इस सेवा के

अफसरों के मामलों में हमेशा लेटलतीफी की जाती है। केंद्र सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों का कैडर रिव्यू प्रत्येक 5 साल में करती है। आईपीएस का 2020 का कैडर अभी भी पेंडिंग चल रहा है। जिसके कारण रापुसे के अफसरों की पदोन्नति के पद नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि राप्रसे के अधिकारियों को मिलने वाली पदोन्नति के पद हर साल बढ़ रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में आईपीएस संवर्ग में 319 पद स्वीकृत हैं। एक बार कैडर रिव्यू होने पर 5 से 10 प्रतिशत पदों में वृद्धि हो जाती है। 2005 में कैडर रिव्यू होने के बाद नियमानुसार 5 साल बाद 2010 में रिव्यू होना था, लेकिन इसे तीन साल की देरी से 2013 में किया गया। इसके बाद 2018 में कैडर रिव्यू होना था, लेकिन इसमें देरी करते हुए उसे 2023 में किया गया। इसके बाद से 2020 का रिव्यू अभी भी होने का इंतजार बना हुआ है। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का कहना है कि इसे 2024 में किया जाए तो आईपीएस संवर्ग में करीब 20 पदों में वृद्धि हो जाएगी। इससे राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को 7 से लेकर 10 पद तक मिल सकते हैं। अगर 5 वर्ष के नियम से रिव्यू हुआ तो 2022 के बाद अब 2027 में ही होगा। ऐसे में रापुसे के कई अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद से ही सेवानिवृत हो जाएंगे और एसपी के पद पर पदस्थ होने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाएगा। उधर, वर्ष 2024 में रिक्त पदों के विरूद्ध रापुसे वर्ष 1995 और 1997 बैच के चार अधिकारियों को पदोन्नति मिल सकेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में रापुसे के अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड होने में 25 से 27 साल का समय लग रहा है। इसके उलट राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के अधिकारी 15-16 साल में पदोन्नत होकर आईएएस बन जाते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के 1269 पद स्वीकृत हैं।

हर साल बर्बाद हो रहा 10,556 मीट्रिक टन फास्फोरस

फास्फोरस के अधिक कुशल उपयोग से इस महत्वपूर्ण उर्वरक का सीमित भंडार 500 से अधिक वर्षों तक चल सकता है। बढ़ती आबादी की भोजन की मांग को पूरा करने के लिए दुनियाभर में फास्फोरस समेत कई उर्वरकों की मदद से फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि ये फायदे तभी होंगे जब देश फास्फोरस का सही उपयोग और बर्बादी को कम करेंगे। नेचर फूड में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, अधिकतम फसल पैदावार के लिए समायोजित फास्फोरस के सही उपयोग से वैश्विक फास्फोरस भंडार को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। लगभग 30 से 40 प्रतिशत खेती की मिट्टी में फास्फोरस का अत्यधिक उपयोग होता है, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश ऐसे हैं जहां फास्फोरस का सबसे अधिक उपयोग होता है।

2050 तक दुनियाभर की आबादी लगभग 10 अरब तक पहुंचने का पूर्वानुमान है और अनुमान है कि इस बढ़ी हुई आबादी को खिलाने के लिए 50 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता होगी, जब तक कि फास्फोरस का उपयोग फसल की पैदावार को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए अधिक कुशलता से नहीं किया जा सकता। यूरोपीय संघ द्वारा एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में सूचीबद्ध और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा चर्चा का विषय, विश्व स्तर पर 20,500 मीट्रिक किलोटन फास्फोरस हर साल उर्वरक के रूप में खेती की मिट्टी में उपयोग किया जाता है। इसकी सीमित आपूर्ति और मीठे या ताजे पानी के नुकसान के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जहां यह पानी की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। फास्फोरस मुख्य रूप से फॉस्फेट की चट्टानों के खनन से आता है, जिनमें से मोरक्को और रूस जैसे देशों में ये अपेक्षाकृत कम संख्या में स्रोत मौजूद हैं।

वैश्विक स्तर पर हमारे पास कितना फास्फोरस बचा है, इसका पिछला अनुमान 30 से 300 वर्षों के बीच काफी अलग है। ये पूर्वानुमान वर्तमान में जारी व्यर्थ की प्रथाओं पर आधारित थे और इनमें बहुत अधिक अनिश्चितता थी। अध्ययन में कहा गया है कि यूके में लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ न्यूजीलैंड में एग्रीसर्च और लिंकन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा वैश्विक फास्फोरस के उपयोग और मिट्टी में इसकी मात्रा का पता लगाया। इस नवीनतम शोध में 28 प्रमुख खाद्य फसलों, गेहूं और मक्का से लेकर चावल और सेब तक की अधिकतम वृद्धि के लिए दुनियाभर में खेती की मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा की जांच की गई। शोध से पता चला कि ऐसी मिट्टी जिसमें पर्याप्त फास्फोरस नहीं था और ऐसी मिट्टी जिसमें पौधों के अधिकतम विकास के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा होती है।

अध्ययन के निष्कर्ष मिट्टी में उपलब्ध फास्फोरस की मात्रा और उर्वरकों के रूप में आवश्यक मात्रा पर नई रोशनी डालते हैं और बताते हैं कि यदि हम इसे अधिक कुशलतापूर्वक और न्यायसंगत तरीके से उपयोग करते हैं तो फास्फोरस भंडार 531 साल तक रह सकता है, जो कि वर्तमान प्रथाओं के साथ बने रहने की तुलना में 77 साल अधिक है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि फास्फोरस एक आवश्यक उर्वरक है जो दुनियाभर के खेतों में फसल उत्पादन को बढ़ाता है। यह कृषि की ऊर्जा है जो हमारी खाद्य प्रणालियों को चलाती है, लेकिन हमें इसके प्रबंधन की जरूरत है। हमें इसके उपयोग के साथ और अधिक कुशल और टिकाऊ होने के तरीकों की तलाश करने की जरूरत है। अध्ययन से पता चलता है कि दुनियाभर में फास्फोरस उर्वरकों का उपयोग कैसे किया जाता है इसकी दक्षता में सुधार करने की काफी संभावनाएं हैं। अध्ययन से पता चलता है कि कीमती और उर्वरकों की कमी तथा सीमित वैश्विक फास्फोरस उर्वरक भंडार को बढ़ाए बिना वैश्विक खाद्य उत्पादन को अनुकूलित करना संभव है।

अध्ययन के मुताबिक, अगले 500 वर्षों में हमारे पास फास्फोरस की कमी होने की संभावना नहीं है, लेकिन केवल तभी जब हम अधिकतम फसल पैदावार करने और अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए जितना आवश्यक हो उतना उपयोग करें। शोधकर्ताओं के मुताबिक, अत्यधिक उपयोग के कारण हर साल 10,556 मीट्रिक टन फास्फोरस बर्बाद हो जाता है, जिसमें से अधिकांश यूरोप में गेहूं और घास के मैदान और एशिया में मक्का और चावल पर हावी है। अध्ययन में कहा गया है कि कई किसान फास्फोरस को मिट्टी में जमा करने के लिए इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, मिट्टी में फास्फोरस का केवल एक अंश ही पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। अधिकतम पैदावार के लिए आवश्यक स्तरों को बनाए रखने के लिए प्रयोगों को समायोजित करने से फास्फोरस की बर्बादी पर लगाम लग जाती है। यदि मिट्टी में अत्यधिक स्तर हैं जिसका उपयोग पौधे नहीं कर सकते हैं, तो फास्फोरस संभावित रूप से पानी में घुल सकता है, यूट्रोफिकेशन की तरह जिससे पानी की गुणवत्ता की समस्याएं पैदा होने का खतरा होता है। लेकिन यह सब कटौती के बारे में नहीं है। दुनियाभर में कृषि भूमि के आंकड़ों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने इस बात की भी गणना की है कि दुनियाभर में लगभग तीन-चौथाई खेती की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है। भारत जैसे एशियाई देशों में फास्फोरस की कमी सबसे गंभीर है। नतीजतन, शोधकर्ताओं ने गणना की है कि विश्व स्तर पर फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए मिट्टी में इसकी कमी को पूरा करने के लिए लगभग 57,000 मीट्रिक टन फास्फोरस के उपयोग की जरूरत है।

● **जितेंद्र तिवारी**

सालाना लगभग 3,000 मीट्रिक टन की कमी

शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि मिट्टी में फास्फोरस की जरूरी मात्रा को बनाए रखने के लिए हर साल 17,500 मीट्रिक टन फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप फास्फोरस की वैश्विक मांग में सालाना लगभग 3,000 मीट्रिक टन की कमी आएगी। अध्ययन के मुताबिक, फास्फोरस का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए, सरकारों को ऐसी नीति बनाने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है जो फास्फोरस के उपयोग को केवल वहीं बढ़ावा दे जहां जरूरत हो। इसमें फसल के जरूरी विकास के लिए फास्फोरस के वितरण को संतुलित करना और बनाए रखने वाली सब्सिडी को कम करना शामिल होगा। फास्फोरस के अत्यधिक उपयोग से जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की भी आशंका जताई गई है।

प्रदूषित हो रही मोक्षदायिनी नदियां

मप्र की दो मोक्षदायिनी नदियां नर्मदा और क्षिप्रा लगातार गिर रहे शहरों के सीवेज और नालों के गंदे पानी से प्रदूषित हो रही हैं। यह स्थिति तब है जब सरकार ने इन दोनों नदियों को निर्मल बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं और करोड़ों रुपए की योजनाएं क्रियान्वित हैं। दरअसल इन नदियों को निर्मल बनाने की जिम्मेदारी जिन विभागों की है, उस विभाग के अफसर नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरत रहे हैं। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी मोक्षदायिनी नर्मदा और क्षिप्रा का पानी प्रदूषित हो रहा है। वहीं सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में क्षिप्रा को बारहमासी नदी बनाने के लिए 911.23 करोड़ की नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना भटक गई है। क्षिप्रा जल और परियोजना से जो जल नदी में डाला जा रहा है, उसका प्रबंधन दोषपूर्ण हैं। योजना के तहत 786.07 करोड़ के जल शुल्क की वसूली नहीं हो पाई।

गौरतलब है कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल लगातार नदियों के प्रदूषण को लेकर रिपोर्ट देता है। नदी किनारों पर इंदौर, उज्जैन और देवास में 6777 उद्योगों से प्रदूषित कचरा पैदा करने वाले 137 उद्योगों में से 5 में ही एसटीपी बने है। क्षिप्रा से जुड़ी नदियों के किनारे प्रदूषण फैलाने वाले 6777 उद्योग में 505 बिना अनुमति के चल रहे हैं। उद्योगों के प्रदूषण को रोकने के लिए निरीक्षण होना था। 2020-21 में ही 300 निरीक्षण के टारगेट में से 197 जगह पर अफसर नहीं गए। आदेश के बाद भी उज्जैन-देवास में ईटीपी नहीं बनाए। क्षिप्रा के लिए 2018 में योजना बनी। प्रदूषण बोर्ड व आईआईटी इंदौर की जांच में नदी के पानी में बीओटी की मात्रा में अंतर रहा।

अगर यह कहा जाए कि सरकारी लापरवाही से प्रदेश की नदियां दम तोड़ रही हैं, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। राज्य को अमृत देने वाली मां नर्मदा और क्षिप्रा को जिम्मेदार ही मैली कर रहे हैं। नर्मदा और क्षिप्रा के किनारे बसे शहरों के नालों से गंदा पानी नदियों में डाला जा रहा है। इससे मां का आंचल मैला हो रहा है। नर्मदापुरम में जिम्मेदार नाले का गंदा पानी नर्मदा में छोड़ रहे हैं तो 10 साल से क्षिप्रा को संवारने वाली योजनाएं दम तोड़ रही हैं। अफसर कागजों में पौधरोपण कर रहे हैं। उद्योगों से निकलने वाला दूषित पानी रोक रहे हैं। नालों के पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर नदियों में छोड़ रहे हैं। उनके कागजी झूठे कारनामों की पोल महालेखाकार (सीएजी) ने खोल दी है। क्षिप्रा में घटते पानी और गंदे होने की जांच सीएजी ने की। क्षिप्रा से जुड़े 14 विभागों के 2016-17 से लेकर 2020-21 में किए काम की पड़ताल की तो विभागों की बड़ी लापरवाही सामने आई।

क्षिप्रा व सहायक नदियों की सफाई नगरीय निकायों को करनी थी। लेकिन निगमों द्वारा ही गंदा पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। क्षिप्रा में मिल रहे 28 नालों में 11 की ही टैपिंग की गई है। वहीं क्षिप्रा और उसकी सहायक नदियों के किनारे सांवेर, महिदपुर, आलोट में नालियां नहीं बनीं हैं। निगमों ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए हैं। भविष्य को देखते हुए 1099.26 एमएलडी के एसटीपी के बजाय 552.5 एमएलडी के ही प्लांट लगाए हैं। ये पूरे समय नहीं चलते। नगर निगमों ने 13वें वित्त आयोग का पैसा लेने गंदगी खत्म करने के आंकड़ों में हेर-फेर की। शहरों में सीवरेज लाइन कहीं 61 तो कहीं 80 लाइन डालकर पूरी बताई। वहीं जल संसाधन, पीएचई और एनवीडीए की लापरवाही के कारण क्षिप्रा प्रदूषित हो रही है। क्षिप्रा पर 599.13 मिलियन यूबिक फीट क्षमता के 18 स्टॉप डेम हैं। क्षिप्रा में पूरे साल पानी नहीं रहता। इस पर टैंक, छोटे बांधों या रोक बांध बनाकर भंडारण क्षमता बढ़ाना था। क्षिप्रा पुनर्जीवित करने 2014 में एनवीडीए ने नर्मदा-क्षिप्रा लिंक योजना बनाई, पर 5 साल में 97.72 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा। नदी पुनर्जीवित नहीं हुई। नदी किनारे मिट्टी कटाव रोकने वन विभाग ने 252.63 हेक्टेयर में पौधरोपण बताया, पर कुछ नहीं किया। पंचायतीराज संस्थाओं ने इंदौर-उज्जैन, देवास, रतलाम के 41 क्षेत्रों में पौधरोपण नहीं किया।

● **लोकेश शर्मा**

क्षिप्रा शुद्धि के लिए अभी ये है योजना

क्षिप्रा के नहान क्षेत्र में कान्ह का पानी मिलने से रोकने को 14 महीने पहले 5 दिसंबर 2022 को जल संसाधन विभाग ने कान्ह का 40 क्यूबिक पानी का रास्ता बदलने के लिए 598 करोड़ 66 लाख रुपए की कान्ह डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना स्वीकृत की थी, जिसका टेंडर खुले कई महीने बीत चुके हैं। परियोजना के क्रियान्यन की जिम्मेदारी पाने को हैदराबाद की वेंसर कंस्ट्रक्शन ने सारी अहर्ताएं प्राप्त कर ली हैं, बावजूद उसे कार्य आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी ने 15 प्रतिशत बिलो रेट पर काम करने का प्रस्ताव दिया है। अगर कार्य आदेश जारी हुआ तो लगभग चार साल योजना पूरी होने में लगेंगे। निविदा शर्त अनुरूप तय ठेकेदार फर्म को अगले 15 वर्ष योजना का रखरखाव भी करना होगा। योजना में त्रिवेणी घाट के समीप गोठड़ा गांव में कान्ह पर पांच मीटर ऊंचा स्टापडेम बनाने, यहां से कालियादेह महल के आगे तक 16.5 किलोमीटर लंबा एवं 4.5 बाय 4.5 मीटर चौड़ा पाइपलाइन नुमा आरसीसी बॉक्स बनाकर जमीन पर बिछाने का प्रावधान है। दावा है कि इस चोकोर बॉक्सनुमा पाइपलाइन से कान्ह का 40 क्यूबिक पानी डायवर्ट किया जा सकेगा। अंतिम 100 मीटर लंबाई में ओपन चैनल का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ गंगा मिशन अंतर्गत इंदौर में 34, 40, 120 एमएलडी (मिलियन लीटर्स पर-डे) के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 11 महीने पहले सरकार ने 511 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसके महीनों बाद योजना को क्रियान्वित कराने को 427 करोड़ रुपए का टेंडर आमंत्रित किया। टेंडर खुले कई सप्ताह गुजर गए हैं, लेकिन टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि योजना केंद्र की है, इसलिए कुछ वक्त लगेगा। स्वच्छ गंगा मिशन अंतर्गत 9 महीने पहले केंद्र सरकार ने उज्जैन नगर निगम को 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। विधानसभा चुनाव से पहले पीलियाखाल में 22 एमएलडी एवं भैरवगढ़ में 2.4 एमएलडी कंट्रीटमेंट प्लांट लगाने संबंधी निविदा प्रक्रिया की। ये अब तक स्वीकृत नहीं हुई है। हैरानी की बात ये है कि टेंडर खुलने के बाद नगर निगम परिषद ने अभी कुछ दिन पहले निविदा प्रस्ताव आमंत्रित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

बाहरी दमदार...अपने बेकाम

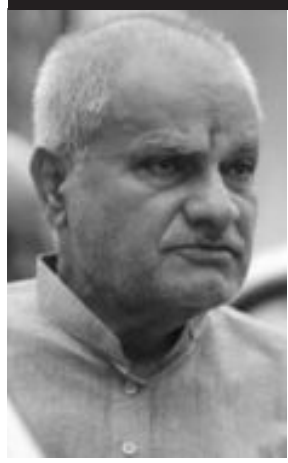

एक वक्त था जब भाजपा चाल, चरित्र और चेहरे की बात भी करती थी और उस पर अमल भी। लेकिन समय के साथ पार्टी पूरी तरह बदल गई है। आज स्थिति यह है कि पार्टी का चेहरा अब आयातित नेता बन गए हैं। जबकि पार्टी की परिपाटी में पनपे दरी बिछाने वाले नेताओं की पूछ-परख कम हो गई है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि भाजपा के मूल कार्यकर्ता या तो घर बैठ गए हैं या फिर किसी अन्य पार्टी में भविष्य तलाश रहे हैं। यानी भाजपा में बाहर से आए नेता दमदार हो रहे हैं और अपने बेकाम।

मप्र में पिछले 1 जनवरी से लेकर अब तक कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों के करीब 1000 नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इससे मूल भाजपाईयों को अपना भविष्य खतरे में नजर आने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा में दूसरी पार्टियों से आए नेता आज बड़े-बड़े पदों पर बैठ गए हैं। खासकर विंध्य क्षेत्र में तो आयातितों का ही दबदबा है। देश और प्रदेश में जब कांग्रेस की तूती बोलती थी, तब विंध्य समाजवादियों का गढ़ था। अब विंध्य इलाका भाजपा के गढ़ में तब्दील हो चुका है। विंध्य में भाजपा के तकरीबन सभी बड़े नेता दूसरे दलों से आए हैं। विंध्य में भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, तकरीबन सब दूसरे दलों से आए हैं। भाजपा ने सीधी से डॉ. राजेश मिश्रा को टिकट दिया है। वे बसपा के रास्ते भाजपा में आए हैं। रीवा से जनार्दन मिश्रा भाजपा सांसद और मौजूदा प्रत्याशी हैं। वे समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए हैं। सतना सांसद गणेश सिंह और शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह भी भाजपा प्रत्याशी हैं। गणेश जनता दल और हिमाद्री कांग्रेस से भाजपा में गई हैं।

आयातित नेताओं का भाजपा में कब्जा होने के बाद से दरी बिछाकर संगठन को खड़ा करने वाले नेता अब एक-एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा, पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला के बाद अब राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। तीनों नेताओं की गिनती खाटी संघी के तौर पर होती है। अजय प्रताप सिंह की जड़ें भाजपा और संघ में काफी गहरी हैं। दूसरे नेता गोविंद मिश्रा हैं। वे भाजपा टिकट पर विधायक और सांसद रहे हैं। उन्होंने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। तीसरे नेता केदारनाथ शुक्ला हैं। वे दो सीटों से चार बार भाजपा के विधायक रहे हैं। विंध्य अब भाजपा का गढ़ है और इलाके में पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। इसलिए पार्टी एक-एक कर घर बैठने वाले नेताओं की परवाह नहीं करती है। पार्टी की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विंध्य इलाके में लोकसभा की चार सीटें हैं और चारों मौजूदा सांसद भाजपा के हैं। इलाके में विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं और उनमें से 25 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। दूसरा कारण यह भी है कि विंध्य में भाजपा के तमाम बड़े नेता दूसरे दलों से आए हैं। वे पार्टी में रच-बस गए हैं, इसलिए पार्टी आलाकमान को लगता है कि हमारी जड़ें दूसरे दलों के नेताओं के कारण गहरी हैं। दूसरे दलों से भाजपा में आए नेता विधायक और सांसद के साथ तमाम अहम पदों पर बैठे हैं। इनमें मौजूदा उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से लेकर बहुत सारे बड़े नेता शामिल हैं।

विंध्य क्षेत्र में भाजपा के जितने बड़े नेता हैं उनमें से अधिकांश आयातित हैं। जो नेता कांग्रेस से भाजपा में आए हैं उनमें राजेंद्र शुक्ला उपमुख्यमंत्री, नागेंद्र सिंह गुढ़ विधायक, दिव्यराज सिंह विधायक, हर्ष सिंह पूर्व मंत्री, बिसाहूलाल सिंह विधायक, नारायण त्रिपाठी पूर्व विधायक, विश्वामित्र पाठक विधायक, रामलल्लू वैश्य पूर्व विधायक और हिमाद्री सिंह सांसद हैं। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कम्युनिस्ट पार्टी से, डॉ. राजेश मिश्रा पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा, रीति पाठक विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, शरदेंदु तिवारी पूर्व विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गणेश सिंह सांसद जनता दल, ज्ञान सिंह पूर्व सांसद जनता दल, जनार्दन मिश्रा सांसद समाजवादी पार्टी, शंकरलाल तिवारी पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी, प्रदीप पटेल विधायक बहुजन समाज पार्टी और सिद्धार्थ तिवारी विधायक कांग्रेस आए हैं।

● **विकास दुबे**

जिनको मिला भाजपा का टिकट वे चमक उठे

भाजपा ने मध्यभारत प्रांत क्षेत्र में आने वाले लोकसभा क्षेत्रों में जिन पर भी दांव लगाया है वे जीतकर चमक उठे हैं। इस बार नर्मदापुरम से उतारे गए दर्शन सिंह चौधरी की पहचान किसानों के लिए आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता से लेकर शिक्षक आंदोलन करने वाले कर्मचारी नेता की है। इसी तरह राजनीति के साथ-साथ भौगोलिक रूप से बड़ी सागर सीट से महिला आयोग की पूर्व सदस्य लता वानखेड़े को आगे बढ़ाया गया है। संगठन की ताकत के साथ वे भी प्रचार में जुट गई हैं। सागर से 2019 में भाजपा से सांसद चुने गए राजबहादुर सिंह लोकसभा चुनावों के पूर्व पूरे संसदीय क्षेत्र में कोई बड़ा नाम नहीं थे। वे सागर शहर की स्थानीय राजनीति करते थे। शहर के वृंदावन और गोपालगंज वार्ड से तीन बार के पार्षद सिंह को पार्टी ने टिकट दिया और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो गई। 2019 के पहले ठाकुर प्रज्ञा सिंह की पहचान एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं थी। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थीं। मालेगांव बम धमाकों में नाम आने के चलते उनका नाम चर्चा में आया। जाने-पहचाने नेता के सामने युवा चेहरे ने कमाल कर दिया और उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता को साढ़े तीन लाख मतों से मात देने का करिश्मा कर दिखाया। इसी तरह बैतूल-हरदा लोकसभा सीट पर भी भाजपा ने 2019 में चौंकाने वाले नाम को आगे बढ़ाया। दुर्गादास उइके शासकीय स्कूल में शिक्षक थे। इसके अतिरिक्त गायत्री परिवार से जुड़े उइके की पहचान धर्म-संस्कृति के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता की थी। भाजपा ने स्वच्छ छवि के नेता को आगे बढ़ाया तो उन्होंने साढ़े तीन लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल कर संसद में पहुंचने का सफर आसानी से तय कर लिया।

गायब हो गया बसंत का मौसम

पर्यावरण में हो रहे बदलाव का दुष्प्रभाव अब किसी से छुपा नहीं है। पर्यावरण का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों की माने तो इस बार सर्दियों पर जलवायु परिवर्तन का ऐसा प्रभाव पड़ा है जिसके चलते बसंत ऋतु ही गायब हो गई है। क्लाइमेट कंट्रोल के गहन अध्ययन में देश के 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव सामने आए हैं।

विश्व में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। जलवायु में बदलाव के दुष्प्रभाव दिखने लगे हैं और अब आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट में पर्यावरण का अध्ययन करने वाली संस्था क्लाइमेट सेंट्रल ने विशेषज्ञों और आंकड़ों के हवाले से कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की ऋतुओं में बदलाव देखा जा रहा है। सर्दी के मौसम पर यह विशेष रूप से दिख रहा है। कहीं सर्दी में तापमान बढ़ रहा है तो कहीं कम हो रहा है। कई लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि सर्दी के बाद आने वाली बसंत ऋतु मानो गायब सी हो रही है। साइंस क्लाइमेट सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. एंड्रयू परशिंग कहते हैं कि मध्य और उत्तर भारतीय राज्यों में जनवरी में तापमान में कमी के बाद फरवरी में तेजी से बढ़ता तापमान सर्दी से बसंत की तरह की स्थिति की ओर बढ़ने के प्रभाव की ओर स्पष्ट संकेत करता है। कोयला और तेल के ईंधन के तौर पर प्रयोग करके लोगों ने भारत में हर मौसम में धरती के तापमान को बढ़ा दिया है।

जलवायु परिवर्तन के लिहाज से देखें तो साल 1850 के बाद से वैश्विक औसत तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हुई है और इस आंकड़े ने साल 2023 को एक नया कीर्तिमान बनाया है। तापमान में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड का बढ़ता स्तर है। क्लाइमेट सेंट्रल की इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत को जलवायु परिवर्तन के वैश्विक रुझानों के संदर्भ में परखना और यहां आ रहे परिवर्तनों का अध्ययन करना है। इस रिपोर्ट में सर्दियों (दिसंबर-फरवरी) पर ध्यान केंद्रित रखा गया है। रिपोर्ट में भारत के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मासिक औसत तापमान की गणना की गई है। साथ ही विशेषज्ञों ने साल 1970 से अब तक वृहद अवधि पर भी ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि यही वह अवधि है जब विश्व में सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग हुई है। लगातार दर्ज किया जा रहा डाटा भी यही कहता है। रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए, प्रत्येक माह में तापमान में वृद्धि के साथ प्रत्येक तीन महीने की मौसम अवधि के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। धरती के गर्म होने की दर साल 1970 के बाद से औसत तापमान में परिवर्तन के रूप में व्यक्त की जाती है।

राजस्थान में सबसे बड़ी तापमान वृद्धि

उत्तरी भारत में जनवरी के ट्रेंड (कम या हल्की तापमान वृद्धि) और फरवरी (तेजी से तापमान वृद्धि) के बीच जो भिन्नता है, उसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में अब सर्दी जैसे ठंडे तापमान से सीधे तौर पर गर्म परिस्थितियों वाले अचानक बदलाव की आशंका प्रबल हो गई है जैसा आमतौर पर मार्च के महीने में होता रहा है। मौसम में इस बदलाव को दिखाने के लिए जनवरी और फरवरी में तापमान में वृद्धि की दर के बीच के अंतर को लिया गया और सबसे बड़ी तापमान वृद्धि राजस्थान में हुई जहां फरवरी की गर्मी जनवरी से 2.6 डिग्री अधिक रही। कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनवरी-फरवरी के तापमान के बीच 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर देखा गया। ये राज्य हैं- राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उप्र, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड। यह तथ्य उन रिपोर्ट को मजबूती प्रदान करते हैं, जिनमें कहा गया कि ऐसा लगता है कि भारत के कई हिस्सों में बसंत का मौसम गायब सा हो गया है। इस अध्ययन में 1 जनवरी, 1970 से 31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी (ईईए) से दैनिक औसत तापमान निकाला गया है। ईईए मौसम स्टेशनों, गुब्बारों और उपग्रहों से मौसम संबंधी आंकड़ों के मिलान के साथ डाटा उपलब्ध कराने के लिए कम्प्यूटर मॉडल के उपयोग की वैज्ञानिक विधि इस्तेमाल करती है।

कई भारतीयों का कहना है कि बसंत का मौसम जैसे गायब सा हो गया है। तापमान अब काफी जल्दी सर्दी से गर्मी जैसी परिस्थितियों में बदल जाता है। इस रिपोर्ट में क्लाइमेट सेंट्रल के विशेषज्ञों ने मौसम के बदलाव के माध्यम के बसंत के मौसम को लेकर भारतीयों की इस धारणा का अध्ययन करने का प्रयास किया है और यह भी जानने का प्रयास किया है कि देश में कहां पर यह धारणा सबसे अधिक लागू हो सकती है। अध्ययन में शामिल देश के प्रत्येक क्षेत्र में सर्दी के दौरान तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। साल 1970 के बाद से मणिपुर में तापमान में सबसे अधिक 2.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है जबकि देश की राजथधानी दिल्ली में सबसे कम यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस की ही बढ़ोतरी सर्दी के दौरान तापमान में हुई है। इस अध्ययन में देश के जिन 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, उनमें से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्दी सबसे तेजी से गर्म होने वाला मौसम पाया गया है। यहां यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि पतझड़ के बाद सबसे अधिक स्थानों में तापमान बढ़ने के मामले में सर्दी के मौसम का देश में दूसरा स्थान है। पतझड़ देश के 13 क्षेत्रों में सबसे तेजी से गर्म होने वाला मौसम रहा। देश में सर्दी के मौसम में तापमान में बदलाव के पैटर्न में भी उल्लेखनीय अंतर महसूस किए गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि देश के दक्षिणी भाग में दिसंबर और जनवरी में तापमान वृद्धि अधिक पाई गई है। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर और जनवरी महीने में सिक्किम में 2.4 डिग्री सेल्सियस और मणिपुर में 2.1 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ। देश के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी के दौरान तापमान में कमजोर वृद्धि देखी गई या यूं कहें कि इस क्षेत्र में सर्दी को और ठंडा होते देखा गया।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

बढ़ रहा मानव-वन्यजीव संघर्ष

धरती पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने और मानव जीवन के लिए सुख-समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जितना जरूरी आदमी है, उतने ही जरूरी अन्य जीव जन्तु और पादप भी हैं। इसी तरह हमारे जीवन में बहुत काम आने वाले पालतू पशु जितने जरूरी हैं, उतने ही जरूरी वन्य जीव जन्तु भी हैं। इनमें से भी अगर केवल वनस्पतियों पर निर्भर जीव जन्तु ही धरती पर रहेंगे तो यह धरती वनस्पति विहीन हो जाएगी, इसलिए दूसरे जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीवों का सही अनुपात में सलामत रहना बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। इस असंतुलन के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है।

सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि देश में बाघों और तेंदुओं जैसे मांसाहारी जीवों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। कूनो पार्क में विदेश से लाए गए चीतों की वंश वृद्धि की सूचना है। देश में बाघों की संख्या 3683 तक पहुंच गई। लेकिन दूसरी तरफ केरल में वायनाड, कन्नूर, पलक्कड़ और इडुक्की जिलों की मानव वन्यजीव संघर्ष की इस सरकारी रिपोर्ट के आकड़े भी देखिए जिनमें कहा गया है कि 2022-23 में इन जिलों में 8,873 जंगली जानवरों के हमले दर्ज किए गए, जिनमें से 4193 जंगली हाथियों द्वारा, 1524 जंगली सूअरों द्वारा, 193 बाघों द्वारा, 244 तेंदुओं द्वारा और 32 बाइसन द्वारा किए गए थे। उत्तराखंड की राजधानी के कुछ इलाकों में लोगों को रात को घरों से न निकलने की सलाह प्रशासन द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य में गुलदारों के बढ़ते हमलों को देखते हुए वन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा रखी है। श्रीनगर गढ़वाल में तो मानों गुलदारों को रात का पहरा देने की ड्यूटी लगी हो। देहरादून महानगर के आसपास जनवरी और फरवरी में मानवभक्षी तेंदुए तीन लोगों को निवाला बना चुके हैं।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा जुलाई 2022 में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी गई लिखित जानकारी के अनुसार हाथियों ने 2019 से लेकर 2022 तक देश में 1,579 मनुष्यों को मार डाला। इनमें से सबसे अधिक 322 मौतें ओडिशा में हुईं, इसके बाद झारखंड में 291, पश्चिम बंगाल में 240, असम में 229, छत्तीसगढ़ में 183 और तमिलनाडु में 152 मौतें हुईं। सन् 2019 और 2021 के बीच बाघों ने अभयारण्यों में 125 मनुष्यों को मार डाला। इनमें से लगभग आधी मौतें महाराष्ट्र में हुईं। उत्तराखंड में हर साल मानव पशु संघर्ष बढ़ रहा है। राज्य गठन के वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक, कुल 1,054 लोग वन्यजीवों के हमलों का शिकार हुए, 5,112 व्यक्ति ऐसे हमलों में घायल हुए। उत्तराखंड में गुलदारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और मानव जीवन के लिए सर्वाधिक खतरा ये गुलदार ही बने हुए हैं। इस संकट के लिए बेजुबान वन्यजीवों को अकेले दोषी ठहराना न तो न्यायसंगत है और ना ही इससे कोई हल निकल सकता है। देखा जाए तो मनुष्य ही इस संघर्ष के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। मानव आबादी बढ़ते जाने से उसका वन्यजीव आवासों में विस्तार होता जा रहा है जिससे वन्यजीवों के आवास की हानि और विखंडन हो रहा है। यह स्थिति वन्यजीवों को मानव बहुल क्षेत्रों में भोजन और आश्रय खोजने के लिए मजबूर करती है, जिससे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है।

वनों की कटाई, कृषि और शहरीकरण जैसे भूमि उपयोग परिवर्तन वन्यजीव आवास और प्रवास पैटर्न को बदल देते हैं, जिससे जानवर मानव बस्तियों के निकट संपर्क में आ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र को बदल रहा है और वन्यजीवों के व्यवहार, वितरण और भोजन की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। इससे जानवरों की गतिविधियों और सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार जैसी अवैध गतिविधियां पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करती हैं और वन्यजीव आबादी को कम कर सकती हैं, जिससे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और मनुष्यों के साथ संघर्ष हो सकता है।

मानवीय गतिविधियां बढ़ने से प्राकृतिक शिकार की आबादी को खत्म कर देती हैं। इससे मांसाहारी जीव घरेलू जानवरों को निशाना बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सड़कें, बाढ़ और अन्य मानव निर्मित संरचनाएं वन्यजीव गलियारों और प्रवास मार्गों को बाधित करती हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है, जो समुदाय अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, उन्हें वन्यजीवों के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इधर, कुछ मामलों में, वन्यजीव व्यवहार के बारे में जागरूकता की कमी और अपर्याप्त शमन उपाय संघर्षों में योगदान कर सकते हैं। संघर्षों को कम करने के लिए शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है।

● रजनीकांत पारे

ऐसे रोका जा सकता है हिंसक संघर्ष

मानव-वन्यजीव संघर्ष को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे में एक वैश्विक चिंता के रूप में मान्यता दी गई है। विशेषज्ञों द्वारा ऐसे कई दृष्टिकोण और उपाय सुझाए गए हैं जिनसे क्षति या प्रभाव को कम करने, तनाव कम करने, आय और गरीबी के जोखिमों को दूर करने और स्थायी समाधान विकसित करने के लिए अपनाए जा सकते हैं। इन सुझावों में वन्यजीवों को बस्तियों में आने से रोकने के लिए बाधाएं (बाढ़, जाल, खाईयां), रखवाली और पूर्व-चेतावनी प्रणालियां, निवारक और विकर्षक (सायरन, रोशनी, मधुमक्खी के छत्ते), स्थानांतरण (वन्यजीवों को स्थानांतरित करना), मुआवजा या बीमा, जोखिम कम करने वाले विकल्प प्रदान करना, साथ ही प्रबंधन भी शामिल हैं। ऐसे उपायों की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन के लिए प्रभावित समुदायों के सहयोग से समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण में अच्छे सिद्धांतों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों को प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाएं वन्य जीवन पर निर्भर करती हैं। इसलिए मानव-वन्यजीव संघर्षों का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता विजन 2050 को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें मानवता प्रकृति के साथ सद्भाव में रहती है और जिसमें वन्यजीव और अन्य जीवित प्रजातियां संरक्षित हैं।

बाघों की मौत संदिग्ध

शिकार की आशंका

शहडोल वन वृत्त के अंतर्गत वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक कुल तीन साल में अकेले उमरिया जिले में 35 बाघों की मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा लगभग 30 बाघों की जान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर मौतों को बाघों के बीच होने वाले आपसी संघर्ष की वजह से बताया गया। वन विभाग को गोपनीय जानकारी मिली है कि इनमें से कई बाघों की मौत सामान्य ढंग से होने वाले आपसी संघर्ष में नहीं हुई, बल्कि उनकी मौत का कोई और ही कारण था। खासतौर से वर्ष 2021 में हुई कुछ बाघों की मौत बेहद संदेहजनक है और संभवतः प्रमाणिक भी है कि वह शिकार के कारण हुई है। वर्ष 2021 में बांधवगढ़ और घुनघुटी के जंगल सहित उमरिया जिले में कुल 15 बाघों की मौत हुई थी। 19 जनवरी 2021 को दमना बीट में एक बाघ शावक की मौत बड़े ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। बाघ शावक की मौत को पार्क प्रबंधन ने पूरी तरह से छुपा लिया था। बाद में चुपचाप बाघ का पीएम कराकर उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। इसी तरह 14 मई 2021 को एक बाघ का शव मानपुर परिक्षेत्र में जमीन में दबा हुआ मिला था, जो साफ-साफ शिकार का परिणाम था। 29 अगस्त 2021 को मानपुर परिक्षेत्र के दमना बीट में एक कुएं में 14 वर्षीय बाघिन का शव मिला था। जिसका शिकार गले में फंदा डालकर किया गया था और बाद में उसके नाखून और दांत तोड़कर कुएं में फेंक दिया गया था।

शहडोल वन वृत्त में कुछ अधिकारियों द्वारा शिकारियों को संरक्षण दिए जाने की आहट वन विभाग को मिल रही है। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में पिछले तीन सालों में हुई बाघों की मौत की जांच के लिए पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने तीन सदस्यीय एक जांच टीम का गठन भी कर दिया है। तीन सदस्यों की इस टीम में रितेश सिरोठिया भारतीय वन सेवा, प्रभारी स्टेट टाइगर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मप्र भोपाल समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि सदस्य के रूप में डॉ. काजल जाधव, सहायक प्राध्यापक स्कूल ऑफ वाइल्ड लाईफ फॉरेन्सिक एंड हेल्थ जबलपुर और मंजुला श्रीवास्तव अधिवक्ता एवं मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक कटनी, मप्र को शामिल किया गया है। यह टीम बाघों की मौत के दस्तावेजों, शिकारियों के पग मार्क तलाशने की कोशिश करेगी।

19 जनवरी 2021 को दमना बीट में एक बाघ शावक की मौत हुई। बाघ शावक की मौत को पार्क प्रबंधन ने पूरी तरह से छुपा लिया। चुपचाप बाघ का पीएम कराकर उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। 14 एवं 15 फरवरी 2021 की दरमियानी रात पनपथा बफर परिक्षेत्र की जाजागढ़ बीट के कक्ष क्रमांक आरएफ 395 में भदार नदी के किनारे बमरघाट में बाघों की लड़ाई हुई थी, जिसमें एक बाघ की मौत हो गई। 29 मार्च 2021 को एक बाघिन का शव बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी जोन की रोहनिया बीट में पाया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघिन की मौत 3 से 4 दिन पहले हो गई थी। 12 अप्रैल 2021 को एक 10 वर्षीय बाघ की मौत शिकार में हुई। 14 अप्रैल 2021 को बनबेई बीट में 4 साल की बीमार बाघिन की मौत हो गई। 14 मई 2021 को शिकार में मरे एक बाघ का मानपुर परिक्षेत्र में जमीन में दबा शव मिला, वहीं 27 मई 2021 को जिले के घुनघुटी में एक बाघ का शव पाया गया। यह शव पतनार कला में पाया गया था। 18 जून 2021 को जिले के घुनघुटी में एक बाघ शावक की अज्ञात वाहन से कुचल जाने के कारण मौत हो गई थी। 16 अगस्त 2021 को 6 महीने के बाघ शावक का शिकार हुआ जिसे आपसी संघर्ष बता दिया गया। 27 अगस्त 2021 को फिर एक बाघ की मौत को आपसी संघर्ष बताकर टाल दिया गया। 29 अगस्त 2021 को मानपुर परिक्षेत्र के दमना बीट में एक कुएं में 14 वर्षीय बाघिन का शव मिला जिसका शिकार गले में फंदा डालकर किया गया था और बाद में उसके नाखून और दांत तोड़कर कुएं में फेंक दिया गया था। 7 नवंबर 2021 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर कोर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी-210 में एक नर बाघ का शव पाया गया। 18 नवंबर 2021 को बाघ टी 37 का शव परासी बीट में पाया गया। 26 नवंबर 2021 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली रेंज से पकड़ी गई घायल बाघिन टी 66 की भूख की वजह से मौत हुई।

8 जनवरी 2022 को टाइगर रिजर्व के मानपुर रेंज बिजौरी हर्राई के निकट मझौली बीट के आरएफ 338 छिंदहाहार में एक साल से कम शावक का बुरी तरह से नुचा हुआ शव पाया गया 27 अप्रैल 2022 को धमोखर के ददरौड़ी बीट में 5 साल की बाघिन मृत अवस्था में मिली। 2 जून 2022 को कल्लवाह रेंज के मझखेता बीट में 4 महीने के बाघ शावक का शव मिला। 4 जुलाई 2022 को पाली रेंज के जमुहाई से सटे साल्हे ढोंडा के जंगल में रिजर्व फॉरेस्ट 526 में तीन दिन पुराना 5 से 7 साल के मेल बाघ का शव मिला। 19 सितंबर 2022 को ताला में स्पॉटी टी 41 की 11 साल की उम्र में वृद्धावस्था के कारण मौत हो गई। 26 दिसंबर 2022 को खितौली रेंज के गढ़पुरी में बाघ शावक की मौत हो गई। वहीं 30 दिसंबर 2022 को घुनघुटी रेंज के कांचोदर बीट में बाघिन की मौत, कारण अज्ञात। वहीं 4 फरवरी 2023 को घुनघुटी रेंज के बलवई बीट में मुड़ना नदी के किनारे बाघ का शव मिला। 2 मार्च 2023 को खितौली रेंज के डोभा बीट के कक्ष क्रमांक 374 में 18 महीने के मादा बाघ शावक का शव पाया गया। मौत का कारण आपसी संघर्ष बताया गया। 3 अप्रैल 2023 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर के बिरुहली बीट के कक्ष क्रमांक 406 जुट्टा तालाब के पास बाघ के हमले में डेढ से तीन महीने के शावक की मौत हुई।

8 मई 2023 को पनपथा बफर के ग्राम करौंदिया में 10 वर्षीय बाघ का शव पाया गया। 18 मई 2023 को बांधवगढ़ के झोरझोरा में मादा बाघ शावक का शव पाया गया। आपसी लड़ाई में मौत बताई गई। 16 जुलाई 2023 मानपुर रेंज के देवरी बीट में ग्राम मढ़उ के पास घायल बाघिन मिली जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। 21 जुलाई 2023 को मानपुर रेंज कर देवरी बीट आरएफ 363 में बाघ का एक सप्ताह पुराना शव पाया गया था। 9 अगस्त 2023 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर परिक्षेत्र के पथरहटा बीट में बाघिन का कई दिनों पुराना शव पाया गया। 27 अगस्त 2023 को मानपुर बफर रेंज के बीट पटेहरा एके पीएफ क्रमांक 641 में लगभग 4 वर्ष के नर बाघ का शव मिला। 15 सितंबर 2023 को मानपुर रेंज के पटेहरा बीट में बाघ का कई दिन पुराना शव मिला। 20 सितंबर 2023 को ताला गेट के पास युवा बाघ की मौत हुई। 19 और 20 दिसंबर को किला मार्ग पर और यहां से दो किमी की दूरी पर आपसी लड़ाई में दो बाघों की मौत हो गई।

● **राकेश ग्रोवर**

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वह पार्टी अपने आप में विश्व की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है। लेकिन सत्तारूढ़ दल को हमेशा विपक्ष का डर सताता रहता है। इसलिए सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्ष को दबाए रखने का हर प्रयास किया जाता रहा है। चाहे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर भारतीय इतिहास को देखें तो इंदिरा गांधी ने सबसे अधिक 51 बार राष्ट्रपति शासन लगवाया है।

● राजेंद्र आगाल

21 मार्च को जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया तो विपक्ष ने एक सुर में अलाप किया कि यह लोकतंत्र की हत्या है। यह बदले की राजनीति है। विपक्ष के आरोप के संदर्भ में देखें तो भाजपा से अधिक कांग्रेस ने इस देश में विपक्षी पार्टियों पर अंकुश लगाया है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूंस डाला था। इंदिरा गांधी ने आरएसएस को निशाना बनाकर उसे राजनीतिक वैधता प्रदान करने, राजीव ने 1989 में जनादेश का सम्मान नहीं करने, वाजपेयी-आडवाणी ने समय से पहले चुनाव करवाने की जो गलतियां कीं, उससे भारतीय राजनीति की दिशा बदली। अब केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विपक्ष के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या भारत में बदले की राजनीति होती है?

2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तभी पूरे देश में यह संदेश प्रसारित हो गया था कि अब शासन का रुख कठोर होगा। इसकी वजह यह थी कि नरेंद्र मोदी खांटी संघी नेता हैं और उनकी पूरी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई है। यानी उनका टारगेट कांग्रेस ही है। इसकी झलक उस समय दिखी जब उन्होंने कांग्रेसमुक्त भारत का नारा दिया। उनके शासनकाल की सबसे अच्छी बात अब तक यह रही कि उन्होंने बेवजह राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति चलाई है, उसे विपक्षी बदले की राजनीति कह रहे हैं। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि अभी तक केवल विपक्षी नेता ही ईडी, सीबीआई और आईटी के रडार पर रहे हैं। हालांकि विपक्ष भले ही एजेंसियों की कार्यवाही को बदले की राजनीति माने, लेकिन विपक्षी नेताओं के यहां जिस तरह कालाधन पकड़ाया हैं, उससे देशभर में यह संदेश जा रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है।

देश में वर्तमान समय में दिल्ली शराब पॉलिसी में हुआ भ्रष्टाचार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में जिस तरह ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है उससे पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद कहा है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा न देने पर अड़े रहते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कानून के जानकारों का भी कहना है कि उपराज्यपाल अनुच्छेद-239एए के तहत राष्ट्रपति को शामिल कर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के आलोचकों का कहना है कि ज्यादातर बार इसे राज्य में राजनीतिक विरोधियों की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसे संघीय राज्य व्यवस्था के लिए खतरा मानते हैं। हालांकि, 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही केंद्र सरकार ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। केंद्र में पिछली कांग्रेस सरकारों ने अनुच्छेद-356 का इस्तेमाल कर 100 से ज्यादा बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद में कहा भी था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद-356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हुए 51 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया।

पहली बार सरकार बर्खास्त

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद-356 का पहली बार 20 जून 1951 को पंजाब सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया। तब उन्होंने पंजाब की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया था। हालांकि, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 1951 में पंजाब की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने अंदरूनी कलहों से निपटने के लिए खुद ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी। रिकॉर्ड के मुताबिक, पहली बार केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट ईएमएस नम्बूदरीपाद की सरकार को 1959 में बर्खास्त कर अनुच्छेद-356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद-356 केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार को हटाकर प्रदेश का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद-356 कहता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र नाकाम होने या इसमें रुकावट पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के दो आधार हो सकते हैं। पहला, जब कोई राज्य सरकार संविधान के मुताबिक शासन चलाने में सक्षम ना हो और दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हो। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था, कि आरोप लगते हैं कि हम राज्य सरकारों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन, इतिहास उठाकर देख लीजिए कि वो कौन सी पार्टी थी, जिसने अनुच्छेद-356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल

किस प्रधानमंत्री ने कितनी बार लगाया राष्ट्रपति शासन?

	प्रधानमंत्री	कार्यकाल	कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा?
•	जवाहरलाल नेहरू	15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964	7
•	लालबहादुर शास्त्री	9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966	1
•	**इंदिरा गांधी**	**24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984**	**51**
•	मोरारजी देसाई	24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979	17
•	चरण सिंह	28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980	4
•	राजीव गांधी	31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989	6
•	वीपी सिंह	2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990	2
•	चंद्रशेखर	10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991	5
•	पीवी नरसिम्हा राव	21 जून 1991 से 16 मई 1996	11
•	अटल बिहारी वाजपेयी	16 मई 1996 से 1 जून 1996 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004	5
•	एचडी देवेगौड़ा	1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997	1
•	इंद्र कुमार गुजराल	21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998	0
•	मनमोहन सिंह	22 मई 2004 से 26 मई 2014	12
•	**नरेंद्र मोदी**	**26 मई 2014 से अब तक**	**10**

कैसे काम करता है राष्ट्रपति शासन?

देश में अब तक 132 बार अलग-अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इनमें से तकरीबन 90 बार राष्ट्रपति शासन तब लगा, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आर्टिकल-356 को हम आसान भाषा में राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। इसके तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को भंग किया जा सकता हैं। जब किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्यपाल उस समय राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा कर सकता है। आमतौर पर इसे 6 महीने के लिए लगाया जाता है लेकिन यदि राज्य में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो इसे अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वहां की सारी व्यवस्था सीधे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, इसलिए इसका मतलब हुआ कि यहां का पूरा शासन केंद्र के हाथ में आ जाता है। राष्ट्रपति शासन को कभी भी हटाया जा सकता है। आमतौर पर राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो आधार होते हैं। पहला, अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लें कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है। दूसरा, अगर राज्य, केंद्र सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है। दूसरे प्रावधान का जिक्र आर्टिकल-365 में है। इसके अलावा अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले या विधानसभा अपना मुख्यमंत्री ना चुन पाए तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है।

किया। इन्होंने 90 बार से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। इसमें से सिर्फ इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद-356 का 51 बार इस्तेमाल किया। केरल की चुनी हुई वामपंथी सरकार को पंडित जवाहर लाल नेहरू पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कुछ ही समय में चुनी हुई पहली सरकार को घर भेज दिया। तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि की सरकार को भी कांग्रेस ने ही बर्खास्त किया था। हर क्षेत्रीय नेता को कांग्रेस ने परेशान किया। राज्यपाल कार्यालय को कांग्रेस कार्यालय में बदल दिया गया। केंद्र ने 70 और 80 के दशक में विपक्ष की राज्य सरकारों को गिराने के लिए संविधान के अनुच्छेद-356 का खूब दुरुपयोग किया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इस अनुच्छेद के सबसे ज्यादा इस्तेमाल का आरोप लगता है। वह करीब 15 साल देश की प्रधानमंत्री रहीं। केंद्र की कांग्रेस सरकारों ने 1966 से 1977 के बीच 36 बार और 1980 से 1984 के बीच 15 बार अलग-अलग राज्यों में विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया। वहीं, केंद्र में जनता पार्टी के तीन साल के शासनकाल में 21 बार अलग-अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनीं तो उन्होंने एकसाथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी अलग-अलग राज्यों में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था।

ऐसा माना जाता है कि 70 और 80 के दशक में विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए केंद्र सरकार ने संविधान के इस अनुच्छेद का खूब दुरुपयोग किया। आर्टिकल-356 के दुरुपयोग का सबसे ज्यादा आरोप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर लगता है। इंदिरा गांधी के आपातकाल के पहले और बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर लगभग 15 साल का कार्यकाल रहा। इस दौरान 1966 से 1977 के बीच 36 बार और 1980 से 1984 के बीच 15 बार अलग-अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आजादी से लेकर अब तक जितनी बार भी राष्ट्रपति शासन लगा है, ज्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आर्टिकल-356 का दुरुपयोग सिर्फ कांग्रेस ने ही किया। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी के तीन साल के कार्यकाल में 21 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इन तीन साल में 6 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनीं और उन्होंने एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया।

भाजपा ने कब लगाया राष्ट्रपति शासन

आर्टिकल-356 के इस्तेमाल को लेकर भाजपा भी पीछे नहीं रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जहां इसका 5 बार प्रयोग हुआ। वहीं 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र इसके उदारहण हैं। सरकार में पहली बार 28 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। मोदी सरकार में अब तक 10 बार आर्टिकल-356 का इस्तेमाल हो चुका है। राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि 1994 के एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल-356 के उपयोग को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। एसआर बोम्मई अगस्त 1988 से अप्रैल 1989 के बीच कर्नाटक में जनता दल की सरकार में मुख्यमंत्री थे। लेकिन अप्रैल 1989 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बोम्मई की सरकार को इस आधार पर बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया कि उनके पास बहुमत नहीं है। इसके विरोध में बोम्मई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने मार्च 1994 में फैसला सुनाया और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए व्यापक गाइडलाइन तय की। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक केंद्र सरकार आर्टिकल-355 का पूरी तरह उपयोग न कर ले, तब तक अनुच्छेद-356 को लागू करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अनुच्छेद-355 केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था संभालने के लिए दखल करे। इसके जरिए केंद्र ये भी देखता है कि राज्य में सबकुछ संविधान के अनुरूप चल रहा है या नहीं।

अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे केंद्र की सरकारों ने आर्टिकल-356 का इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार किया है। लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि देश में दो राज्य ऐसे भी हैं जहां अब तक राष्ट्रपति

शासन नहीं लगा है। ये दो राज्य हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आपको बता दें कि अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जम्मू-कश्मीर में लागू हुआ जो 6 साल 264 दिन तक चला था, वहीं सबसे कम कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 7 दिन के लिए लगा था। अब तक उप्र और मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो राज्यों में सबसे ज्यादा है।

ये भी है चुनौती

डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में अनुच्छेद-356 को संविधान के मृत पत्र की संज्ञा दी थी। उम्मीद की गई थी कि इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। लेकिन अब तक तो ऐसा होता दिखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि इंदिरा गांधी की सरकार में अनुच्छेद-356 का सर्वाधिक प्रयोग हुआ लेकिन सभी पार्टियों ने इसका मनमाना इस्तेमाल किया। हालांकि दल-बदल कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल-356 का दुरुपयोग मुश्किल जरूर हो गया। राजभवन की बजाय बहुमत का निर्धारण जब विधानसभा में होने लगे तो राज्यपाल की भूमिका भी कम हो गई। इसलिए समय के साथ आर्टिकल-356 का दुरुपयोग कम हुआ और यह संविधान और संघवाद के लिए अच्छी बात है। विराग गुप्ता कहते हैं कि आर्टिकल-356 के मुकाबले एक नई चुनौती सामने आ रही है। कई राज्य सरकारों के आरोप हैं कि राज्यपाल उन्हें पूरी ताकत से काम नहीं करने दे रहे। संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के स्पष्ट निर्धारण के बावजूद इस तरीके के विरोधाभास होना संघीय व्यवस्था के लिए बेहतर संकेत नहीं हैं।

आपातकाल सबसे बड़ी गलती

इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी में आरएसएस को निशाना बनाया जाना और उसके हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डालना, जिनमें अधिकतर गुमनाम किस्म के लोग थे। ये जनसंघ के उन नेताओं से अलग लोग थे जिन्हें उन्होंने जेल में बंद किया था। 1989 में, राजीव गांधी द्वारा अपनी सरकार न बनाने का फैसला, जबकि उन्हें लोकसभा में 197 सीटें मिली थीं। उनका कहना था कि जनादेश उनके खिलाफ है और वे उसका सम्मान करेंगे। याद रहे, उनकी पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी द्वारा मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से चुनाव जीतने से उत्साहित होकर आम चुनाव समय से छह महीने पहले करवाना।

इमरजेंसी थोपे जाने को आपने सबसे बड़ी राजनीतिक भूल क्यों नहीं माना, आरएसएस के काडर को निशाना बनाने और जेल में डालने को इतना अहम कैसे मान लिया, इन सवालों का जवाब सीधा-सा है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने की तोहमत से जल्द ही बरी हो गईं, 1977 में उनकी हार मामूली झटका बनकर रह गई। तीन साल के अंदर ही वे भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट आईं। इमरजेंसी के बाद के 46 वर्षों में से 25 साल अगर उनकी पार्टी सत्ता में रही, तो साफ है कि जनता ने इमरजेंसी वाली उनकी भूल माफ कर दी। लेकिन उन्होंने आरएसएस को जो निशाना बनाया उसका असर लंबे समय तक दिखा। सबसे पहले तो इसने एक राजनीतिक ताकत के तौर पर आरएसएस को वैधता प्रदान कर दी, और उसे उनकी पार्टी के मुख्य वैचारिक प्रतिद्वंद्वी का दर्जा दे दिया। तब तक, उनकी पार्टी की मजबूती यह थी कि उसे किसी विचारधारा से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उनकी अपनी ही पार्टी में कुछ रूढ़िपंथी, दक्षिणपंथी झुकाव वाले, स्वतंत्र पार्टी के उदारवादी पूंजीवाद के समर्थक, वामपंथी धारा के कुछ तत्व मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा बनाम दूसरी विचारधारा वाली स्थिति कभी नहीं रही थी।

इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को इस मुकाबले में उलझा दिया। आरएसएस के अधिकतर गुमनाम और साधारण लोगों को भारी संख्या में गिरफ्तार करवाकर उन्होंने आरएसएस को व्यापक सम्मान और कुछ हद तक ताकत भी दिला दी। समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने भी उसके काडर को अपना हरावल दस्ता बना लिया। कुछ समय बाद जनसंघ ने भाजपा के रूप में अपना नया अवतार ले लिया, जो बाद के दशकों में कमजोर पड़ती कांग्रेस की एकमात्र वैचारिक प्रतिद्वंद्वी बन गई। अगर इंदिरा गांधी ने आरएसएस को निशाना न बनाया होता तो आज मोदी दूसरी बार बहुमत से सत्ता में न बैठे होते और तीसरी बार गद्दी पर नजर न टिकाए होते। 1989 के चुनाव ने राजीव गांधी की कांग्रेस को 1984-85 की 414 सीटों से 197 सीटों पर सिमटा दिया था। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जनता दल, जिसे केवल 143 सीटें मिली थीं, और जिसके सबसे बड़े नेता वीपी सिंह

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बवाल?

आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। कथित शराब घोटाला मामले में 9 बार समन भेजने के बाद भी वे पूछताछ के लिए नहीं गए। वे प्रवर्तन निदेशालय के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अगर ईडी अदालत का आदेश ले आए, तो वे पूछताछ के लिए हाजिर हो जाएंगे। जब उन्हें लगने लगा कि जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं, तो उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि आम चुनाव तक उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इस पर अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उनके आवास पर छापा मारा और कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्हें अपने दफ्तर ले गई, फिर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका उसी समय से जताई जा रही थी, जब उन्हें चौथा समन भेजा गया था। खुद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सार्वजनिक मंचों से कहते फिर रहे थे कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार करवा सकती है। इसी हफ्ते सीबीआई ने जब कहा कि शराब घोटाला मामले में अभी कुछ और बड़े लोग गिरफ्तार होंगे, तब पक्का हो गया कि केजरीवाल जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। कथित शराब घोटाले को लेकर पिछले एक-डेढ़ वर्ष से खूब सियासत भी हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से नई आबकारी नीति बनाई और भारी रिश्वत लेकर लोगों को शराब के ठेके बांट दिए। इस आरोप में आम आदमी के कई नेता और दिल्ली सरकार के अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। भारत राष्ट्र समिति की नेता और केसीआर की बेटी के कविता को भी इस घोटाले में संलिप्तता के आरोप में पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि इस पूरे घोटाले के मुख्य षड्यंत्रकारी केजरीवाल हैं।

प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा न करने का फैसला करके एक ऐसे अस्वाभाविक गठबंधन का रास्ता बना दिया जिसमें एक-दूसरे के घोर वैचारिक दुश्मन, भाजपा और वामदलों ने बाहर से समर्थन देकर वीपी सिंह की सरकार बनवा दी।

जाहिर है, राजीव गांधी ने सोचा होगा कि इस तरह का बेमेल गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और फिर वे अगले चुनाव में वापस सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन वे आंकलन में कई गलतियां कर बैठे। सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे यह नहीं समझ पाए कि भाजपा को कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में खड़ा करने का मौका लालकृष्ण आडवाणी को देने के क्या खतरे हो सकते हैं। उधर कांग्रेस कमजोर पड़ती गई, इधर आडवाणी की भाजपा की सीटों की संख्या जल्दी ही सैकड़े के अंक में पहुंच गई और उसने अछूत वाले अपने ठप्पे से इस हद तक मुक्ति पा ली कि 1998 में पर्याप्त संख्या में क्षेत्रीय दलों ने उसके साथ गठजोड़ कर लिया। अछूत वाले इस पुराने ठप्पे से मुक्ति की मुख्य बात यह थी कि विचारधारा के आधार पर इसका विरोध करने वाले मंडलवादी और वामपंथी दलों ने भी भाजपा के साथ गठबंधन स्वीकार कर लिया। यह 1989 में राजीव गांधी की ओर से मिला उपहार था। उनकी पार्टी बाद में 15 साल तक सत्ता में जरूर रही लेकिन कमजोर पड़ती गई। इस एक गलत आंकलन ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस युग का पटाक्षेप कर दिया और 2014 में भाजपा युग शुरू हो गया।

जरा सोचिए, कांग्रेस ने 197 सांसदों के बावजूद अपनी सरकार बनाने से मना कर दिया, जबकि इसके बाद 20 वर्षों (1996, 1998, 1999, 2004) तक बने सभी गठबंधनों का नेतृत्व उस पार्टी ने किया जिसे इससे कम सीटें मिली थीं। इस आंकड़े में मामूली सुधार बेशक कांग्रेस ने ही 2009 में 206 सीटें जीतकर किया। हम केवल गठबंधनों की बात कर रहे हैं, 1991-96 में नरसिम्हा राव की अल्पमत वाली कांग्रेस सरकार की नहीं। गठबंधन की अपरिहार्यता को राजीव भांप नहीं पाए और उन्होंने अपने सबसे शातिर प्रतिद्वंद्वियों को सत्ता सौंपने का जो

आलसी फैसला किया उसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल डाली। जनवरी 2004 तक, तीन अहम हिंदी प्रदेशों में भारी चुनावी जीत हासिल करके भाजपा नेतृत्व उड़ान भरने लगा। उसने मान लिया कि वहां जो हुआ वह उसके प्रभाव वाले दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। प्रमोद महाजन के नेतृत्व में उसके विचारकों और आडवाणी के साथ जुड़े तत्वों ने फैसला कर लिया कि चुनाव समय से पहले करवा लेना चाहिए और लहर का लाभ उठा लेना चाहिए। संदेह जाहिर करने वाले एकमात्र नेता थे वाजपेयी, जो अल्पमत में थे।

आडवाणी गुट एक और मंशा से भी काम कर रहा था, जो उतना छिपा हुआ भी नहीं था कि वाजपेयी की सेहत उन्हें 5 साल से ज्यादा नहीं सक्रिय रहने देगी, इसके बाद आडवाणी आसानी से उत्तराधिकार संभाल लेंगे। उस समय भारत ने तीन तिमाहियों तक औसत 8 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर्ज की थी। इसने इंडिया शाइनिंग मुहिम शुरू करने का पर्याप्त कारण उपलब्ध करा दिया। उस जोश में भाजपा वह काम करना भूल गई जिसने उसे सत्ता में पहुंचाया था। वह काम था, अपने गठबंधन के साथियों को जोड़े रखना। इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा को भारी हार का सामना करना पड़ा और उसे कांग्रेस से सात कम, 138 सीटें ही मिलीं। गुजरात दंगों के बाद उसके प्रति पुरानी अछूत वाली भावना कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों और उसके संभावित सहयोगियों में फिर से उभर आई। इस वजह से न केवल कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में वापस आ गई, आडवाणी और उनके सभी साथियों के राजनीतिक करियर पर विराम लग गया। इस बीच नरेंद्र मोदी को अपनी तैयारी करने और उभरने का समय मिल गया। अब सवाल है कि किसकी भूल को किस नंबर पर रखा जाए। वैसे राजीव गांधी की भूल सबसे ऊपर रखी जाएगी, क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति पर सबसे बड़ा असर डाला। उनकी मां ने आरएसएस को राजनीतिक वैधता प्रदान करने की जो भूल की थी उसके मुकाबले राजीव की भूल को मात्र इसलिए बड़ा माना जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी फिर भी 1984 तक और अपनी मृत्यु के बाद भी उसे हाशिये पर रखने में सफल रही थीं। राजीव ने दिसंबर 1984 में भाजपा को मात्र दो सीटों पर समेट दिया था।

अगर उन्होंने 1989 में इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ी होती तो बाद के दशकों में राजनीति कुछ अलग ही दिशा में चल सकती थी। वैसे, अपनी मां की भारी भूल का इस हद तक तो उन्होंने सुधार किया ही। इंदिरा गांधी ने आरएसएस को राष्ट्रीय राजनीति में जगह और इज्जत दिलाई। आडवाणी की भूल यह थी कि उन्होंने खुद अपनी महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर दिया। बेशक इसने मोदी के लिए रास्ता बनाया, और मोदी ने उन्हें भारतरत्न से सम्मानित करके अपना आभार जता दिया।

भ्रष्टाचार पर प्रहार या विपक्ष के नेताओं पर वार

केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करती है, लेकिन चुनावी चंदे में हुई हेरा-फेरी को लेकर खुद दबे पांव बच निकलने की कोशिश भी करती है। शराब घोटाले में जांच एजेंसियों को पहले से पता था कि घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता है तो उन्हें पहले ही क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया क्योंकि तीसरे समन के बाद गिरफ्तार करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पास था। फिर दो साल तक इंतजार करने के पीछे की मंशा क्या थी। घोटाले में शामिल होने के बावजूद दो साल तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो चुनाव तक रुककर भी इसे अंजाम दिया जा सकता था। यही जल्दबाजी जांच एजेंसियों को तो कटघरे में खड़ा करती ही है, सरकार की मंशा पर भी सवालिया निशान उठाती है। क्या सरकार आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से भयभीत है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं क्या केंद्र की वर्तमान सरकार 2024 के चुनाव में जीत को लेकर जो 400 पार का दावा कर रही है, उसे अंजाम देने के लिए इस तरह की कार्यवाहियों की जरूरत है। समूचा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ अटैक के मूड में है। कांग्रेस, सपा, राजद, एनसीपी के शरद पवार, सीपीएम आदि विपक्षी दलों के नेताओं ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, तथा कहा है कि न प्रधानमंत्री को और न ही उनकी सरकार को ऐसा करना शोभा देता है।

शोषण से मुनाफा

क्या आप जानते हैं कि दुनिया में करीब 2.76 करोड़ लोग हर दिन जबरन मजदूरी करने को मजबूर हैं। मतलब कि प्रति हजार लोगों पर 3.5 लोग वो हैं जो आधुनिक दासता के इस दलदल में फंसे हैं। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी नई रिपोर्ट प्रोफिट्स एंड पावर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर में सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक जबरन मजदूरी के हर 10 में से 9 यानी करीब 86 फीसदी मामलों में निजी क्षेत्र की भूमिका है। वहीं राज्यों की हिस्सेदारी करीब 14 फीसदी है। हालांकि आईएलओ ने अपनी इस रिपोर्ट में सरकारी क्षेत्रों द्वारा जबरन श्रम से किए जा रहे अवैध मुनाफे को शामिल नहीं किया है।

आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि निजी क्षेत्र में जबरन मजदूरी में लगे 37 फीसदी यानी 63 लाख श्रमिक औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े थे। वहीं 32 फीसदी यानी 55 लाख के साथ सेवा क्षेत्र दूसरे स्थान पर था। इसी तरह कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 12 फीसदी थी। मतलब की 21 लाख मजदूर कृषि क्षेत्र से जुड़े थे। वहीं घरेलू कार्यों के क्षेत्र में यह आंकड़ा 14 लाख वहीं अन्य क्षेत्रों में 19 लाख (11 फीसदी) दर्ज किया गया है। वहीं यदि 2016 से 2021 के आंकड़ों पर गौर करें तो इस दौरान जबरन मजदूरी करने को मजबूर लोगों की संख्या में 27 लाख का इजाफा हुआ है। आईएलओ के मुताबिक जबरन मजदूरी या जबरन कराया जा रहा श्रम अपराध होने के साथ-साथ इंसानों के मौलिक अधिकारों का भी गंभीर रूप से हनन किया जा रहा है। इसका असर न केवल पीड़ित पर पड़ता है बल्कि सारे समाज को इसकी आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक निजी क्षेत्र को इस जबरन मजदूरी के चलते सालाना करीब 19.6 लाख करोड़ रुपए (23,600 करोड़ डॉलर) का अवैध मुनाफा हो रहा है। वहीं यदि 2014 के बाद से, देखें तो इस मुनाफे में 37 फीसदी का इजाफा हुआ है, जो करीब 6,400 करोड़ डॉलर है।

रिपोर्ट की मानें तो मुनाफे में हुई यह वृद्धि, जबरन श्रम में लगे पीड़ितों की संख्या में हुए इजाफे और अधिक मुनाफे के चलते हुई है। इस जबरन मजदूरी से सबसे अधिक होने वाले कुल वार्षिक मुनाफे को देखें तो इस मामले में यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र अव्वल है, जहां हर साल इससे 8,400 करोड़ डॉलर का मुनाफा हो रहा है। वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र 6,200 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं अमेरिका में 5,200 करोड़ डॉलर, अफ्रीका में 2,000 करोड़ डॉलर और अरब देशों में 1800 करोड़ डॉलर का मुनाफा हो रहा है। रिपोर्ट में जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि मौजूदा समय में तस्कर और अपराधी अब हर पीड़ित से औसतन करीब 10,000 डॉलर कमा रहे हैं, यह कमाई एक दशक पहले 8,269 डॉलर से कहीं अधिक है। वहीं यदि प्रति पीड़ित के लिहाज से देखें तो यूरोप और मध्य एशिया में सालाना सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। इसके बाद अरब देशों, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र का स्थान आता है।

आंकड़ों की माने तो दुनियाभर में जबरन श्रम से मुनाफे में हुई वृद्धि से यौन तस्कर प्रत्येक पीड़ित से औसतन 27 हजार डॉलर तक कमा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में यौन शोषण जबरन श्रम के सबसे आकर्षक रूप में उभरा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो जितने लोग जबरन श्रम का शिकार हैं उसमें से 27 फीसदी यौन शोषण के शिकार हैं। हालांकि जबरन मजदूरी से होने वाले कुल अवैध मुनाफे का 73 फीसदी से अधिक इन्हीं से कमाया जा रहा है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि यौन शोषण के बाद औद्योगिक श्रम के लिए मजबूर किए गए पीड़ितों से शोषक सालाना 3,500 करोड़ डॉलर का अवैध मुनाफा कमा रहा है। इसके बाद सेवा क्षेत्र जबरन मजदूरी के चलते 2,080 करोड़ डॉलर, जबकि कृषि क्षेत्र में यह शोषक वर्ग 500 करोड़ डॉलर (41,514 करोड़ रुपए) की चांदी काट रहा है। वहीं घरेलू कार्य के क्षेत्र में इन जबरन मजदूरों से सालाना 260 करोड़ डॉलर का फायदा लिया जा रहा है। देखा जाए तो यह वो मुनाफा है जो सही मायनों में मजदूरों को मिलना चाहिए लेकिन जबरन श्रम के दांव-पेंचों के चलते यह मुनाफा शोषण करने वालों की झोली में जा रहा है। रिपोर्ट अवैध मुनाफे पर अंकुश लगाने और अपराधियों को इसका दंड मिल सके इसे सुनिश्चित करने के लिए निवेश पर जोर देती है ताकि स्थिति में बदलाव लाया जा सके। इसके साथ ही रिपोर्ट में कानूनी ढांचे को मजबूत करने की बात भी कही गई है। इसी तरह जिन क्षेत्रों में इस तरह का जोखिम बहुत ज्यादा है वहां श्रम क्षेत्र के निरीक्षण का विस्तार करने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कानूनों को भी मजबूत करने की सिफारिश की गई है।

● **बृजेश साहू**

खुशहाली सूचकांक में भारत 126वें पायदान पर

संयुक्त राष्ट्र ने हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक, ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है पैसा और पावर आपको खुशहाल नहीं बनाता है। फिनलैंड ने चीन और अमेरिका को पछाड़ते हुए एक बार फिर से ऊंचा मकाम हासिल किया है। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे खुशहाल देशों में ज्यादातर देश यूरोपीय हैं। वहीं भारत की तुलना में पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल देश है। भारत 126वें स्थान पर है। वहीं, आर्थिक तंगी से जूझ रहा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सूची में 108वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन 143 देशों की खुशहाली मापने के लिए 6 मानकों पर सवाल तैयार किए गए थे। इनमें संबंधित देश के प्रति व्यक्ति की जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता और भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन के आधार पर रैंकिंग की गई। खास बात ये है कि फिनलैंड को लगातार सातवें साल ये मुकाम हासिल हुआ है। खुशहाली में उसने बड़े-बड़े देशों को पछाड़ा है। 10 सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नार्वे, लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्थान बनाए रखा। वहीं 10 नीचे के देशों में अफगानिस्तान, लेबनान, लिसोटी (साउथ अफ्रीकी देश), कांगो, जिम्बाब्वे, बोत्सोवाना, मलावी (ईस्ट अफ्रीकी देश), इस्वातिनी (अफ्रीकी देश) और जाम्बिया शामिल हैं।

कांग्रेस के पंच न्याय सिद्धांत को देखें तो ऐसा लगता है इसे कांग्रेस के नेताओं ने नहीं बल्कि कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों ने तैयार किया है। इसमें हसिया हथौड़ा यानी किसान मजदूर के साथ ओबीसी, एससी, एसटी को भी न्याय दिलाने की बात कही गई है। एक ओर अगर आप समाज को किसान, मजदूर और आदिवासी में बांट देते हैं तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अलग से जगह कहां बचती है? लेकिन यह विरोधाभाष कांग्रेस द्वारा जारी पंच न्याय सिद्धांत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

विपक्ष कर रहा आत्मघाती गोल

लोकसभा चुनाव में पहले दिन से भाजपा और मोदी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर प्रवेश के बाद से लोकसभा के चुनाव राष्ट्रपति प्रणाली की तरह हो गए हैं। मोदी एक लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। जब तक उनके सामने एक वैकल्पिक चेहरा नहीं होगा, तब तक विपक्ष का चांस ही दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष भले ही यह कहता रहे कि 1996 में कौन सा चेहरा था, या 1977 में कौन सा चेहरा था, तब भी तो जनता ने तख्ता पलट दिया था। तो इन दोनों वक्त की परिस्थितियों को समझना जरूरी है। 1977 का नतीजा आपातकाल के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया थी, और 1996 का नतीजा नरसिंह राव की भ्रष्ट सरकार और हिंदुत्व के उभार के कारण आया था। बाबरी ढांचा टूट चुका था, जिस कारण मुस्लिम वोटर कांग्रेस से नाराज था। एक तरफ मुस्लिमों ने कांग्रेस छोड़कर क्षेत्रीय पार्टियों का रूख कर लिया था। दूसरी तरफ हिंदू भाजपा की तरफ आकर्षित होने लगे थे। 1996 का नतीजा कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन किसी के पक्ष में नहीं था, इसलिए वह भारतीय राजनीति का सबसे कठिन दौर था, जब दो साल बाद ही चुनाव करवाने पड़े थे। 1984 से पहले के दौर को याद कीजिए, देश के दूरदराज के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी लोकप्रिय थीं। या 1964 से पहले का जमाना देख लीजिए जब जवाहर लाल नेहरू लोकप्रिय थे।

आज से 10 साल पहले तक दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में किसी से पूछते थे कि प्रधानमंत्री कौन हैं, तो जवाब मिलता था इंदिरा गांधी। जबकि इंदिरा गांधी की 30 साल पहले हत्या हो गई थी। भारतीय राजनीति में चेहरे का हमेशा महत्व रहा है। तमिलनाडु में एमजीआर और बाद में करुणानिधि या जयललिता, इसी तरह आंध्रप्रदेश में एनटीआर चेहरे ही थे, जो राजनीति में आते ही छा गए। विपक्ष के पास न चेहरा है, न 1977 और 1996 की तरह मुद्दा है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद कुछ समय के लिए एक बार अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के चेहरे थे। वाजपेयी के समय भी लेखक अखबारों में लिखते थे, वाजपेयी के बाद कौन। नेहरू, इंदिरा और वाजपेयी, इन तीनों के कार्यकाल में अखबारों और टेलीविजन की दुनिया में एक शब्द बहुत ही पॉपुलर हुआ था, वह शब्द था टीना फेक्टर। टीना का फुल फार्म है, देयर इज नो एल्टरनेटिव, यानी कोई विकल्प ही नहीं है।

अब नरेंद्र मोदी के लिए भी वही स्थिति पैदा हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव में मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। दस साल पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इसलिए बुरी तरह हार गई थी क्योंकि उनकी सरपरस्ती में चल रही मनमोहन सिंह सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़ दिए थे। अपने सहयोगी दलों के मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री

भाजपा का चुनावी दांव है सीएए

मोदी सरकार ने अपना वायदा निभाते हुए नागरिकता संशोधन कानून के नियम जारी कर दिए हैं। विपक्ष, खासकर तृणमूल कांग्रेस, ऐसा मानकर चल रहे थे कि 2020 के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए मुस्लिम आंदोलन से डरकर जैसे मोदी सरकार ने पिछले 4 साल में सीएए के नियम लागू नहीं किए, वैसे ही चुनावों तक उसे ठंडे बस्ते में डाले रखेगी। इस कानून का मुस्लिमों की ओर से विरोध इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर सताए गए हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाईयों को कानून में ढील देकर भारत की नागरिकता दी जा रही है, वैसे ही बांग्लादेश और म्यांमार से आए मुस्लिमों को भी नागरिकता दी जाए। जबकि भारत सरकार की नजर में बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, वहां मुसलमानों को धार्मिक आधार पर सताए जाने का कोई कारण ही नहीं है। जहां तक म्यांमार का सवाल है, तो वहां बांग्लादेशी मुसलमानों की हिंसक गतिविधियों के खिलाफ वहां के बौद्धों की प्रतिहिंसा के चलते उन्हें वहां से भागना पड़ा है, लेकिन क्योंकि वे मूल रूप से बांग्लादेशी हैं, इसलिए उन्हें वापस बांग्लादेश जाना चाहिए, न कि भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करनी चाहिए।

खुद कहते थे कि गठबंधन की राजनीति की कुछ मजबूरियां होती हैं। इसका मतलब यह था कि वह भ्रष्टाचार को अपनी सरकार की मजबूरी बता रहे थे। वहीं से परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा बना, जो आज 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। अपने दूसरे दौर के 5 सालों में मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई कि विपक्ष का कोई नेता वैकल्पिक चेहरा ही नहीं बन पाया। देश की आम जनता यह मानने लगी है कि परिवारवाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा तो है ही, भ्रष्टाचार की जड़ में भी परिवारवाद है।

नरेंद्र मोदी ने एक-एक कर विपक्ष के सभी नेताओं को अदालत में खड़े होकर जमानत लेने को मजबूर कर दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर पी. चिदंबरम तक सब भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर रिहा हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर रिहा हैं। ममता बनर्जी की कैबिनेट के दो मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। उनका भतीजा ईडी की पूछताछ के घेरे में है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के दो मंत्री भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में एक साल से भी ज्यादा समय से जेल में हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए हैं। केजरीवाल शराब घोटाले और जल प्राधिकरण घोटाले में ईडी की पूछताछ से बचते घूम रहे थे। ईडी के समन की तामील न करने के केस में खुद केजरीवाल जमानत पर रिहा थे। वहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का एक मंत्री भ्रष्टाचार में जेल की हवा खा चुका है, आप का एक सांसद भी शराब घोटाले में जेल में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सरकारी जमीन हड़पने और अवैध खदान के आरोपों में इस्तीफा देकर जेल में जाना पड़ा है। उनकी भाभी सीता सोरेन को रिश्वत मांगने के आरोप में दोषी पाया गया है। इसलिए विपक्ष जितना चाहे गठबंधन कर ले, विपक्ष के नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है।

राहुल गांधी को मोदी का विकल्प बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनमें कोई विजन ही दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें भारतीय संस्कृति, परंपराओं और भारतीय राजनीति की कोई समझ ही नहीं है। इसकी झलक बार-बार उनके भाषणों में दिखती है। नफरत की राजनीति से कोई भारतीय जनमानस में अपनी जगह नहीं बना सकता। राहुल गांधी की सारी राजनीति मोदी विरोध और उनसे नफरत पर टिकी है। भले ही उन्होंने मुंबई में अपनी दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन भाषण में कहा कि विपक्ष की राजनीति मोदी या भाजपा के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका कोई भाषण मोदी विरोध के बिना खत्म ही नहीं होता। उन्हें इतनी सी समझ नहीं है कि मोदी ने भारतीय वोटरों के मन में अपनी जगह नेहरू और इंदिरा गांधी जैसी बना ली है। उनका

कम्युनल पॉलिटिक्स का मुखौटा बनते राहुल गांधी

भारत की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों की कुछ खास मौजूदगी दिखाई नहीं देती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कम्युनिस्टों की कम्युनल पॉलिटिक्स का मुखौटा बने घूम रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर बिना वजह उन्होंने हिंदू धर्म में एक होती है शक्ति का उल्लेख करके उसे खत्म करने की बात कह दी। विवाद बढ़ा तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर सफाई दे दी कि वो नरेंद्र मोदी द्वारा इकट्ठी की जा रही शक्ति की बात कर रहे थे। अगर ऐसा ही था तो उन्होंने उसे हिंदू धर्म से क्यों जोड़ा, यह समझना कठिन है। असल में राहुल और प्रियंका के आसपास उनके कम्युनिस्ट सलाहकारों का घेरा है जिसके खिलाफ प्रमोद कृष्णम जैसे उनकी पार्टी के नेता ही सवाल उठा चुके हैं। ये कम्युनिस्ट सलाहकार ही इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संचालित कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पर कम्युनिस्टों का वैचारिक प्रभाव रहा है लेकिन जब से कम्युनिस्ट पार्टियों का भारत में पतन हुआ है, कांग्रेस नवोदित कामरेडों की शरणस्थली बन गई है। अब न सिर्फ कैडर के रूप में आईसा और एसएफआई के वर्कर कांग्रेस में पहुंच रहे हैं बल्कि वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी अब कम्युनिस्ट पार्टी में ही परिवर्तित हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टियां जिस विभाजनकारी राजनीति के चलते भारत में अप्रासंगिक हो गईं, अब कांग्रेस पार्टी भी उसी विभाजनकारी राजनीति को अपना चुकी है।

विरोध सिर्फ मुद्दों पर हो सकता है, लेकिन विपक्ष एक मुद्दा उठाकर दूसरे दिन उसे भूल जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे का कानूनी प्रावधान था, विपक्ष ने भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया, लेकिन उन्होंने खुद भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध ठहरा दिया है, तो विपक्ष भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जितनी भाजपा कटघरे में खड़ी है, उतनी ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और आम आदमी पार्टी कटघरे में है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड भी विपक्ष का सेल्फ गोल ही है।

राहुल गांधी हो या विपक्ष का कोई भी अन्य नेता, वे मोदी पर हमले करके सिर्फ सेल्फ गोल ही कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की रैली में लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के हिंदू होने और उनके परिवारहीन होने का बयान देकर सेल्फ गोल कर लिया था। अब राहुल गांधी ने यह कहकर अपने खिलाफ बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया कि उनका मुद्दा हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ है। वह अपनी बात को आसान शब्दों में समझा ही नहीं पाते, अलबत्ता हिंदू धर्म के बारे में अपने अल्पज्ञान के कारण हिंदुओं के आक्रोश और हंसी का पात्र बन जाते हैं। जिसका हिंदू धर्म के बारे में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जीवन पद्धति कहा है, उसका बोध ही नहीं है, वह भारत की 80 प्रतिशत हिंदू जनता का नेता कैसे बन सकता है।

मुंबई के अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि उनका विरोध भाजपा या मोदी से नहीं है, हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, उनका विरोध उस शक्ति के खिलाफ है। हिंदू धर्म में मां काली को शक्ति माना जाता है, मां दुर्गा को शक्ति माना जाता है, स्त्री को शक्ति माना जाता है। राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि वह क्या कहना चाहते हैं, और क्या कह रहे हैं। अपने नेता के अल्पज्ञान और विजन की कमी के कारण कांग्रेस खुद ही हतोत्साहित हो चुकी है। कांग्रेस चुनाव में कहीं लड़ती हुई दिखाई ही नहीं दे रही। मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, सभी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने ठीक समय पर कहा था कि लड़ाई तब दिखाई देगी, जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाराणसी में मोदी के सामने खड़े हों। लेकिन गांधी परिवार तो चुनाव लड़ने से ही भाग रहा है। और तो और सोनिया गांधी चुनावों से पहले ही राज्यसभा पहुंच गईं।

● **विपिन कंधारी**

चुनाव में पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है, दरअसल, ये आम धारणा है। लेकिन हकीकत में एक-एक वोट का हिसाब-किताब होता है। एक वोट के लिए कितना खर्च हो रहा है। सबका लेखा-जोखा रखा जाता है। ये आज की बात नहीं है, जब से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है तब से, आजादी के बाद से अबतक के हिसाब मौजूद हैं। हालांकि समय के बाद चुनाव के लिए खर्च भी बढ़े हैं और तरीके भी। पहले बैलट पेपर के जरिए वोटिंग होती थी, अब ईवीएम के जरिए मतदान हो रहा है। टेक्नोलॉजी में विस्तार की वजह से वोटिंग के तरीके बदले हैं।

दुनिया का सबसे महंगा चुनाव

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में भी लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो गया है। मुख्य चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। 18वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में किया जाएगा। वहीं, मतगणना 4 जून को की जाएगी। अब आम चुनाव कराने में हजारों-हजार करोड़ का खर्च आता है। ये तो सिर्फ चुनाव आयोग का खर्च है। लेकिन अगर इसमें राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के खर्च को भी जोड़ दिया जाए, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बार आम चुनाव में 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का अब तक का सबसे महंगा चुनाव होगा। इतना ही नहीं, हर पांच साल में चुनावी खर्च दोगुना होता जा रहा है। 2019 के चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जबकि, इससे पहले 2014 में लगभग 30 हजार करोड़ के खर्च की बात कही जाती है।

दरअसल, चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार पानी की तरह पैसा बहाते हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की तो एक लिमिट तय कर रखी है, लेकिन पार्टियों पर कोई पाबंदी नहीं है। यही वजह है कि अब भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होते जा रहे हैं। बीते कुछ आम चुनावों में जितना खर्च हुआ है, वो कई देशों की जीडीपी के बराबर है। जानकारी के अनुसार राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज्यादा खर्च तीन चीजों पर होता है। पहला- पब्लिसिटी। दूसरा- उम्मीदवारों पर। और तीसरा- ट्रैवलिंग पर। आंकड़ों पर नजर डालें, तो शुरू के छह आम चुनावों में प्रति मतदाता लागत एक रुपए से भी कम थी। मगर, बढ़ती महंगाई और रुपए के कमजोर होने से हर बार चुनाव के खर्च में बेतहाशा वृद्धि होती है। चुनाव आयोग हर साल मतदाता जागरूकता अभियान, वोटर कार्ड बनाने से लेकर ईवीएम के रखरखाव पर बहुत खर्च करता है। 2014 में पहली बार मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) का उपयोग किया गया, इस वजह से भी लागत में वृद्धि हुई। लोकसभा चुनाव पर होने वाला पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने का खर्च संबंधित राज्य सरकारों की ओर से वहन किया जाता है।

चुनाव कराने का पूरा खर्च सरकारें उठाती हैं। अगर लोकसभा चुनाव हैं, तो सारा खर्च केंद्र

कौन उठाता है लोकसभा चुनाव का खर्च?

देश में आम चुनाव का खर्च केंद्र सरकार उठाती है। इसमें इलेक्शन कमीशन के प्रशासनिक कामकाज से लेकर, चुनाव में सिक्योरिटी, पोलिंग बूथ बनाने, ईवीएम मशीन खरीदने, मतदाताओं को जागरूक करने और वोटर आईडी कार्ड बनाने जैसे खर्चे शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक साल-दर-साल ईवीएम खरीद के खर्चे में भी इजाफा हुआ है। 2019-20 के बजट में ईवीएम खरीदने और मेंटेनेंस के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। वहीं 2023-24 के बजट में यह राशि बढ़कर 1891.8 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में चुनाव खर्च के लिए 2442.85 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इसमें 1000 करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव में खर्च किए जाएंगे। ईवीएम के लिए बजटीय आवंटन 34.84 करोड़ रुपए है। साल 2014 में चुनाव आयोग ने 3.82 लाख बैलट पेपर और 2.5 लाख मशीन खरीदी थी। एक ईवीएम की जीवन अवधि करीब 15 साल होती है। साल 2018 और 2013 में चुनाव आयोग ने 13 लाख बैलट यूनिट और 10 लाख कंट्रोल यूनिट और खरीदी थी। दरअसल चुनाव से जुड़े खर्चे चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय दोनों को दिए जाते हैं। ईवीएम मशीन की खरीद जैसे चुनावी खर्च कानून मंत्रालय के बजट में आते हैं।

सरकार उठाएगी। विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकारें करती हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ हैं तो फिर खर्च केंद्र और राज्य में बंट जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले आम चुनाव में 10.45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2004 के चुनाव में पहली बार खर्च हजार करोड़ रुपए के पार पहुंचा। उस चुनाव में 1,016 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2009 में 1,115 करोड़ और 2014 में 3,870 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 2019 के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि, माना जाता है कि 2019 में चुनाव आयोग ने 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया होगा।

एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने 6,405 करोड़ रुपए का फंड जुटाया था। और इसमें 2,591 करोड़ रुपए खर्च किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, सात राष्ट्रीय पार्टियों ने बीते चुनाव में 5,544 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया था। इसमें से अकेले भाजपा को 4,057 करोड़ रुपए मिले थे। कांग्रेस को 1,167 करोड़ रुपए का फंड मिला था। 2019 में भाजपा ने 1,142 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जबकि, कांग्रेस ने 626 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया था। 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीती थीं। इस हिसाब से देखा जाए तो भाजपा को एक सीट औसतन पौने चार करोड़ रुपए में पड़ी थी। कांग्रेस 52 सीट ही जीत सकी थी। लिहाजा, एक सीट जीतने पर उसका औसतन 12 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ था।

चुनाव आयोग ये सारा पैसा चुनावी प्रक्रिया पर करती है। चुनाव के दौरान ईवीएम खरीदने, सुरक्षाबलों की तैनाती करने और चुनावी सामग्री खरीदने जैसी चीजों पर पैसा खर्च होता है। पिछले साल कानून मंत्रालय ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त फंड मांगा था। चुनाव आयोग के अलावा राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार अच्छा-खासा खर्च करती हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए 95 लाख रुपए की सीमा तय कर रखी है। यानी, एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों के स्टार प्रचारक दिनभर में ही कई-कई रैलियां करते हैं। इसके लिए हेलिकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। 2019 में अकेले भाजपा ने ही ट्रैवलिंग पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए खर्च किए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने लगभग 1,500 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पर किए थे। इनमें से सात राष्ट्रीय पार्टियों ने 1,223 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया था। पब्लिसिटी पर सबसे ज्यादा खर्च भाजपा और कांग्रेस ने किया था। भाजपा ने 650 करोड़ तो कांग्रेस ने 476 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया था। अनुमान है कि इस साल चुनाव में 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से सिर्फ 20 प्रतिशत ही चुनाव आयोग का खर्च होगा। बाकी सारा खर्चा राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार करेंगी। ये खर्च कितना ज्यादा है, इसे इस तरह समझ सकते हैं कि सरकार 80 करोड़ गरीबों को लगभग 8 महीने तक फ्री राशन बांट सकती है। केंद्र सरकार की ओर से अभी हर महीने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। इस पर हर तीन महीने में लगभग 46 हजार करोड़ रुपए का खर्च आता है।

साल-दर-साल खर्च

चुनाव	कुल खर्च (करोड़ में)	मतदाता	प्रति मतदाता खर्च (रू. में)
1952	10.45	17,32,12,343	0.6
1957	5.90	19,36,52,179	0.3
1962	7.32	21,63,61,569	0.3
1967	10.80	25,02,07,401	0.4
1971	11.61	27,41,89,132	0.4
1977	23.04	32,11,74,327	0.7
1980	54.77	35,62,05,329	1.5
1984	81.51	40,03,75,333	2.0
1989	154.22	49,89,06,129	3.1
1991	359.1	5,11,533,598	7.0
1996	597.34	59,25,72,288	10.1
1998	666.22	60,58,80,192	11.1
1999	947.68	61,95,36,847	15.3
2004	1,016.08	67,14,87,930	15.1
2009	1,114.38	71,69,85,101	15.5
2014	3,870.34	83,40,82,814	46.4
2019	12,000	91,19,50,734	131.58
2024	24,000	98,66,00,000	243.25

मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। इस साल चुनाव के लिए 1.48 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं रखी गई हैं। इसके अलावा, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं के लिए 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही, इस साल पोस्टल बैलेट के जरिए 19.1 लाख सेवा कार्मिक और अन्य मतदाता वोट करेंगे, जो चुनावी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। मालूम हो कि मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने खास व्यवस्था की है। पहली बार ऐसा होगा कि मतदाताओं का वोट लेने के लिए चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मी घर भी जाएंगे। दरअसल, 85 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए ड्यूटी पर तैनात कर्मी उनके घर जाकर वोट लेंगे। चुनाव संबंधी कार्यों के लिए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित कुल 4.5 लाख कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनमें से 1.67 लाख से अधिक मतदान अधिकारी हैं। इसके अलावा, चुनाव के दौरान 1.2 लाख से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

लोकसभा चुनाव 2024 में एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। इनमें चुनाव प्रचार, वाहन, खाना-पानी, टेंट और बैनर-पोस्टर तक शामिल है। चुनाव के दौरान गायकों और सोशल मीडिया पर दिए गए विज्ञापन का भी हिसाब होता है। फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए ये रकम प्रति उम्मीदवार के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए निर्धारित है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी खर्च अधिकतम 95 लाख रुपए, 2014 के लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए, 2009 के चुनाव में 25 लाख रुपए, और 2004 के लोकसभा चुनाव में 25 लाख रुपए खर्च का दायरा था।

● **इन्द्र कुमार**

तैयारी के साथ दावेदारी...

देशभर में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दोनों बड़ी पार्टियों ने भी दावे करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो भाजपा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी जबकि भाजपा का दावा है कि वो सभी 11 सीटें जीतेगी। दोनों पार्टियों में किसकी पार्टी के दावे में ज्यादा दम है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा लेकिन फिलहाल हम 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों के रिजल्ट का विश्लेषण करें तो जनता के मूड का पता चल सकता है। 3 दिसंबर 2023 को आए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को हम लोकसभा वार देखें तो पाएंगे कि भाजपा 8 लोकसभा सीट पर और कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर आगे रही है। इन नतीजों पर नजर डालने से एक अंदाजा लगाया जा सकता है।

2019 के लोकसभा चुनाव में, भाजपा ने 50.7 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 9 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 40.9 प्रतिशत वोट शेयर प्राप्त करके दो सीटों पर जीत दर्ज की। भगवा पार्टी ने 2014 के आम चुनाव में 48.7 प्रतिशत वोट शेयर के साथ दस सीटें हासिल की थीं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें-राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में मतदान हुए थे। चुनाव आयोग ने राज्य में 11 अप्रैल 2019, 18 अप्रैल 2019 और 23 अप्रैल 2019 को तीन चरणों में मतदान की घोषणा की थी।

सबसे पहले बात रायपुर लोकसभा सीट की। ये सीट राज्य बनने से पहले से ही भाजपा का गढ़ बन चुकी है। इस लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें से 8 पर भाजपा का कब्जा है और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनाव में मिले वोट को जोड़ लें तो भाजपा रायपुर लोकसभा सीट पर 2 लाख 44 हजार 222 वोटों से आगे रही है। दुर्ग लोकसभा सीट पर भी 9 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से भाजपा ने 7 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थीं। यहां कांग्रेस की ओर से पाटन सीट पर भूपेश बघेल और भिलाई सीट पर देवेंद्र यादव ने जीत दर्ज की थी। इस लोकसभा सीट पर सभी विधानसभा के परिणामों के मुताबिक भाजपा 1 लाख 39 हजार 196 वोटों से आगे रही है। बिलासपुर लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से छह पर भाजपा और दो पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस लिहाज से भाजपा बिलासपुर लोकसभा सीट पर 99 हजार 345 सीटों पर आगे है।

राजनांदगांव लोकसभा सीट पर थोड़ा ट्विस्ट है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है तो भाजपा ने मौजूदा सांसद संतोष पांडेय को रिपीट किया है। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट आती हैं। 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने 5 सीटों पर और भाजपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन कुल वोटों के मामले में यहां भाजपा 1 लाख 11 हजार 966 मतों से कांग्रेस से आगे है। सरगुजा सीट में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं जहां भाजपा ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर 1 लाख 57 हजार 873 है। बस्तर लोकसभा सीट में विधानसभा की आठ सीटें हैं। जिसमें से भाजपा ने छह सीट जीती हैं वहीं कांग्रेस महज दो सीट जीत सकी थी। यहां वोटों के अंतर से भाजपा 81 हजार 646 मतों से आगे है। कोरबा लोकसभा एक हाईप्रोफाइल सीट है। इस सीट से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत सांसद हैं और भाजपा ने यहां से सरोज पांडेय को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि विधानसभा के परिणामों के अनुसार भाजपा को बढ़त हासिल है। यहां की 8 लोकसभा सीटों में 6 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। यहां भाजपा 61 हजार 208 वोटों से कांग्रेस से आगे है।

अब बात राज्य में कांग्रेस को बढ़त दिलाने वाली सीटों की। सबसे पहले जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर नजर डालते हैं। ये सीट एससी सीट है। पिछले विधानसभा चुनावों में इसकी सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। यहां जीत के अंतर को देखें तो कांग्रेस 1 लाख 17 हजार 196 मतों से भाजपा से आगे है। कांकेर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां की 8 विधानसभा सीटों में से 5 में कांग्रेस और 3 पर भाजपा के विधायक हैं। यहां कांग्रेस कुल 82 हजार 300 मतों से भाजपा से आगे है। दूसरी तरफ महासमुंद लोकसभा सीट के परिणामों में थोड़ा ट्विस्ट मिलता है। यहां की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने पांच और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं लेकिन कुल मतों के मामले में कांग्रेस यहां भाजपा से 9 हजार 483 वोटों से आगे रही है। कांग्रेस के बड़े नेता चरणदास महंत का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है और तीन और मिला दें तो राज्य में 5 सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

पीएम आवास हो सकते हैं गेमचेंजर

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। राज्य में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के 18 लाख गरीबों के मकान निर्माण के काम में तेजी ला दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में प्रदेश के 16 लाख गरीब आवास से इसलिए वंचित हो गए थे, क्योंकि राज्यांश की राशि नहीं मिल पाई थी। आवास नहीं दे पाने से व्यथित होकर भूपेश कैबिनेट के मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से त्याग पत्र तक दे दिया था। इसके बाद भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती रही। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने सड़क से लेकर सदन तक आवासहीनों का मुद्दा उठाया था और विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की जीत के लिए यह बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। विधानसभा की 90 सीटों में से 54 पर जीत हासिल कर भाजपा ने भूपेश सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट हासिल हुई। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से पिछली बार भाजपा ने 9 और कांग्रेस ने 2 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा सभी 11 सीटों को जीतने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है।

एनसीपी में बगावत से किसको लाभ?

कई दलों का अस्तित्व खतरे में

सबका साथ-सबका विकास का नरेंद्र मोदी का नारा वास्तविकता में शिवसेना के गुटों पर फिट बैठता है क्योंकि अकेले ये दोनों गुट इतने कमजोर हो चुके हैं कि चुनाव में उतरना इनके अस्तित्व को समाप्त कर देगा। फिर राज ठाकरे का भाजपा के साथ आना भी दोनों गुटों को परेशान करेगा। राज ठाकरे की मनसे भले ही राजनीतिक रूप से अभी इतनी सक्षम न हो किंतु राज ठाकरे का अपना व्यक्तित्व है जिससे उनकी क्षमताओं को नकारा नहीं जा सकता। इन परिस्थितियों में सर्वाधिक लाभ भाजपा को हुआ है क्योंकि वह छोटे भाई की भूमिका से निकलकर बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और बाला साहब ठाकरे की विरासत के निर्णायक दौर में उसके अपने हित छुपे हैं।

लोकतंत्र की पिच पर आम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अबकी बार 400 पार का नारा आम जनमानस के दिमाग में फिट करके मनोवैज्ञानिक बढ़त बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस में चुनाव लड़ने योग्य उम्मीदवारों का टोटा पड़ रहा है। इन सबके बीच 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर है। 2014 के आम चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना के साथ गठबंधन में 23 सीटें जीती थीं जबकि शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस मात्र 2 सीटें जीत पाई थी जबकि शरद पवार की एनसीपी ने 4 सीटों पर परचम लहराया था। 2019 के आम चुनाव में एक बार पुन: भाजपा और शिवसेना गठबंधन ने क्रमश: 23 और 18 सीटें जीतीं। एनसीपी भी 4 सीटों को बचाने में कामयाब रही जबकि कांग्रेस 2 सीटों में से 1 गंवाकर और सिमट गई। उसे विदर्भ की एकमात्र चंद्रपुर सीट से संतोष करना पड़ा जबकि 2014 में कांग्रेस ने मराठवाड़ा में 2 सीटें, नांदेड और हिंगोली पाई थीं।

वर्तमान में मराठवाड़ा के दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भगवा लहर पर सवार होकर राज्यसभा का टिकट कटा चुके हैं। यानी जिस मराठवाड़ा में अशोक चव्हाण कांग्रेस की लाज बचाते थे, उनका भी साथ अब कांग्रेस के पास नहीं है। हालांकि साथ तो अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे भी नहीं हैं और शरद पवार तथा अजित पवार की राहें भी जुदा हो चुकी हैं। शिंदे और अजित अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं वहीं शरद पवार अब भी बची-खुची ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। वहीं अब राज ठाकरे भी बहती गंगा में हाथ धोने के इरादे से भाजपा गठबंधन का हिस्सा बनने की मंशा से दिल्ली दरबार के चक्कर काट रहे हैं। गोयाकि महाराष्ट्र का राजनीतिक सर्कस अब अपने चरम पर है और सभी अपने लाभ और हानि का आंकलन कर रहे हैं। अब चुनाव परिणाम ही बताएगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 1.5 प्रतिशत वोट लाने वाली राज ठाकरे की मनसे के साथ आने से भाजपा को कितना और क्या लाभ होगा? हां, भाजपा यदि हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर खेलना चाहती है तो मनसे को आगे करके वह अपने मन की कर सकेगी। वहीं मनसे को भाजपा के माध्यम से अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने का अवसर मिलेगा किंतु इसका शिंदे गुट की शिवसेना पर क्या असर होगा, इसका अनुमान लगा पाना अभी कठिन है।

हालांकि इन सभी कवायदों के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी भी नहीं सुलझा है जिसके कारण महाराष्ट्र की जनता भी भ्रमित है। 6 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने जब अजित पवार गुट को असली एनसीपी घोषित किया तो अपने राजनीतिक दांव-पेंच से इंदिरा गांधी तक को चौंकाने वाले शरद पवार निश्चित रूप से राजनीति में अपने ही भतीजे से हार गए। एक समय जिन परिस्थितियों में उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी तोड़कर एनसीपी बनाई थी, उन्हीं परिस्थितियों में उनके भतीजे ने उन्हें किनारे करके चाचा को राजनीतिक वनवास पर भेज दिया है।

चूंकि इस समय देश में मोदी लहर की चर्चाएं आम हैं तो अजित का भाजपा गठबंधन में होना उन्हें लाभ का सौदा दिख रहा है। लाभ की संभावना तो भाजपा भी जता रही है क्योंकि मराठा नेतृत्व के न होने से जो हानि उसे महाराष्ट्र में उठानी पड़ती थी, इस बार उसकी भरपाई होने की बात की जा रही है। पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे, बारामती, सतारा, मढ़ा, कोल्हापुर जैसे एनसीपी के गढ़ों में यदि अजित पवार का जादू चल जाता है तो भाजपा की मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाएगी। अजित पवार के सहयोग से ही भाजपा इन लोकसभा सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लेगी। हालांकि पुणे से अभी भाजपा सांसद है किंतु यह लोकसभा भी एनसीपी के प्रभाव क्षेत्र वाली मानी जाती है। वहीं शरद पवार के लिए यह आम चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव हो सकता है और भतीजे द्वारा पार्टी पर कब्जे की सहानुभूति उन्हें कथित राजनीतिक वनवास से निकाल सकती है जिसका सीधा लाभ इंडिया एलायंस को होगा। कांग्रेस के नीति-नियंता भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अजित पवार के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। साथ ही वे शरद पवार के माध्यम से सहानुभूति कार्ड भी खेल रहे हैं। इस कवायद में भाजपा-कांग्रेस भले ही अपना भला कर लें, सर्वाधिक नुकसान पवार परिवार का होगा क्योंकि उनकी जुदा राहें मतदाताओं को भी जुदा कर देंगी। अब जबकि शरद पवार गुट को चुनाव आयोग से इलेक्शन सिंबल मिल गया है तो शरद गुट मजबूती से मैदान में उतर चुका है। वहीं शरद गुट को अजित पवार के भाई श्रीनिवास का भी साथ मिला है जिन्होंने शरद पवार को बूढ़ा है, कमजोर नहीं... कहते हुए अजित के समक्ष परेशानियां पैदा कर दी हैं। संभवत: अब यही नारा शरद गुट के लिए संजीवनी का काम करेगा।

महाराष्ट्र में यह चुनाव बाल ठाकरे के असली वारिस को चुनने का भी चुनाव है। बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे की परिवार से जुदा हुई राहों से शिवसेना का उतना नुकसान नहीं हुआ था जितना एकनाथ शिंदे के साथ छोड़ने से हुआ है। वर्तमान में उद्धव ठाकरे के समक्ष परिवार की राजनीतिक विचारधारा को बचाने के साथ ही कांग्रेस से गठबंधन क्यों के प्रश्न का उत्तर देना कठिन होगा। हालांकि मराठी मानुष के नाम पर सहानुभूति उन्हें भी मिलेगी, किंतु इससे वोटों में कितनी तब्दील होगी कहना कठिन है। शिंदे-ठाकरे के साथ भाजपा के ऊपर बाला साहब की विरासत के टुकड़े करने का जो दाग लगा है, आम चुनाव उसकी भी सफाई देगा। सत्ता के लिए विचारधारा को तिलांजलि देना या सत्ता के लिए परिवार को छोड़ देना; दोनों का फैसला जनता करेगी। यह भी तय होगा कि असली कौन और नकली कौन? जो शिवसेना पूर्व में भाजपा के साथ गठबंधन करके सभी सीटों पर अपना परचम फहराती थी, अब एक-एक सीट के लिए दोनों गुट भाजपा-कांग्रेस के ऊपर निर्भर हैं।

● **बिन्दु माथुर**

दुविधा में पायलट

राजनीतिक कलह की आग में जब भी शोले भड़कते हैं, तो शिकवा-शिकायतों की चिंगारियां उड़े बिना नहीं रहतीं। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर भारी भीड़ जुटाकर चुपके से अपना दर्द साझा करते हुए सचिन पायलट ने अपना दावा फिर दोहरा दिया कि पार्टी के लिए अपना सब कुछ झोंकने के बावजूद मुझे क्या मिला? जब उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तभी अंदेशों के बादल उठने लगे थे कि मुख्यमंत्री न बन पाने की खलिश उन्हें बेचैन किए रहेगी। कुछ हफ्तों बाद ही उनके और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तनाव की खबरें रिसने लगीं।

इन अफवाहों को बल तब मिला, जब पायलट ने गहलोत के कामकाज को लेकर बेसिर-पैर की बातें शुरू कर दीं। असली सत्ता अपने पास नहीं होने का संताप पायलट को भीतर-ही-भीतर कचोटता रहा। नतीजतन पायलट अपनी कुर्सी के ही कैदी बनकर रह गए। पायलट लाख चाहें भी, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बिना कोई संघर्ष किए छोटी-सी उम्र में ही उन्होंने सांसदी और केंद्रीय मंत्री की पाग पहनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री तक का ताज भी पहन लिया। गहलोत तो इस बात पर तंज कसने से भी नहीं चूके कि बिना संघर्ष के ही जब पायलट को इतना कुछ मिला, तो उन्हें इसकी कद्र नहीं हुई। लेकिन उनकी सियासी जन्म कुंडली का इससे ज्यादा दुखद वृतांत क्या हो सकता है कि पार्टी के मुखिया पद को ही उन्होंने लांछित कर दिया। विश्लेषकों का कहना है कि जब पार्टी का मुखिया ही लक्ष्मण रेखा लांघ जाए, तो बाकी क्या रह जाता है? ताकत दिखाने की बाजीगरी में पासे उलटे पड़ने के बाद सचिन एक बार फिर अपने समर्थकों को साथ लेकर पिछला रुतबा और ओहदा पाने के लिए घमासान में उलझे हैं। सचिन पायलट समर्थक पंजाब का उदाहरण देते हुए जोश से बोलते हैं कि जब वहां (पंजाब में) कार्यवाही हो गई, तो राजस्थान में टालमटोल क्यों? लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों ने पायलट खेमे पर हमलावर होते हुए दो-टूक कह दिया कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की और सरकार गिराने की कोशिश की, वे किस हक से हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं?

विश्लेषकों का कहना है कि पायलट ने जिस तरह की मनमानी की, उससे पनपा तनाव अब शायद ही कम हो सके। वजह साफ है कि हर रोज कोई-न-कोई नेता आग में घी डालने वाली बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहा। तेवर जितेंद्र सिंह ने भी दिखाए कि पार्टी हाईकमान ने पायलट से जो वादे किए हैं, उन्हें निभाया जाना चाहिए। प्रश्न है कि पायलट अपने 5 से 6 विधायकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इस घमासान के चलते जितिन प्रसाद की भाजपा में उड़ान से भी शोले भड़के। लेकिन यह शोले जल्द ही राख में तब्दील हो गए। असल में मोदी सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो मंत्री पद से नवाज दिया; लेकिन जितिन प्रसाद देखते ही रह गए। सूत्रों का संकेत है कि पायलट को मनचाहा पद मिल पाना कतई संभव नहीं है। जबकि समझा जाता है कि उन्हें पार्टी का महासचिव बनाकर किसी प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है। हालात जो भी हों, पायलट की इच्छा शांत नहीं हो रही है और भौहें तनी हुई हैं। राजनीतिक सूत्रों की मानें, तो पायलट के आंगन में बड़े दावों वाला एक खेल खेला जा रहा है। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में पायलट फिसलकर भाजपा के आंगन में जा गिरें, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। क्योंकि सियासी खेल में रिश्तों के नियम तय नहीं होते। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। भाजपा की तरह कांग्रेस में भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकने से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के गढ़ दौसा में उनके करीबी युवा नेता नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने की ताल ठोककर कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा दी है। मीणा के चुनाव लड़ने की घोषणा से पार्टी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। माना जा रहा है कि अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं तो, इसका सीधा-सीधा नुकसान कांग्रेस को भुगतना होगा। ऐसे में कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल करते हुए नरेश मीणा को मनाना आवश्यक हो गया हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकने वाले नेता नरेश मीणा ने कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों की टेंशन बढ़ा रखी है। नरेश मीणा ने 27 मार्च को नामांकन रैली भी निकाली। साथ ही कांग्रेसी नेताओं पर भी नरेश मीणा ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि मुझे कांग्रेस में ले लो, लेकिन राजस्थान के नेता सिर्फ टालमटोल कर रहे हैं। नरेश मीणा ने कहा कि नेताओं के पास ही ठेका है कि उनके परिवार और उनके बच्चे ही चुनाव लड़ें और मंत्री बनें। दौसा को राजेश पायलट, किरोड़ी लाल और नवल किशोर जैसे नेताओं की जरूरत है। मैंने मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका के लिए भी बड़ी मेहनत की थी और सबके लिए करता आया हूं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

पायलट की प्रतिष्ठा लगी है दांव पर

आम चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट अभी टोंक से विधायक हैं। टोंक-सवाईमाधोपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस हरीश चंद्र मीना को उम्मीदवार घोषित कर रखा है। राजस्थान में 2024 भारतीय आम चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की प्रतिष्ठा टोंक की बजाय दौसा में दांव पर लगी है। दौसा सचिन पायलट को विरासत में मिली सीट है। यहां सचिन पायलट के समर्थक भी बड़ी संख्या में हैं। दरअसल, दौसा सीट से सचिन पायलट ही नहीं बल्कि उनके पिता राजेश पायलट व माता रमा पायलट भी सांसद रहे हैं। साल 1991 से 1999 पिता राजेश पायलट चार बार दौसा सांसद चुने गए, जबकि साल 2000 में रमा पायलट व साल 2004 में सचिन पायलट दौसा सांसद बने। दौसा सीट को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस नेता नरेश मीना समेत राजनीति के कई जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में दौसा सीट की टिकट सचिन पायलट के हाथ में है। वे चाहेंगे उसे ही टिकट मिलेगी। हालांकि यह बात अलग है कि कांग्रेस 2004 के बाद अभी तक दौसा में नहीं जीती है।

बाहुबलियों की कमजोर होती पकड़

उप्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी को पूरी करते दिख रहे हैं। इस बीच वैसे नेताओं की चर्चा शुरू हो गई है, जिन्होंने उप्र की राजनीति को अपने स्तर पर खूब कंट्रोल किया। यह उप्र की सियासत के बाहुबली कहलाए। दरअसल, प्रदेश में बाहुबलियों के जोर पर राजनीतिक दलों ने चुनाव परिणाम तक को नियंत्रित किया। वोटिंग के दौरान बाहुबलियों के जोर पर क्षेत्र के चुनाव परिणाम को नियंत्रित करने की नीति बनाई गई। बाहुबलियों को पार्टियों की ओर से संरक्षण दिया गया। स्थिति तब विकट हुई, जब बाहुबलियों ने खुद राजनीति में एंट्री मार ली। अब वे सरकार बनाने से लेकर मंत्री बनाने तक को कंट्रोल करने लगे। कई बाहुबलियों ने सियासत की जमीन पर भी अपना सिक्का खूब चलाया। लेकिन, वक्त के साथ बाहुबलियों की सियासत पर पकड़ कमजोर होती गई। आज के समय में प्रदेश की सियासत में बाहुबलियों का कुछ जोर दिखता है। वहीं, बड़े स्तर पर बाहुबलियों को सत्ता के किनारे लगाने में सफलता मिलती दिखी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2021 में आए आदेश ने बड़ी भूमिका निभाई।

अतीक अहमद ने एक समय पूर्वांचल की राजनीति को कंट्रोल किया। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनाने के बाद अतीक अहमद ने राजनीति में कदम रखा। 80 के दशक में अपराध की दुनिया में सिक्का जमा चुका अतीक अहमद अपने रुख में बदलाव करने लगा। 1989 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनावी मैदान में उतरे अतीक ने अपने बाहुबल का दम दिखाया। वह चुनावी जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। इसके करीब तीन दशक तक उसकी राजनीति प्रयागराज में गरमाती रही। उप्र के प्रतापगढ़ जिले में एकमात्र बाहुबली हैं, उनका नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है। कहते हैं, जहां से कुंडा की सीमा शुरू होती है, वहां से राज्य सरकार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा इसलिए कि यहां सब कुछ राजा भैया की मर्जी से चलता है। अपराध भी और न्याय भी। राजा भैया से जुड़ी अपराध की कहानियां यहां खूब सुनी और सुनाई जाती हैं।

मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है। उसने जेल से बाहर और जेल में रहते हुए पूर्वांचल से लेकर उप्र की राजनीति को नियंत्रित किया। मुख्तार अंसारी एक प्रतिष्ठित परिवार से आता था, लेकिन वह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा डॉन बन गया। धनंजय सिंह को जौनपुर में रॉबिनहुड के तौर पर माना जाता रहा है। एक समय धनंजय को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया गया। एनकाउंटर में कथित तौर पर मार गिराए जाने वाले धनंजय सिंह ने प्रयागराज में सरेंडर कर सबको चौंका दिया था। छात्र राजनीति से अपना प्रभुत्व जमाने वाले धनंजय सिंह ने एक समय वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बीच आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। कई पार्टियों में रहा। विधायक से लेकर सांसद तक बनने में सफलता दर्ज की। 1980 तक एक नाम विजय मिश्रा का केवल इस कारण पहचाना जाता था, वह था पेट्रोल पंप के संचालक का। वे ट्रक चलवा रहे थे। हालांकि, क्षेत्र में उनकी पहचान उनके कारनामों से होने लगी। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने विजय मिश्रा को राजनीति की राह दिखाई। ज्ञानपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे और ब्लॉक प्रमुख के पद पर उतरे। इसके बाद राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ता गया। मुलायम सिंह यादव के खास बन गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितना क्षेत्र में रहते हैं, उससे अधिक समय जेल में। हालांकि, प्रभाव इतना कि किसी भी पार्टी से आ जाएं, चुनाव जीत जाते हैं। विजय मिश्रा को कभी मुलायम अपने बेटे की तरह मानते थे।

पूर्वांचल की बादशाहत में एक बड़ा नाम ब्रजेश सिंह का रहा है। मुख्तार अंसारी को अपराध की दुनिया में सीधी चुनौती ब्रजेश सिंह से मिली। ब्रजेश सिंह की जिंदगी में ट्रेजडी, क्राइम, इमोशन, ड्रामा सब है। गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी को अपराध की दुनिया में एक अलग स्थान हासिल है। कहते हैं कि उनके गुर्गे ऐलान करते थे कि आज घर से नहीं निकलना, गोलियां चलेंगी, लाशें गिरेंगी। उप्र की राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत की और फिर उसे स्थापित किया। माफिया से माननीय और फिर मंत्री बन गए। चुनाव हारे तो विरासत बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंप दी। पिछले दिनों उनकी मौत हो गई। डीपी यादव को दूध से लेकर दारू तक अधिकार के लिए जाना जाता है। उनकी गिनती उप्र के बाहुबली नेताओं में की जाती है। वे घर से दूध बेचने निकले थे और देश के सबसे बड़े शराब माफिया बन गए। पार्टियों ने बुला-बुलाकर विधायक-सांसद और मंत्री बनाया। उप्र के बाहुबली नेताओं में अमरमणि त्रिपाठी का नाम आता है। वे लंबे समय तक लव-सेक्स और मर्डर के आरोप में जेल में बंद रहे। कवियत्री मधुमिता हत्याकांड ने इस बाहुबली नेता के राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगा दिया।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

अपराधियों ने कंट्रोल की राजनीति

राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता जताई। इसके बाद कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी। पार्टी के मेन पेज पर एक कैप्शन होगा। इसमें लिखा होना है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के मोबाइल एप पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी को रखे जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग से सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई है। सोशल मीडिया, वेबसाइट, टीवी विज्ञापन, प्राइम टाइम डिबेट, पंपलेट के जरिए लोगों को जागरूक किए जाने का आदेश दिया है। राजनीति में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर राजनीतिक दल इस आदेश का पालन नहीं कराते हैं तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में जानकारी दे। कम प्रसार वाले अखबारों की जगह अधिक प्रसार वाले न्यूजपेपर और मीडिया चैनल पर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी जाए।

बड़े भाई की भूमिका में आई भाजपा

बिहार में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ सोमवार को सीटों का बंटवारा कर लिया। सीटों के बंटवारे में नीतीश की पार्टी जदयू को एक सीट कम देकर भाजपा ने यह बता दिया कि बिहार में अब बड़े भाई की भूमिका भाजपा निभाएगी। ठीक पांच वर्ष पूर्व 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश को बड़ा भाई मानकर भाजपा ने अपनी पांच सीटों वाल्मीकिनगर, झंझारपुर, सीवान, गोपालगंज और गया की कुर्बानी दी थी। लेकिन अब 2024 में जेडीयू से एक सीट ज्यादा लेकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश हों लेकिन बिहार में सरकार और गठबंधन की कमान भाजपा के पास ही रहेगी। इस बार जेडीयू को अपनी दो जीती हुई सीटें काराकाट और गया की कुर्बानी देनी पड़ी है। हालांकि बदले में एक शिवहर की सीट जरूर जदयू के खाते में चली गई है।

भाजपा ने बिहार के सीट बंटवारे में यह भी साफ कर दिया है कि भले ही रामविलास पासवान की पार्टी और सभी सांसद रामविलास के भाई पशुपतिनाथ पारस के साथ हों, जमीनी हकीकत चिराग के साथ है और एनडीए के लिए अखिल बिहार स्तर पर दलित चेहरा भी वही होंगे। इसी कारण पशुपतिनाथ पारस के मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री होने और चार सांसद होने के बाद भी पशुपतिनाथ पारस को बिना सीट दिए चिराग पासवान को पांच सीटे देकर असली उत्तराधिकारी मान लिया। हालांकि चिराग से भाजपा ने नवादा सीट जरूर हासिल कर ली है। मोदी के 400 पार की राह में सबसे बड़ा अवरोध बिहार ही था। नीतीश को तेजस्वी से तोड़कर वापस एनडीए में लाना और सीटों के बंटवारे में छोटे दलों को एडजस्ट करने में सफल होकर भाजपा ने बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। पिछले तीन चुनाव से लगातार जीत के नए रिकॉर्ड बनाने वाली एनडीए को मजबूत करने के लिए भाजपा को 2024 में नीतीश कुमार और बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छोटे दलों को साधना जरूरी था।

भाजपा ने मोदी और शाह की रणनीति में इसे बखूबी साधा है। भाजपा की कोशिश हर हाल में बिहार में 2019 के प्रदर्शन को दोहराना है जिसमें 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी और सिर्फ एक किशनगंज की सीट कांग्रेस ने जीती थी। आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। भाजपा जानती है कि बिहार में मोदी कितने भी लोकप्रिय हों और भाजपा का संगठन कितना भी मजबूत हो लेकिन नीतीश के सामाजिक समीकरण के आगे सब धराशायी हो जाता है। बिहार की राजनीति में भाजपा के लिए नीतीश मजबूरी हैं। बिहार में नीतीश के साथ दो दशकों से ज्यादा जुड़ा हुआ ईबीसी का वोट बैंक भाजपा को सभी सीटें जीतने के लिए जरूरी है। नीतीश के लिए भी लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ जरूरी है। 2014 के चुनाव में मोदी के नाम पर नीतीश एनडीए का साथ छोड़कर अकेले मैदान में उतरे थे और चारों खाने चित्त हो गए थे। 2014 में जदयू ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे लेकिन उसे मात्र दो सीटें मिली थीं। लेकिन भाजपा को जमकर फायदा हुआ। भाजपा को 22 और भाजपा के सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाह को 3, रामविलास पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थीं। जबकि 2014 में यूपीए के हिस्से में मात्र 7 सीटें आईं थी। इनमें राजद 4 सीट पर सिमट गई थी तो कांग्रेस दो और एक सीट पर एनसीपी विजयी हुई थी।

बिहार में सीटों के बंटवारे ने बताया कि मोदी की लोकप्रियता के बाद भी भाजपा सीटों के बंटवारे में सामाजिक ध्रुवीकरण की कसौटी पर नजर रखकर इसका गुणा-भाग करके सियासी फायदा उठाने में नहीं चूकती है। नीतीश ने भाजपा का दामन भले ही तीन बार छोड़ा लेकिन भाजपा ने नीतीश को फिर से साथ लेने में जरा भी देरी नहीं की। इस बार मोदी के नेतृत्व में भाजपा का पूरा फोकस ओबीसी, दलित और अति पिछड़े वोट बैंक पर है। राहुल गांधी के लगातार ओबीसी की बात करने और सत्ता में आने पर जातिगत सर्वे करवाने का वादा करने के बाद मोदी इस वर्ग को भाजपा से छिटकने नहीं देना चाहते और इस कारण इस वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हरियाणा में ओबीसी नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना हो या इसके पहले मप्र में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार और उप्र के यादव मतदाताओं को संदेश देना हो। दरअसल भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को भी अभी से ध्यान में रख रही है और उसी हिसाब से बिहार को लेकर फैसले ले रही है।

● **विनोद बक्सरी**

पशुपति पारस से इंडिया को कितना फायदा

बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटें फाइनल होने के बाद जो आशंका थी, वह सच साबित हुईं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पारस की पार्टी के 5 सांसद 2021 से केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का हिस्सा थी। जबकि, उनके भतीजे चिराग पासवान एलजेपी (रामविलास) के अकेले सांसद थे। एनडीए ने बिहार में चिराग की पार्टी के लिए 5 सीटें छोड़ी हैं और पारस को एक भी सीट नहीं दी है, इसलिए उन्होंने पार्टी के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार से निकलने का फैसला किया है। यह स्पष्ट है की भाजपा ने चाचा की जगह भतीजे पर भरोसा दिखाया है तो इसके पीछे करीब 5.5 प्रतिशत पासवान वोट है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग के पिता रामविलास पासवान की वजह से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। उनके निधन के बाद उनके भाई पारस और बेटे चिराग के बीच पार्टी का बंटवारा जरूर हुआ, लेकिन माना जाता है कि सिर्फ 5 सांसद ही पारस के साथ रह गए, समर्थक आज भी चिराग के साथ जुड़े हुए हैं। लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ बहुत करीब से जुड़े रहे एक व्यक्ति का कहना है कि आज 99 प्रतिशत पासवान वोट चिराग के साथ हैं। इसके अलावा उनकी हर वर्ग के मतदाताओं में पैठ है, जिनमें ब्राह्मण से लेकर यादव जाति के लोग भी शामिल हैं। उनके अनुसार अगर इस हिसाब से देखें तो चिराग के पास 7-8 प्रतिशत वोट है।

आर्थिक तंगी या ब्लैकमेलिंग

पिछले साल नवंबर महीने में सत्ता में आने के बाद से, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपने भारत विरोधी रुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी घरेलू और वैश्विक स्तर पर आलोचना हो रही है। भारतीय सैनिकों को वापस भेजने से लेकर चीन की ओर झुकाव तक, मुइज्जू ने खुलकर एंटी-इंडिया कैम्पेन चलाया है। लेकिन, मुइज्जू के एक बयान को लेकर उस वक्त एक्सपर्ट्स हैरान हो गए, जब उन्होंने नई दिल्ली को अपने देश का सबसे करीबी सहयोगी बताते हुए भारत से माले को कर्ज चुकाने में राहत देने का आग्रह किया है। मोहम्मद मुइज्जू का ये बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत के साथ एक के बाद एक समझौतों को रद्द करने के बाद भारत को लेकर उनकी तारीफ एक्सपर्ट्स के गले नहीं उतर रही है। लिहाजा, सवाल ये उठ रहे हैं, कि मोहम्मद मुइज्जू का वास्तव में हृदय परिवर्तन हुआ है, या फिर मालदीव की आर्थिक तंगी ने उन्हें भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर किया है, या फिर भारत से कर्ज चुकाने में राहत मांगना मोहम्मद मुइज्जू की कोई नई चाल है?

भारत संग कारोबार शुरू करने पर गंभीर शहबाज सरकार

आर्थिक उथल-पुथल के बीच, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है, कि अगस्त 2019 में कारोबारी संबंध को निलंबत करने के बाद उनका देश भारत से कारोबार फिर से शुरू करने को लेकर गंभीरता से विचार करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत से कारोबार फिर से बहाल करने को लेकर नए बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं, कि क्या पाकिस्तान कारोबारियों के प्रेशर में आकर भारत से फिर से कारोबार शुरू करने की बात कर रहा है, या फिर जिन्ना के वंशजों की अक्ल ठिकाने पर आ गई है? पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पर विचार करेगा। वहीं, एक पाकिस्तानी अखबार ने डार के हवाले से कहा है, कि हम भारत के साथ व्यापार के मामलों को गंभीरता से देखेंगे। उनकी टिप्पणियों ने भारत के प्रति राजनयिक रुख में संभावित बदलाव का संकेत दिया है।

नवंबर 2023 में पदभार संभालने के बाद पहली बार एक स्थानीय मीडिया ऑउटलेट को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है, कि भारत मालदीव को सहायता प्रदान करने में सहायक रहा है और उसने सबसे बड़ी संख्या में मालदीव में परियोजनाओं को लागू किया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा और इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति का ये बयान उस वक्त आया है, जब भारत ने अपने सैनिकों के पहले बैच को मालदीव से बुला लिया है और 10 मई तक सभी सैनिकों को मालदीव से वापस आ जाना है। इंटरव्यू के दौरान, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से आर्थिक संकट के समय मालदीव की मदद भी मांगी है। दरअसल, भारत ने मालदीव के विकास कार्यों को लेकर अलग-अलग सरकारों को मदद दी है और उसी ऋण भुगतान को लेकर मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से मदद मांगी है। उन्होंने कहा, कि हमें जो स्थितियां विरासत में मिली हैं, वे ऐसी हैं कि भारत से बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज लिया जाता है। इसलिए, हम इन ऋणों के पुनर्भुगतान ढांचे में उदारताएं तलाशने के लिए चर्चा कर रहे हैं। मुइज्जू ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मालदीव पर भारत का बहुत बड़ा कर्ज है, और मालदीव फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय कर्ज को चुका सके।

मालदीव की मीडिया ने राष्ट्रपति मुइज्जू के हवाले से कहा है, कि इसकी वजह से वर्तमान में मालदीव की सर्वोत्तम आर्थिक क्षमताओं के अनुसार ऋण चुकाने के विकल्प तलाशने के लिए भारत सरकार के साथ चर्चा की जा रही है। इसके अलावा, मुइज्जू ने कहा है कि मालदीव की लगातार मदद के लिए उन्होंने भारत सरकार का आभार भी जताया है। मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि मैंने अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि मेरा इरादा किसी भी चल रही परियोजना को रोकने का नहीं है। इसके बजाय, मैंने उन्हें संबंधों को मजबूत करने और उनमें तेजी लाने की इच्छा व्यक्त की। पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 400.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया था। भारत समर्थक नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के प्रशासन के नेतृत्व वाली मालदीव की पिछली सरकार ने भारतीय निर्यात और आयात बैंक (एक्जिम बैंक) से 1.3 मिलियन डॉलर का ऋण लिया था। इसे मिलाकर पिछले साल के अंत तक मालदीव की भारत पर बकाया राशि 6.2 अरब मालदीवियन एमवीआर हो गई है।

भारत की तारीफ करना और ऋण को लेकर मदद मांगना, क्या ये मोहम्मद मुइज्जू की एक और चाल है? ये सवाल इसलिए है, अगर भारत ऋण चुकाने में मोहलत देने से इनकार करता है, तो मोहम्मद मुइज्जू अपनी जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे, कि भारत को लेकर उनकी सरकार की जो नीति है, वो सही है। और अगर भारत मोहलत देता है, तो मोहम्मद मुइज्जू की सरकार को राहत मिलेगी और वो खुलकर अपने चीनी एजेंडे को आगे लेकर जाएंगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कहा है, कि वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को जिद्दी होना बंद करना चाहिए और पड़ोसियों के साथ बातचीत में शामिल होना चाहिए। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का ये बयान उस वक्त आया है, जब कुछ दिन पहले मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से कर्ज चुकाने में मोहलत देने की मांग की थी। मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक नेता माना जाता है, जिन्होंने काफी हद तक भारत और मालदीव के बीच के रिश्ते को खराब कर दिए हैं। जबकि, मोहम्मद मुइज्जू से ठीक पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति थे, जो भारत समर्थक नेता था और उनके नेतृत्व में दोनो देशों के संबंध में काफी तेजी से विकास हुए। पिछले साल सितंबर में 45 साल के मुइज्जू ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में 62 साल के मोहम्मद सोलिह को कुछ हजार वोट से हरा दिया था। वहीं, मालदीव में अब संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं और चार माफन्नु निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे एमडीपी संसदीय उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते वक्त सोलिह ने कहा कि उन्होंने वे मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जिनमें मुइज्जू ने कहा है कि वो भारत के साथ ऋण पुनर्गठन पर चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि, सोलिह ने ये नहीं कहा कि मालदीव के वित्तीय संकट के पीछे भारत का हाथ है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

वोट के लिए नेतन्याहू से रिश्ते तोड़ रहे बाइडेन!

इजराइल के फैसले से हैरान बाइडेन प्रशासन!

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है, कि बाइडेन प्रशासन इजराइली प्रधानमंत्री के व्हाइट हाउस की यात्रा कैंसिल होने के फैसले से हैरान है और इसे एक अतिप्रतिक्रिया मान रहा है। अमेरिका ने जोर देकर कहा है, कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वाशिंगटन ने गाजा पट्टी में लगभग छह महीने पुराने युद्ध के दौरान ज्यादातर समय युद्धविराम शब्द से परहेज किया है और हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर इजरायल को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। लेकिन, अब स्थिति काफी विकराल हो चुकी है। गाजा में अकाल शुरू हो गया है और भूख से भारी संख्या में लोगों की मौत होने लगी है। जिससे अमेरिका पर भी वैश्विक दबाव बन रहा है। फिलीस्तीन के गाजा नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 7 अक्टबूर को शुरू हुए हमले के बाद अभी तक 32 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता इसलिए भी नाराज हैं, क्योंकि रमजान से पहले गाजा पट्टी में युद्धविराम करवाने में बाइडेन नाराज रहे हैं, जबकि विश्लेषकों का कहना है, कि अब बाइडेन और नेतन्याहू के लिए चुनौती अपने मतभेदों को नियंत्रण से बाहर बढ़ने से रोकना है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच के संबंध गत दिनों गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के बीच सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को लेकर इजराइल में भारी नाराजगी है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने गाजा युद्धविराम पर प्रस्ताव पारित होने दिया है, जिसको लेकर इजराइल की तरफ से अमेरिका को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाई प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी व्हाइट हाउस का दौरा रद्द कर दिया है। जिसके बाद आशंका जताई जा रही है, कि गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में स्थित शहर राफा में जोरदार इजराइली सैन्य अभियान शुरू हो सकता है और भारी खूनखराबा हो सकता है। इजराइल की नाराजगी इस बात को लेकर है, कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा पट्टी में युद्धविराम को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया, तो अमेरिका ने इस प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोकने के बजाय, मतदान से गैर-हाजिर होने का विकल्प चुना।

अमेरिका इससे पहले इजराइल के खिलाफ पेश होने वाले हर प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोक दिया करता था, लेकिन इस बार अमेरिका मतदान से गैर हाजिर हो गया, लिहाजा इजराइल के खिलाफ ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव यूएनएससी में पास हो गया, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका है। यूएनएससी में जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उसमें हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई के साथ-साथ गाजा पट्टी में पूर्ण युद्धविराम की मांग की गई थी। जबकि, इजराइल ने कहा है, कि उसकी लड़ाई उस वक्त तक चलती रहेगी, जब तक हमास का नामोनिशान नहीं मिट जाता है, लेकिन इजराइल की कार्रवाई में करीब 32 हजार लोग मारे गए हैं, जिसका मुस्लिम देशों के साथ-साथ अमेरिकी मुस्लिमों में भी भारी विरोध हो रहा है। स्थिति ये है, कि अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले मुस्लिमों ने बाइडेन का बहिष्कार करने का कैम्पेन चलाना शुरू कर दिया है।

बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा था, क्योंकि उस बैठक के दौरान इजराइल और अमेरिका के बीच गाजा पट्टी में युद्धविराम के साथ-साथ मानवीय सहायता पहुंचाने को लेकर बातचीत होने वाली थी। खासकर इस वक्त, जब गाजा में भुखमरी शुरू हो गई है, उस वक्त मानवीय सहायता के पहुंचाने के रास्ते में आई ये नई बाधा गाजावासियों की स्थिति को और भी खराब कर देगा। ऐसी रिपोर्ट्स थी, कि इस बैठक के दौरान इजराइल अमेरिका पर राफा में जमीनी लड़ाई शुरू करने को लेकर समर्थन भी मांगने वाला था। लेकिन, अब इजराइल ने कहा है, कि वो बगैर अमेरिकी मदद के भी अपने अभियान को जारी रखेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के राफा में आक्रामक हमले की धमकी ने इजराइल और अमेरिका के संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है और बाइडेन नहीं चाहते हैं कि नवंबर चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोटरों की नाराजगी झेलनी पड़े और डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले से भी काफी आक्रामक प्रचार के जरिए आगे चल रहे हैं, उन्हें और मदद हो। इसके अलावा, डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने भी बाइडेन पर युद्धविराम के लिए दबाव बनाना काफी तेज कर दिया है, लेकिन बाइडेन के सामने दूसरी दिक्कत ये है कि अगर वो इजराइल के खिलाफ खुलकर जाते हैं, तो फिर चुनाव कैम्पेन के लिए उनकी फंडिंग कैसे होगी, क्योंकि अमेरिका में यहूदियों का प्रभाव कितना है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन, अमेरिका में सगबुगाहट इस बात को लेकर है कि बाइडेन प्रशासन इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता को या तो रोक सकते हैं, या फिर सीमित कर सकते हैं।

रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक प्रशासन के पूर्व मिडिल ईस्ट वार्ताकार आरोन डेविड मिलर ने कहा कि इससे पता चलता है कि बाइडेन प्रशासन और नेतन्याहू के बीच विश्वास टूट रहा है। उन्होंने कहा कि यदि संकट का सावधानी से प्रबंधन नहीं किया गया, तो यह और भी बदतर होता जाएगा। जबकि, यूएनएससी वोटिंग से अमेरिका का गैर-हाजिर रहना, दुनिया को एक ऐसा संदेश देता है, कि इजराइल को लेकर अमेरिका में अब निराशा भर रही है। लेकिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी दिक्कतें हैं। उनकी सरकार को समर्थन देने वाली दूसरी धुर दक्षिणपंथी पार्टियां हमले को और तेज करने की मांग कर रही हैं। इसके अलावा, नेतन्याहू को उन परिवारों को भी समझाना होगा, जिनके सदस्य अभी भी हमास के कब्जे में हैं। वाशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक में मध्य पूर्व कार्यक्रम के निदेशक जॉन अल्टरमैन ने कहा, कि ऐसा कोई कारण नहीं है, कि यह संबंधों के लिए घातक झटका हो। इसलिए मुझे नहीं लगता, कि किसी भी चीज के लिए दरवाजा बंद है। हालांकि, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की यात्रा रद्द होने से अलग इजराइल के रक्षामंत्री योव गैलेंट ने अलग से वॉशिंगटन की यात्रा की है, जिससे एक संकेत ये जाता है, कि दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन अभी भी बना हुआ है। लेकिन, अमेरिका के वोटिंग से दूर रहने से बाइडेन और नेतन्याहू के बीच दरार और गहरी हो गई है, जो एक-दूसरे को वर्षों से जानते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच के सबसे अच्छे समय में भी इन दोनों नेताओं के आपसी संबंध उतने अच्छे नहीं रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, बाइडेन ने एक एमएसएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया, कि राफा में हमला इजराइल के लिए एक रेड लाइन क्रॉस करने जैसी होगी।

● **कुमार विनोद**

राजनीति में नारी की कागजी भागीदारी

यूं तो देश की महिलाएं राजनीति के उच्च शिखर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन्हें राजनीति में वह सम्मान आज तक नहीं मिल सका है, जिसकी वह हकदार हैं। और तो और देश की राजधानी में जहां देश की संसद है और जहां से देश की सरकार चलती है, उस दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति अच्छी नहीं है। आप को जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में दिल्ली-एनसीआर की 13 लोकसभा सीटों में से केवल दिल्ली की एक सीट पर ही महिला सांसद हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी को अलग कर दिया जाए तो अन्य एक भी सीट पर महिला सांसद नहीं हैं। राजनीति में महिलाओं की दशा बताने के लिए दिल्ली-एनसीआर का उदाहरण ही काफी है।

बेशक महिलाओं को लेकर 1998 से लंबित कानून को संसद से पास करा दिया गया है, जिसमें महिलाओं की 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी की बात की गई है, लेकिन राजनीति में महिलाओं की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। एनसीआर में 13 लोकसभा सीटें आती हैं। दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा शुरू हो गई है, इसमें से गठबंधन में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने सात में से अपने हिस्से की चार सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, मगर एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है। जबकि भाजपा ने घोषित किए गए पांच सीटों के प्रत्याशियों में से दो महिलाओं को टिकट दिया है। कांग्रेस गठबंधन में बची हुई तीन सीटों में से किसी सीट पर महिला प्रत्याशी उतारेगी, अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एनसीआर क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी किसी दल द्वारा महिलाओं को उतारे जाने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति में कागजों में ज्यादा, जमीन पर कम हिस्सेदारी है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी।

अपेक्षा की जाती है कि भारत वर्ष 2030 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की 1.6 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत की दर से विकास करेगी, लेकिन भारत के इस आशाजनक आर्थिक विकास के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अनुरूप गति नहीं पा सकी है। इस परिदृश्य में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की राह में मौजूद बाधाओं को दूर करना समय की मांग है। लैंगिक समता प्राप्त करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिले, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता को मिलकर कार्य करना होगा।

अंतर-संसदीय संघ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, भारत में 17वीं लोकसभा में कुल सदस्यता में महिलाएं मात्र 14.44 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत निर्वाचन आयोग की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं संसद के सभी सदस्यों के मात्र 10.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्य विधानसभाओं के मामले में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व औसतन 9 प्रतिशत है। इस संबंध में भारत की रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। हैरानी की बात तो यह है कि यह वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो महिलाओं को राजनीतिक दलों में प्राय: कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे उनके लिए अपने दलों में विभिन्न पदों से गुजरते हुए आगे बढ़ना और चुनाव के लिए दल का नामांकन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। प्रतिनिधित्व की इस कमी को राजनीतिक दलों के भीतर मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रह और इस धारणा का परिणाम माना जा सकता कि महिलाएं पुरुषों की तरह चुनाव जीतने योग्य नहीं होतीं। एक समस्या यह भी है कि भारत एक गहन पितृसत्तात्मक समाज है और महिलाओं को प्राय: पुरुषों से हीन माना जाता है। यह मानसिकता समाज में गहराई तक समाई हुई है और महिलाओं की राजनीति में नेतृत्व एवं भागीदारी की क्षमता के संबंध में लोगों की सोच को प्रभावित करती है। यह एक अच्छी शुरुआत है कि अब इस दिशा में गंभीरता से सोचा जाने लगा है।

आज दिल्ली नगर निगम में आरक्षण के कारण 50 प्रतिशत महिला पार्षद हैं। यह बात और है कि कई महिलाओं की सीटों को उनके परिवार के लोग देखते हैं, मगर उन्हें सम्मान मिला है। आज दिल्ली में महापौर के पद पर महिला हैं। गाजियाबाद में भी महापौर पद पर महिला हैं। आरक्षण नहीं होने पर दिल्ली विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत तो क्या 20 प्रतिशत भी नहीं है। दिल्ली विधानसभा में 12 प्रतिशत महिलाओं ही हिस्सेदारी है। ऐसे में यहां भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी नजर आएगी। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर हम समग्र बात करें तो भारत के इतिहास में आधुनिक काल ही अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाएं भारत की जनसंख्या का करीब आधी आबादी हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षाकृत देश की आर्थिक संपन्नता का कम लाभ मिला है।

● **ज्योत्सना**

महिलाओं को प्रेरित करती इनकी कहानियां

ये कहानियां दूसरों को आगे बढ़ने के लिए उम्मीद और प्रोत्साहन देती हैं। इनमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, मैडम बीकाजी कामा, कस्तूरबा, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित ने महत्वपूर्ण योगदान किया। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में इंदिरा गांधी, नंदिनी सत्पथी, मोहसिना किदवई, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित और स्मृति ईरानी आदि ने सक्रियता दिखाई है। इंदिरा गांधी ने तो 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया है और तो और इस समय भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो आदिवासी इलाके से आती हैं।

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

पार्सल

रिया ने नेहा से कहा- रिसेप्शन पर तुम्हारा पार्सल आया है जाकर ले लो।

नेहा सोचते हुए जा रही थी पता नहीं किसने भेजा है। वो पार्सल कमरे में लेकर आई और जल्दी-जल्दी खोलने लगी। उसमें दो-तीन डब्बे थे, एक डब्बे में गोंद के लड्डू और दूसरे डब्बे में कुछ नमकीन थे, साथ ही कुछ रंग-बिरंगी दुप्पटे थे। पार्सल के सामान को देखकर नेहा की आंखें नम हो गई।

नेहा की मां को गुजरे कई साल हो गए, तीन साल से वो होस्टल में रह रही हैं आज तक उसके लिए कभी कुछ नहीं आया। उसके सारे दोस्तों के घर से हमेशा कुछ-न-कुछ आता था। ये देखकर वो हमेशा उदास हो जाती थी।

बेटा पार्सल मिला क्या

जी पापा मिल गया, कहते-कहते नेहा थोड़ा भावुक हो गई

पसंद आया?

जी!

आपने ये सब कैसे बनाया, नेहा ने पूछा

अरे मैंने नहीं बनाया, पड़ोस की सरला आंटी से बनवाया।

तुम्हारी मां की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता लेकिन थोड़ा-सा दूर कर सकता हूं। कहते हुए नेहा के पापा भी भावुक हो गए।

- विभा कुमारी 'नीरजा'

रेस का घोड़ा

हेलो सर!

हलो।

क्या मेरी बात डॉ. शर्मा जी से हो रही है।

हां जी, बोल रहा हूं। पर आप

कांग्राचुलेशन्स सर। मैं साहित्यिक वेबसाइट 'ढिंचाक' से मिस सुधा बोल रही हूं। सर, आप इस हफ्ते 'आथर ऑफ द वीक' के लिए नॉमिनेट किए गए हैं।

अच्छा, ये क्या होता है?

सर, हमारी साहित्यिक वेबसाइट की ओर से हर सप्ताह एक राइटर को 'आथर ऑफ द वीक' के रूप में चुना जाता है। जिस राइटर को सबसे अधिक लाइक्स और वोट मिलते हैं, उसे आकर्षक 'ई-सर्टिफिकेट' देकर सम्मानित किया जाता है। सम्मानित राइटर को हमारे पैनल के प्रकाशकों की पुस्तकों की खरीदी करने या उनसे अपनी पुस्तकें प्रकाशित कराने पर 25 प्रतिशत का भारी डिस्काउंट मिलता है। मैंने ईमेल के माध्यम से आपको वोटिंग लाइन की लिंक भेज दी है। सो प्लीज, आप अपने परिचितों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और उन्हें भी करने को कहें, ताकि आप 'आथर ऑफ द वीक' चुने जा सकें।

देखिए मैडम जी, मैं एक राइटर हूं, रेस का घोड़ा नहीं।

उन्होंने कहा और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना फोन काट दिया।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

किसकी बारी है

चुनावों का बिगुल, बज चुका है
जंग का मैदान, अब सज चुका है
जनता को रिझाने, का दौर जारी है
देखते हैं इस बार किसकी बारी है।।
बड़ी-बड़ी घोषणाएं, तो कर चुके
मुफ्त बांटने की, रस्म पूरी कर चुके
सब हैं जनता के, रहमो-करम पर
उसके मन में, क्या है बस यही,
दुश्वारी है।
देखते हैं, इस बार किसकी बारी है।।
यूं तो किसी ने, कोई कसर न छोड़ी
किए प्रण पूरे, और हेकड़ी तोड़ी
हवा के रूख का, है क्या ठिकाना
कब पलट, जाए बाजी जनता, सब
पर, भारी है।
देखते हैं इस बार किसकी बारी है।।
सारे तीर तर्कश के, आजमां लिए
कहीं सख्ती की? कहीं बहला लिए
अंत में गद्दी, किसके हाथ लगेगी
सबके, अपने-अपने दावे अपनी
रायशुमारी है।
देखते हैं, इस बार किसकी बारी है।।
कुछ आपस में, लड़ने में व्यस्त हैं
तो कुछ, मान-मनौव्वल, से त्रस्त हैं
एक-दूजे की पोल, खोल रहे सब
दूध का धुला, न कोई सब वोट के,
पुजारी हैं।
देखते हैं, इस बार किसकी बारी है।।
भ्रष्टाचार अब भी, मुंह बाए खड़ा है
कोई कुछ भी कहे, यह मुद्दा बड़ा है
ऐसा नहीं कि, जानते-समझते नहीं
पर मानते नहीं यह कैसी,
समझदारी है।
देखते हैं, इस बार किसकी बारी है।।
लोकतंत्र का है, यह महापर्व
वोट के अधिकार, का है उत्सव
इसको छुट्टी की, तरह न जाने
मताधिकार को, महत्वपूर्ण मानें
कुछ अपनी भी, जिम्मेदारी है।
देखते हैं, इस बार किसकी बारी है।।
कुछ अपनी भी, जिम्मेदारी है
देखते हैं, इस बार किसकी बारी है।।

- नवल अग्रवाल

अनकैप्ड खिलाड़ियों पर रहेगी नजर...

भारत में हर साल गर्मियों के दिनों में खेली जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल काफी लोकप्रिय हो चुकी है। नए खिलाड़ियों के लिए यह एक ऐसा मंच है, जिस पर बेहतर प्रदर्शन करके देश के लिए खेलने का अवसर मिल जाता है। बीसीसीआई के चयनकर्ताओं की नजर आईपीएल पर खास तौर से रहती है। आज कई युवा खिलाड़ी किसी न किसी प्रारूप में भारतीय टीम का हिस्सा बन चुके हैं। युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा चमकाने का इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता। यही इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण भी है जो 22 मार्च से शुरू हो गया है और 26 मई तक चलेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह आईपीएल 2024 की नीलामी प्रक्रिया में अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए फ्रेंचाइजियों ने करोड़ों रुपए खर्च किए, वैसे ही ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से दर्शकों और बीसीसीआई का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इनमें समीर रिजवी का नाम सबसे पहले है।

समीर रिजवी: गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर रिजवी को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पिछले साल खेले गए यूपी टी-20 लीग के पहले सीजन में समीर रिजवी के बल्ले से शानदार प्रदर्शन करना था, जिसमें उन्होंने कानपुर सुपरस्टार्स की तरफ से खेलते हुए 9 पारियों में 2 शतकों के साथ कुल 455 रन बनाए थे। वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 में भी उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने 69.25 के औसत से रन बनाए। समीर ने अब तक 11 टी-20 मैचों में 49.16 के औसत से 295 रन बनाए हैं। अब चेन्नई को भी उनसे वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वो ऑक्शन में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट न खेलने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। समीर डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार तेजी से रन बनाने के कारण लोकप्रिय हुए हैं और अंडर-19 लेवल पर भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

अर्शिन कुलकर्णी: साउथ अफ्रीका में इस साल की शुरुआत में खेले गए आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहने वाले महज 19 साल के अर्शिन कुलकर्णी को 20 लाख रुपए में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने खरीदा। बल्ले के साथ गेंद से भी कमाल दिखाने वाले अर्शिन टीम के लिए मैच विनर खिलाड़ी की भूमिका निभा सकते हैं। दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज कुलकर्णी का घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड देखा जाए तो 6 टी-20 मैचों में 121 रन बनाने के साथ 4 विकेट भी हासिल किए हैं। वहीं इसके अलावा अंडर-19 वर्ल्डकप में उनके बल्ले से 7 मैचों में एक शतकीय पारी सहित कुल 189 रन निकले थे, जबकि गेंद से 4 विकेट हासिल किए थे।

रॉबिन मिंज: गुजरात टाइटंस ने झारखंड के 21 साल के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज को 3.60 करोड़ रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। मिंज स्वाभाविक तौर पर एक आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं। हालांकि अभी तक उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में झारखंड की सीनियर टीम से एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला है। इसके बावजूद उनकी आक्रामक खेलने की शैली गुजरात की टीम के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

कुशाग्र कुमार: झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज कुशाग्र कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने 7 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। कुशाग्र के अभी तक के करियर को देखा जाए तो उनके आंकड़े उतने बेहतरीन नहीं दिखाई देंगे लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सीजन में कुशाग्र ने महाराष्ट्र के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में 67 रनों की पारी ऐसे समय में खेली थी जब उनकी टीम 355 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी। कुशाग्र की इस एक पारी ने सभी को काफी प्रभावित किया था। कुशाग्र के घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन को देखा जाए तो उन्होंने 11 टी-20 मैचों में अब तक 140 रन बनाए हैं, तो वहीं लिस्ट ए के 23 मुकाबलों में 46.66 के औसत से 700 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतकीय पारियां भी शामिल हैं।

शुभम दुबे: राजस्थान रॉयल्स ने घरेलू क्रिकेट में विदर्भ की टीम से खेलने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम दुबे को 5 करोड़ 80 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। शुभम ने लगातार अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया है। निचले क्रम में खेलने वाले शुभम दुबे का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें उन्होने 7 मैचों में 73.66 के औसत से 221 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 187.28 का रहा। शुभम ने अब तक अपने करियर में खेले 20 टी-20 मैचों में 37.30 के औसत से 485 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 145.20 का रहा है।

अवनीश राव अरावेली: अवनीश को चेन्नई ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। अवनीश अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। मगर इससे पहले जूनियर लेवल क्रिकेट में खेली गई 183 रनों की पारी के कारण उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। अवनीश एक विकेटकीपर हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में उन्हें महेंद्र सिंह धोनी से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है।

नुवान तुषारा: श्रीलंका के 29 साल के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा लीजेंड लसिथ मलिंगा जैसे एक्शन से गेंदबाजी करते हैं। उन्हें आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। तुषारा ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक भी ली थी। वह आईपीएल 2024 में अपनी गेंदबाजी से सबको सरप्राइज कर सकते हैं।

नेहाल वढेरा: पंजाब के 23 साल के नेहाल वढेरा ने 2023 में आईपीएल में डेब्यू कर बल्ले से कमाल किया था। नेहाल ने 145 के स्ट्राइक रेट से 241 रन बनाए थे जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल थे। नेहाल इस सीजन और बेहतर प्लेयर बनकर सामने आ सकते हैं और टीम को कई मैच जितवा सकते हैं।

गेराल्ड कोएट्जी: साउथ अफ्रीका के युवा और तेज तर्रार गेंदबाज गेराल्ड कोएट्जी ने पिछले साल भारत में खेले गए वर्ल्ड कप में कोहराम मचाया था। तब उन्होंने 20 विकेट झटके थे। उसके बाद से ही उन्हें आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ में खरीदा। कोएट्जी अपनी खूंखार गेंदबाजी से आईपीएल सीजन में तहलका मचा सकते हैं।

अजमतुल्ला ओमरजाई: हार्दिक पंड्या अब गुजरात टाइटंस में नहीं है, लेकिन टीम के पास उनकी अफगानिस्तान के अजमतुल्ला ओमरजाई है। 23 वर्षीय ओमरजाई की तुलना हार्दिक से की जाने लगी है। वह बल्लेबाजी लाइनअप में मजबूती दे सकते हैं। वहीं पावरप्ले में बॉल को स्विंग करा सकते हैं। हाल ही में अजमतुल्ला ने श्रीलंका के खिलाफ 149 रनों की पारी खेली थी।

● **आशीष नेमा**

बसंती के किरदार से कभी बाहर नहीं आ पाईं हेमा मालिनी, बोलीं- मैंने 200 फिल्में की हैं लेकिन...

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को उनके फैंस बसंती कहकर भी बुलाते हैं। 1975 की क्लासिक फिल्म शोले में हेमा ने बसंती का किरदार निभाया था। अभिनेत्री को कई बार कहते हुए देखा गया है कि वह इस किरदार से कभी बाहर नहीं आ सकेंगी। बॉलीवुड के साथ हेमा मालिनी में राजनीति में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है।

हेमा मालिनी ने हाल ही में एक बातचीत में कहा, मैं बसंती की छाया से कभी बाहर नहीं आऊंगी। मैं उसी के साथ पैदा हुई थी। मैंने 200 फिल्में की हैं और लोग अब भी मुझे शोले की बसंती या सीता और गीता और बागबान के रूप में याद करते हैं। उन्होंने कहा, मैं सभी को बताती हूं कि मैं एक में तीन हूं, एक फिल्म कलाकार, एक डांसर और एक राजनीतिज्ञ।

अपनी रिलीज के इतने वर्षों बाद भी रमेश सिप्पी की शोले अपने कलाकारों और किरदारों के साथ एक बड़ा आकर्षण बनी हुई है। हेमा के साथ फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अमजद खान, संजीव कुमार जैसे किरदार भी नजर आए थे। फिल्म के सभी कलाकार हिट हैं। मगर जय-वीरू की जोड़ी और बसंती का किरदार दर्शकों को बेहद पसंद है। बसंती का किरदार हेमा मालिनी के भी पसंदीदा किरदारों में से एक है।

जब 5 साल सांसद रहने के बाद भी पछताए गोविंदा, राजनीति में आने के फैसले को बताया था गलत

बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा आज बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन एक दौर था जब इंडस्ट्री में इन्हीं का सिक्का चलता था। आज गोविंदा को भले काम नहीं मिल रहा, लेकिन 90 के दशक में वह हर एक बड़े फिल्ममेकर की पहली पसंद थे। गोविंदा फिल्मों में अपने कमबैक के लिए स्ट्रगल के बीच अब राजनीति में अपनी दूसरी पारी को लेकर चर्चा में हैं। जी हां, गोविंदा ने एक बार फिर राजनीति का दामन थाम लिया है। इससे पहले 2004 में गोविंदा ने फिल्मी दुनिया छोड़कर बॉलीवुड में अपने पैर जमाए थे। गोविंदा तब 43 साल के थे जब उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था और अब एक बार फिर राजनीति का हिस्सा बन गए हैं।

गोविंदा ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ज्वॉइन की है। हालांकि, वह इससे पहले ही कांग्रेस की टिकट से सांसद रह चुके हैं। लेकिन, गोविंदा से जब राजनीति को लेकर उनका अनुभव पूछा गया था तो उन्होंने इसे अपना सबसे खराब एक्सपीरियंस बताया था। एक्टर से जब राजनीति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि वह अपनी इस पारी को भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि वह इसे अपना बेहतरीन अनुभव नहीं मानते। अब सालों बाद एक बार फिर गोविंदा की राजनीति में एंट्री हुई है।

फिल्मों में आने से पहले टिन के कारखाने में काम करते थे शोले के सूरमा भोपाली, साबुन-पतंग भी बेचे

शोले में सूरमा भोपाली का किरदार अमर करने वाले जगदीप आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 7 दशक के एक्टिंग में उन्होंने करीब 400 फिल्मों से लोगों को हंसाने का काम किया, लेकिन असल जिंदगी में संघर्ष से अछूते नहीं रहे।

भारत-पाक बंटवारे में हुए दंगों में उनके पिता मारे गए। फिर मां ने अनाथाश्रम में काम करके उन्हें पाला। मां की मदद करने के लिए 7-8 साल की उम्र से ही उन्होंने सड़कों पर गुब्बारे बेचे, टिन, पतंग और साबुन की फैक्ट्री में काम किया। इसी दौरान उनका रिश्ता फिल्मों से जुड़ा। फिर चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरुआत कर उन्होंने फिल्मों में लीड किरदार निभाने तक का सफर तय किया। फिल्मों के जैसे ही जगदीप की पर्सनल लाइफ भी फिल्मी रही। बेटे को देखने आई लड़की की बड़ी बहन को ही दिल दे बैठे और शादी भी की। जगदीप का जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च 1939 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश बहुत ठाट-बाट से हुई, लेकिन ये खुशियां बस चंद दिनों की ही थीं।

बस कैसे न कैसे करके उंगली करना है

बहते पानी के दरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में पत्थर आने पर वो तो उस पत्थर के ऊपर या साईड से कहीं से भी रास्ता बना के आगे बढ़ता ही जाएगा। वो तो आगे बढ़ जाएगा पर उंगली कर्ता का क्या, वो तो वहीं अपना सा मुंह लिए खड़ा ही रह जाएगा। धरा का धरा अपना सा मुंह लिए ये सोचेगा खुद के मन में ही, कि अरे मैं फलाने को इतना कुछ सुना रहा हूं पर फलाने के कान पर तो जूं भी नही रेंग रही।

अब बात यों हुई कि हम तो सीधे चुपचाप बैठ, अपने हर एप पर घूम रहे थे, एप कहें तो हर वेबसाइट जिस पर हमारी जिंदगी में आनंद, सुकून के कुछ पल मिलते हैं बिताने के लिए, तो हम कहां थे, अरे हां! मार्निंग वॉक कर रहे जरा सुबह-सुबह सोशल मीडिया पर यही समझ लो।

अब हुआ यूं कि हम चलते-चलते सभी की पोस्ट देख रहे थे तभी हर बार की तरह इस बार भी घुमा फिरा के फिर एक पोस्ट पर नजर पड़ गई। देखा, पढ़ा, सुना उस पोस्ट के हर एक विवरण को ध्यान से फिर सोचा चलो भाई इसी पोस्ट पर दूसरों की तरह जरा अपने भी विचार हम लिख दें। जैसा कि पहले के लेख में मैंने बताया था कि फर्श से अर्श तक जाने वालों से सीखो, जलने कुढ़ने से अपना ही खून जला खुद का ही नुकसान न करें। ठीक उसी तरह से मिलते-जुलते भावों से भरा लेख है ये मेरा बस थोड़ा बहुत अंतर है। अब क्या करें मेरा मन ही ऐसा है कि कोई किसी को जबरदस्ती उंगली करे तो थोड़ी फोकट की राय मैं भी दे देती। अरे फोकट की राय सुनकर यदि इक्का-दुक्का समझ जाएं तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है, बस समझाना हमारी कलम का कर्तव्य, समझना न समझना उंगली कर्ताओं का कर्तव्य। अरे भाई, क्यों किसी को ऐसे नहीं तोड़ सके तो वैसे तोड़ने की कोशिश कर रहे? बहते पानी के दरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में पत्थर आने पर वो तो उस पत्थर के ऊपर या साइड से कहीं से भी रास्ता बना के आगे बढ़ता ही जाएगा। वो तो आगे बढ़ जाएगा पर उंगली कर्ता का क्या, वो तो वहीं अपना सा मुंह लिए खड़ा ही रह जाएगा, धरा का धरा अपना सा मुंह लिए ये सोचेगा खुद के मन में ही, कि अरे मैं फलाने को इतना कुछ सुना रहा हूं, पर फलाने के कान पर तो जूं भी नही रेंग रही। तो चलिए बताती हूं की असल में मेरी नजर किस गलियारे में और किस तरह के पोस्ट पर गई थी। दरअसल मेरी नजर गई एक काफिले के ऊपर बनाए गए वीडियो पर और उस वीडियो पर कसे गए कटू शब्दों से भरे व्यंग्य पर। सोचा चलो फिर इन कटू शब्दों में सौम्यता भर इसे ही स्याही बना अपनी कलम में भर कागजों में उतार दूं, ध्यान देने योग्य बात पुन: कह रही हूं, कटू शब्दों में सौम्यता का रसपान भर स्याही बनाना।

चलो तो उस वीडियो के अंतर्गत एक काफिला दिखाया गया, हो सकता है वो काफिला बहुत ही अमीर आदमी का हो जैसे अंबानी जी, टाटा जी, बिड़ला जी या हो सकता है किसी भी उच्च अधिकारी का हो या हमारे देश मतलब हमारे परिवार के वरिष्ठ उच्चाधिकारी का हो खैर क्या फर्क पड़ता है कि काफिला किसका था। अब उस काफिले के अंतर्गत ये दिखाया गया कि एक अधिकारी की कार के आगे-पीछे अनेक कारें थी। अब ये बताइए कि इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है भला? ये तो बहुत जरूरी है देश के किसी भी अमीर आदमी या उच्चाधिकारी की सुरक्षा।

अरे! आज-कल के वातावरण को देखो तो कितना घोर कलयुग है, आंखें खुली हैं सब जानते भी हैं फिर भी? यहां तो आए दिन लोग खबरों में सुनते, अखबारों में पढ़ते कि फलाने शहर, गली-मोहल्ले में खुलेआम किसी न किसी पर कहीं न कहीं हमला हुआ या मार दिया या अपहरण अन्य कितने अपराध हमारी आम जनता के साथ हो रहे। सोचने वाली बात यह है कि यहां तो आम जनता ही आम जनता का शिकार कर लेती है।

पता ही नहीं चलता बहुत से अपराधों में तो कि अपराधी कौन है। कौन, कब, कहां से घात लगाए बैठा, कुछ कह नहीं सकते। अब ये तो हुई आम जनता की बात, कहने का मतलब यह है कि आम जनता ही जब दहशत में जी रही अपने आस-पास की जनता के बीच रहकर जरा तो सोचा होता कि ये तो उच्चाधिकारी या देश के सर्वश्रेष्ठ अमीर, अभिनेता वगैरह-वगैरह किसी का भी काफिला हो सकता है। इनके तो आम जनता से अधिक घात लगाने वाले शिकारी छुप छुपाकर बैठे होंगे तो कैसे इनकी सुरक्षा में भला कोई चूक करे। साधारण शब्दों में वीडियो बनाने वाले के भाव यह थे कि इतनी सारी कारें आगे-पीछे लेकर घर से निकलने वाला या जो भी हो वो बहुत पैसा उड़ा रहा है। अब सोचो मेरे विचारों को पढ़ क्या अभी भी यही कहेंगे कि पैसों की बर्बादी हो रही या पेट्रोल की, जो चीज जरूरी है वो तो जरूरी ही है ना। अब बहुत ज्यादा जरूरत से भरी उपयोगी चीज को भी व्यर्थ बताना मेरी नजरों में तो कहीं से भी सही नही।

इंसान को कोई भी बात कहकर उंगली करने से अच्छा है कि उसके कारणों को शांतिपूर्ण समझे और जब समझ में आ जाए तो मेरी तरह उंगली को ही सौम्यता भरी स्याही में तब्दील कर उकेर दो अपने विचारों को कागजों पर। अरे भाई भला ये कागज जैसी बेहतरीन चीज हम सभी के लिए तो बनी है जिस पर मन के भीतर उठे ज्वार-भाटा, प्रेम, दुख-दर्द, खुशी सभी को लिख अपने भाव या सब बांट सकते हम इन कागजों के साथ। चलो अब मैं बहुत टहल ली अपनी कलम भावों संग भी कागजों के गलियारों में खोकर, अरे अपने भावों संग। अब जरा कुछ काम ही कर लूं घर का।

● **वीना आडवाणी तन्वी**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प

इस संकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है

कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की बृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company

प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है